खण्ड-08 सत्र-02 / अंक-12

बुधवार 02 अप्रैल, 2025 / 12 चैत्र, 1947 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

आठवीं विधान सभा

दूसरा सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-08, सत्र-2 में अंक 06 से 12 तक सम्मिलित हैं।)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

रंजीत सिंह

सचिव

RANJEET SINGH

Secretary

महेन्द्र गुप्ता

उप-सचिव (सम्पादन)

MAHENDRA GUPTA

Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र-2 बुधवार, 02 अप्रैल, 2025/12 चैत्र, 1947 (शक) अंक-12

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1-2
2.	सदन में अव्यवस्था	3-4
3.	विपक्ष के गैरजिम्मेदाराना व्यवहार पर खेदाभिव्यक्ति	5-8
4.	विशेष उल्लेख (नियम-280)	9
5.	बढ़े हुए पानी के बिलों पर चर्चा	10-26
6.	विशेष उल्लेख (नियम-280)	27-44
7.	सीएजी रिपोर्ट (वायु प्रदूषण) प्रस्तुतिकरण एवं चर्चा	45-109
8.	अल्पकालिक चर्चा (नियम-55)	110-129

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-2 बुधवार, 02 अप्रैल, 2025/12 चैत्र, 1947 (शक) अंक-12

दिल्ली विधान सभा

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए:

1. श्री अहिर दीपक चौधरी
2. श्री अजय महावर
3. श्री अनिल कुमार शर्मा
4. श्री अरविन्दर सिंह लवली
5. श्री अशोक गोयल
6. श्री गजेन्द्र दराल
7. श्री हरीश खुराना
8. श्री जितेन्द्र महाजन
9. श्री कैलाश गहलोत
10. श्री कैलाश गंगवाल
11. श्री करनैल सिंह
12. श्री करतारसिंह तंवर
13. श्री कुलदीप सोलंकी
14. श्री मनोज कुमार शौकीन
15. श्रीमजी नीलम पहलवान
16. श्री ओम प्रकाश शर्मा
17. श्री प्रद्यूम्न सिंह राजपूत
18. श्री पवन शर्मा
19. श्री राज करन खत्री
20. श्री राजकुमार भाटिया
21. श्री राज कुमार चौहान
22. श्री रवि कान्त

23. श्री रविन्दर सिंह नेगी
24. श्री संदीप सहरावत
25. श्री संजय गोयल
26. श्री सतीश अपाध्याय
27. सुश्री शिखा राय
28. श्री श्याम शर्मा
29. श्री सूर्य प्रकाश खत्री
30. श्री तरविन्दर सिंह मारवाह
31. श्री तिलक राम गुप्ता
32. श्री उमंग बजाज
33. श्री आले मोहम्मद इकबाल
34. श्री अमानतुल्लाह खान
35. श्री चन्दन कुमार चौधरी
36. चौधरी जुबैर अहमद
37. श्री अजय दत्त
38. श्री जरनैल सिंह
39. श्री कुलदीप कुमार
40. श्री कुलवन्त राणा
41. श्री मुकेश कुमार अहलावत
42. श्रीमती पूनम शर्मा
43. श्री प्रवेश रत्न
44. श्री प्रेम चौहान
45. श्री राम सिंह नेताजी
46. श्री सही राम
47. श्री संजीव झा
48. श्री सोम दत्त
49. श्री सुरेन्द्र कुमार
50. श्री विरेन्द्र सिंह कादियान
51. श्री विशेष रवि

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-2 बुधवार, 02 अप्रैल, 2025/12 चैत्र, 1947 (शक) अंक-12

सदन अपराह्न 02 बजकर 02 मिनट पर समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष (श्री विजेन्द्र गुप्ता) पीठासीन हुए।

माननीय अध्यक्षः अब निम्नलिखित सदस्यों द्वारा विशेष उल्लेख के मामले उठाये जायेंगे।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः एक मिनट, आप श्री राज करण खत्री जी। शुरू करें श्री राज करण खत्री।

...व्यवधान...

श्री राज करन खत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, आप से मेरा।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कोई भी पेपर दिखाना सदन की अवमानना है। मार्शल्स कुलदीप कुमार को बाहर ले जाओ। चलिये। इनको बाहर ले जाओ।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः संजीव झा इन्हें बाहर ले जाईये। संजीव झा। संजीव झा को बाहर ले जाईये। हांजी। सही राम जी को और प्रेम जी को बाहर ले के जाईये। विशेष रवि को बाहर लेके जाईये। मुकेश अहलावत, सुरेंद्र कुमार बाहर लेके जाईये। आतिशी जी को बाहर ले के जाईये। आले मोहम्मद को बाहर ले के जाईये। जरनैल सिंह जी को बाहर लेके जाईये। अनिल झा जी को बाहर ले के जाईये।

(माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार माननीय सदस्यों श्री कुलदीप कुमार, श्री संजीव झा, श्री सही राम, श्री प्रेम चौहान, श्री विशेष रवि, श्री मुकेश कुमार अहलावत, श्री सुरेन्द्र कुमार, श्रीमती आतिशी, श्री आले मोहम्मद इकबाल, श्री जरनैल सिंह और श्री अनिल झा को मार्शल्स द्वारा सदन से बाहर किया गया।)

माननीय अध्यक्षः सदन की बैठक 10 मिनट के लिये स्थगित की जाती है।

सदन पुनः अपराह्न 2 बजकर 10 मिनट पर समवेत हुआ

माननीय अध्यक्ष (श्री विजेन्द्र गुप्ता) पीठासीन हुए।

माननीय अध्यक्षः जी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी जो आज विधान सभा में किया गया।

माननीय अध्यक्षः मार्शल्स सोम दत्त को बाहर ले के जाओ।

(माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार माननीय सदस्य श्री सोम दत्त को मार्शल्स द्वारा सदन से बाहर किया गया।)

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः अब श्री राज करण खत्री जी। शुरू करें।

माननीय उद्योग मंत्री (श्री मनजिंदर सिंह सिरसा): अध्यक्ष जी बड़े खेद की बात है जो आम आदमी पार्टी के जो आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद, आम आदमी पार्टी के लीडर आम आदमी पार्टी ने एक सुनियोजित तरीके से दिल्ली के अंदर अंकित शर्मा हमारे किस तरह से आईबी अफसर को मारने का काम किया और वही लोग आज आके उन्हीं के साथी आज जेलों में बंद हैं जिनके साथी, मुझे बड़ा खेद है जिस तरह का उन्होंने विधान सभा के अंदर अपना आज आचरण दिखाया है इससे बड़ा स्पष्ट है वो उकसाना चाहते हैं दुबारा से। दिल्ली के अंदर इसी तरह की कानून व्यवस्था को दुबारा से खराब करना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं जो अंकित के कातिल जेलों में बंद हैं, जो ताहिर हुसैन जैसे लोग जेलों में बंद हैं दिल्ली में उन लोगों को बताना चाहते हैं कि देखिए हम तुम्हारे साथी हैं, हम तुम्हारी विधान सभा में लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या इस मानसिकता के साथ इस दिल्ली की विधान सभा को चलाया जाएगा, क्या ऐसे लोग जिन्होंने दिल्ली के अंदर दंगे-फसाद किये हैं, बेकसूर लोगों को मारने का काम किया है, जिन लोगों ने सुनियोजित तरीके से दिल्ली के अंदर दंगे-फसाद किये और ये मैं

नहीं कह रहा ये सारी की सारी इंटेलिजेंस की रिपोर्टों में, दिल्ली पुलिस की इंवस्टिगेशन में ये सारी चीजें सामने आई, सुनियोजित तरीके से दिल्ली के अंदर आग लगाने का काम और दिल्ली में लोगों को मारने का काम किया, आज वही लोग दिल्ली में जिनके साथी जो थे, जो इनके निगम पार्षद रहे और फिर और तो और आम आदमी पार्टी ने टिकटें भी उन लोगों को दी और आज वही लोग उनके सपोर्ट के अंदर विधान सभा में आकर जिस तरह का उधम मचा रहे हैं, मैं जरूर चाहता हूं आप इसका संज्ञान ले और ऐसे लोग जो अराजक तत्वों का साथ देना चाहते हैं इनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो सके। आपको इस हाउस की डिग्निटी को मेनटेन करने के लिए, आज कोई कातिलों का साथ दें और विधान सभा में आकर इस तरह का गंद फैलाने का काम करें, उसके ऊपर अध्यक्ष जी आपको कार्रवाई करनी चाहिए। आपका धन्यवाद आपने मुझे समय दिया।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, जिन सदस्यों ने यहां पर उद्दंडता की है और सदन की कार्यवाही को बाधित किया है वो लगातार सदन को बाधित करने का काम कर रहे हैं और जब उनके शॉर्ट नोटिस एक्सेप्ट किये गये तो उस समय ना शॉर्ट नोटिस पर बोलने आये और न ही शॉर्ट नोटिस पर मंत्री जी का रिप्लाई सुनने में उनका कोई इंट्रेस्ट था। अभी मुझे ये सूचना मिली है कि जिन सदस्यों को निष्कासित किया गया है सदन से, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि सदन से निष्कासन का अर्थ है परिसर

से निष्कासन, लेकिन मुझे जानकारी आई कि वो परिसर में हैं, हुडदंग कर रहे हैं। मैं सचिव महोदय से कहूंगा कि सदन को सूचित करें कि जिन लोगों को निष्कासित किया गया है अगर वो सदन के परिसर में हुडदंग कर रहे हैं तो उसकी जानकारी सदन के समक्ष आनी चाहिए। अब, हां, जी, मारवाह जी।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः अध्यक्ष जी, विपक्ष के लिए बड़ी शर्म की बात है जो दिल्ली में दंगे हुए और जो नौजवान की मौत हुई और पूरी दिल्ली को पता है कि ये जो दंगे हुए थे ये पूरी तरह एक षडयंत्र करके किये गये। सबसे बड़ी बात है अभी चुनाव हुए जो दंगों में शामिल था ताहिर हुसैन उसको कितनी वोटें मिली, ये इनके लिए सबूत है। अध्यक्ष जी, जिस हमारे मंत्री जी नाम ले रहे हैं उसकी पूरी दिल्ली में, कपिल शर्मा जी की जिंदाबाद हो रही है क्योंकि उन्होंने वहां पर शांति का संदेश दिया, आपस में भाईचारे का संदेश दिया, जब लोग मुसीबत में थे उनके साथ खड़े हुए और साथ में जो बाहर के, जिन्होंने षडयंत्र की थी वो लोग, उनका असली चेहरा जनता के सामने लेकर आये। अध्यक्ष जी, कल जब ध्यानाकर्षण का आपने टाइम भी दिया, आपने नियम-54 में उनको बोलने का समय भी दिया, क्योंकि आप सबको मिलकर, साथ लगाकर सदन को चलाना चाहते हों लेकिन उनकी नीयत में खोट है। कल आपने बार-बार कहा कि आकर इस पर चर्चा करो लेकिन कोई भी नहीं आया।

अध्यक्ष जी, मैं तो ये कहूंगा कि आपको इनको सख्ती से निपटना है, क्योंकि हर बात पर राजनीति कर रहे हैं, हर बात को राजनीति में लेकर जा रहे हैं, चाहे वो बजट की बात थी चाहे वो किसी पर भी बात थी, बिजली पर बात थी, आप चर्चा छोड़कर गये हो। लेकिन हमारे मंत्री जी ने पौना घंटा उस पर बोलकर क्लीयर किया कि आज जो दिल्ली में बिजली, एक-एक वर्ड क्लीयर किया लेकिन उनमें ये साहस नहीं था कि मंत्री जी बात सुने।

अध्यक्ष जी, आप बड़े सूझबूझ से विधान सभा का सत्र चला रहे हो। लेकिन उनकी नीयत नहीं देख रहे, उनकी नीयत में वही जुनून केजरीवाल का घूम रहा है, बेईमान का घूम रहा है जो दिल्ली का मालिक अपने आपको समझता था। अध्यक्ष जी, मैं यही कहूंगा कि आप इन पर कार्रवाई करते रहें जिससे कि ये हाउस में कोई राजनीति न कर सके। जय हिंद, भारत माता की जय। आपका धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः अब 280 पर निम्नलिखित सदस्यों द्वारा विशेष उल्लेख के मामले उठाये जाएंगे। माननीय सदस्य- श्री राज करन खत्री जी।

विशेष उल्लेख (नियम-280)

श्री राज करन खत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नरेला क्षेत्र में पिछले वर्षों से रोहिंग्या की संख्या बढ़ गई हैं, कई जगह पर तो सरकारी जमीनों पर कब्जा करके बस्तियां बन गई हैं जिससे प्रमुख रूप से सिंघु बॉर्डर के पास ड्रेन नंबर-6 के ऊपर बनी हुई रोहिंग्या बस्ती है, ये लोग दिखाने के लिए तो कबाड़ी का काम करते हैं लेकिन इनके पास हर तरह का नशा भी बिकता है और ये लोग रात में सिंघु बॉर्डर से नरेला जाने वाले रास्ते पर लूटपाट व वारदातों का अंजाम देते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस पर संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई के आदेश दिये जाए। धन्यवाद अध्यक्ष जी आपने बोलने का मौका दिया।

माननीय अध्यक्षः श्री उमंग बजाज।

श्री उमंग बजाजः आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय जल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष जी, जो ये पिछली आपदा पार्टी की सरकार थी इन्होंने एक सोचे समझे षडयंत्र के थ्रू अपना जो दिल्ली की जनता थी, जल बोर्ड के द्वारा उनको बिल्कुल नाजायज और बेबुनियाद पानी के बिल भिजवाये गये और आश्चर्य की बात ये है कि जहां पानी भी नहीं पहुंचा वहां पर लाखों के बिल पहुंच गये और जब व्यक्ति उसको जमा नहीं करा रहे तो उस पर पेनल्टी और ब्याज लगाया जा रहा है और मुझे लग रहा है कि ये मेरी विधान सभा ही नहीं ये पूरी

दिल्ली की समस्या है। तो आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं जल मंत्री जी से ये निवेदन करूंगा कि इसकी जांच कराई जाए, जो दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और एक इस पर पॉलिसी बनाई जाए, जो दिल्ली की और मेरी विधान सभा की जनता इस समस्या से जूझ रहीं है इनको इस समस्या से हल दिलाया जाए, इनको न्याय दिलाया जाए। आपने 280 के तहत बोलने का मौका दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः माननीय उमंग बजाज जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपना विशेष उल्लेख में सदन का ध्यान आकर्षित किया है और मैं समझता हूं कि जो पिछली सरकार ने लोगों को प्रताड़ित करने के लिए जो बिल रेज किये हैं उससे लोग बहुत तकलीफ में हैं, इस पर जितेन्द्र महाजन जी कुछ कहना चाहते हैं।

बढ़े हुए पानी के बिलों पर चर्चा

श्री जितेंद्र महाजनः धन्यवाद अध्यक्ष जी, उमंग जी ने जो विषय रखा है वो पूरी दिल्ली का विषय है। बीस-बीस गज के मकानों के लाखों-लाखों के रूपए के बिल आए और पिछली आपदा सरकार में हालात ये है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोगों ने प्राइवेट लोग भी रखे हुए हैं, जो जाकर इन लोगों का हरासमेंट करते हैं और कनैक्शन काटने के नाम पर अवैध उगाही भी करते है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इस बात की जांच होनी चाहिए की लाखों रुपए के बिल जिन इलाकों में पानी आ नहीं

रहा आपदा सरकार के समय में उन लोगों को लाखों रुपए के बिल मिले और बिल मिलने के बाद इन लोगों से जो अवैध उगाही रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा की गई उसकी भी जांच होनी चाहिए और इन लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, ऐसा मैं सदन से निवेदन करता हूं।

माननीय अध्यक्षः इसपर माननीय सदस्य श्री पवन शर्मा जी।

श्री पवन शर्माः माननीय अध्यक्ष जी जल बोर्ड के साथ-साथ में जो प्राइवेट सेक्टर में जो कम्पनी काम कर रही है वो उसी प्रकार के बिलों के साथ-साथ में जिन घरों में क्नेक्शन भी नहीं है, उन घरों के बिल भी लगातार वो भेज रहे है। मेरा आपसे निवेदन है कि जब वे जल बोर्ड के साथ में कम्पनियों में जहां-जहां काम कर रही है उनको भी साथ में जोड़ा जाए और जो उपभोगता है, जो बिना मतलब से उनके कष्ट को झेल रहे हैं, उनसे उनको मुक्ति मिले ये मैं निवेदन करना चाह रहा हूं।

माननीय अध्यक्षः श्री मनोज शौकीन जी।

श्री मनोज शौकीनः धन्यवाद अध्यक्ष जी, बहुत ही गम्भीर विषय जो अभी जो मेरे साथी ने उठाया, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि ये जो प्राइवेट कम्पनी है, नांगलोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जिसको वो मैनेज कर रही है, जहां पानी देना चाहिए पूरी कैपेसिटी के साथ वो काम नहीं कर रहा और जितनी गाद निकलती है वो सारी की सारी किराड़ी ड्रेन में

आकर के उसको जाम भी करती है, उसने कोई समाधान नहीं निकाला। हमारी ड्रेन फुल रहती है और माननीय अध्यक्ष जी जो बिल है उस प्राइवेट कम्पनी में मुझे याद है कि जब 11 साल से पहले दूसरी सरकार थी और मैं उसमें विधायक था तो एक प्रजेंटेशन उन्होंने दिया था। जल बोर्ड के अंदर की वो बढ़िया पानी साफ सुथरा पानी और 4 मंजिल तक उस पानी को पहुंचाएंगे। वो पानी 4 मंजिल तो क्या मोटर से ही पी पा रहे हैं लोग खिंचकर के, लेकिन बिल इतने अधिक आ गए कि ना तो सरकार के पास रेवेन्यू आ पा रहा है क्योंकि बीस गज के मकान में और लाख रुपए का बिल, ये बहुत ही एक गम्भीर एक विषय है, कोई ऐसी पोलिसी लाकर के, के आगे से रेवेन्यू भी सरकार के पास आ जाए, लोग बिल भी जमा कराएं और पीछे का था जो उसपर जो विचार करकर इसपर निर्णय जरूर लेना चाहिए, बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री सतीश उपाध्याय।

श्री सतीश उपाध्यायः अध्यक्ष जी मैं उमंग बजाज जी की बात ही को कह रहा हूं और सुबह से लेकर लगातार जिस तरह के बिल लोग लेकर के आ रहे हैं, इन्होंने दो साल से इनको मना कर दिया था कि बिल मत पे करिए और लाखों लाखों रुपए के बिल है, इसपर माननीय मंत्री जी को, मंत्रिमंडल को और निश्चित रूप से कोई ना कोई संज्ञान लेकर के, कोई पोलिसी बनानी पड़ेगी क्योंकि डिस्कनैक्शन के नोटिस भी अब लोगों को दे दिए हैं।

रिकवरी के भी दिये हैं, डिस्कनैक्शन के भी दिये हैं और लोगों को सात-सात दिन के नोटिस दिये हैं। हमारे यहां प्राइवेट कम्पनी है उन्होंने भी नोटिसिसिज दिये हैं। बहुत ही गम्भीर विषय है, मंत्री जी मेरा अनुरोध है कि कोई एमैनैस्टी स्कीम अगर लेकर के आनी है या किस तरह से उनको कुछ बिलों में क्या-क्या उनको करना है, माफ करना है, ये विषय दिन-प्रति-दिन और गम्भीर होता जाएगा तो इसपर चिंता करनी चाहिए।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री तरविंदर सिंह मारवाह।

श्री तरविंदर सिंह मारवाहः अध्यक्ष जी धन्यवाद आपका, अभी सतीश उपाध्याय जी ने कहा ये दो साल से नहीं अध्यक्ष जी ये करोना के बाद जो मुख्यमंत्री था वो खुद ही लोगों को कह रहा था बिल जमा मत कराओ। बिल बिल्कुल जमा मत कराओ, तभी इलैक्शन में जब वो गया लोगों ने उसके आगे बिल रखे तो कहता है मुझे जीता दो मैं सारे बिल माफ कर दूंगा। आज हालात ये बन गए हैं कि कम से कम 40-50 लोग रोज बिल लेकर आते हैं, किसी का 40 हजार का, किसी का 50 हजार का, किसी का लाख का, किसी का दो-दो लाख का, क्योंकि लोगों ने उसके कहने पे बिल नहीं जमा कराए। मैं तो अध्यक्ष जी यहां तक कहूंगा कि आपको पावर है, आपका धन्यवाद भी कर दूं कि आपने इस मुद्दे पर हम सबको बोलने का मौका दिया, क्योंकि इसपे केस भी बनना चाहिए, केजरीवाल पे, जिसने मुख्यमंत्री रहते खुद कहा कि आप पानी के बिल मत जमा कराओ मैं माफ कर दूंगा। अब तो

हम मंत्री जी को कहूंगा कि इससे करोड़ों रुपया भी इकट्ठा हो जाएगा, कोई ऐसी स्कीम लेकर आओ जिससे की लोगों को कुछ रियायत भी मिले, क्योंकि उसके करने से, मैसेज हमारा खराब जा रहा है आज, क्योंकि लोगों के कनैक्शन कटने के भी नोटिस आ रहे हैं और सुबह लोग रोज आके रोते है कि इतने–इतने बिल हम कहां से लाएंगे, तो इसलिए अध्यक्ष जी मैं कहूंगा, मंत्री जी से रिक्वैस्ट करूंगा इसपर जरूर आप मुख्यमंत्री जी से बात करके इसपर आप कोई स्कीम लाएं या जैसे भी करना है आप करें क्योंकि वो तो यही चाहते हैं हमारा संदेशा खराब हो। तो इसलिए मैं यही कहूंगा अध्यक्ष जी कि केजरीवाल पर मंत्री जी को कहूंगा की उसकी टेपिंग निकालकर रखो और उसपर केस चीफ सेक्रेटरी को कहो कि इसपर नोटिस दे, कि इसने लोगों को क्यों झूठ बोला, उसके लिए केस बनवाओ इसपर। अध्यक्ष जी ये आपकी ड्यूटी बनती है, इसपर कार्रवाई होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री सूर्य प्रकाश।

श्री सूर्य प्रकाश खत्रीः अध्यक्ष जी मेरे सदन के सभी साथियों में मैं सबसे कम उम्र के विधायक उमंग ने जो आज यह मुद्दा उठाया, यह मुद्दा सही मायने में पूरी दिल्ली के लिए आज एक बड़ी गम्भीर समस्या बनी हुई है। अध्यक्ष जी मेरा तो दफतर भी जो है जल बोर्ड के अंदर ही है और वहां पर पूरी विधानसभा के लोग जो आते हैं, उसके अंदर मैंने देखा किसी का बिल 40 हजार से और 13 लाख तक का बिल मैंने अपनी आंखों से देखा है। दो

लाख, तीन लाख, ढ़ाई लाख और ऐसे बिल भी देखें हैं जिनके घरों में ताले लगे हुए हैं उनके भी बिल आए हुए हैं। अध्यक्ष जी यह समस्या जो है पूरी दिल्ली की है और मैं ये समझता हूं कि ये जो पिछली सरकार थी इस सरकार ने एक पूरी षडयंत्र कर-कर दिल्ली के ये सारे दिल्ली के अंदर ये बिल भिजवाए हैं और उसके बाद वो ये कहता था कि ये बढ़े हुए बिल जो आ रहे हैं, जब हम सत्ता आ जाएंगे तो ये सब बिल माफ कर दिये जायेंगे। और अध्यक्ष जी ये जो काम किया गया है ये जांच का भी विषय है, इससे पूरी दिल्ली आज पीड़ित है और लोग इसमें सुनने के लिए, डिपार्टमेंट सुनने के लिए तैयार नहीं है और ये जो 78 हजार करोड़ का जो घाटा है, वो यही सब घाटा नजर आ रहा है जिससे की आज दिल्ली की जनता पीड़ित है। इसके अंदर जांच कराई जा जाए और मैं जल मंत्री महोदय से कहूंगा कि इसके अंदर दिल्ली के लोगों को न्याय मिले, इसपर जरूर कोई ना कोई पोलिसी आनी चाहिए, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री मोहन सिंह बिष्ट जी।

श्री मोहन सिंह बिष्टः आदरणीय अध्यक्ष जी, वैसे तो ये विशेष उल्लेख में इस मामले को उठाया गया है लेकिन आपने दिल्ली के लोगों की समस्याओं को समझते हुए विशेष उल्लेख के तहत जो इस प्रकार की रूलिंग देकर के आम दिल्ली के विधानसभा के सदस्यों को जो बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, ये सत्य है कि दिल्ली के अंतर्गत पीने का पानी तो है नहीं लेकिन बिलों का इस प्रकार से भरमार है जिस क्षेत्र से मैं चुनाव जीतकर के आया हूं अध्यक्ष महोदय आपको सुनकर के ये बहुत अचंभा होगा कि पिछले दिनों के अंतर्गत एक ऐसी सरकार सामने बैठी हुई जो आज विपक्ष में है उसने उन लोगों के घरों में बेहिसाब बिलों को भेज दिया जिनके घर में पानी नाम की एक बूंद नहीं है। पीने का पानी है नहीं यही नहीं अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक बहुत बड़ा घोटाला क्या किया है कि पानी की पाइप लाइन को उनके घर तक तो छोड़ दिया लेकिन पानी नहीं है। अब बात कहां आ रही है यदि हम जैडआरओ के आफिस में जाते हैं तो वहां से कहते हैं जी वो सर्टिफिकेट लाओ लिख के दो फिर इन बिलों की में कटौती की जाएगी। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं मंत्री जी जल एक ऐसी चीज है जिसके बगैर कोई जी नहीं सकता। यदि इस बार आपने पिछले बिलों को देखते हुए एक पालिसी बना दी और पालिसी के तहत अभी तय कर लिया कि ये बिल इतने इतने से ये हो जाएगा, एक तो आपको रेवन्यू मिलेगा, दूसरा वो लोग मेरी सरकार को दुआ देगें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी मंत्री जी जरूर इसी पर स्टेटमेंट देवें कि जो लोगों के फर्जी बिल आ रखे हैं, जहां पीने का पानी नहीं है उनको तुरंत माफ कर दिया जाए। इस प्रकार का आदेश यदि यहां से मिल जाएगा तो वास्तव में दिल्ली के अंदर एक नया इस प्रकार

का प्रचार प्रसार होगा कि भाजपा की सरकार आने के बाद उन्होंने इस प्रकार का काम किया, ये मैं कहना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री दीपक चौधरी जी।

श्री दीपक चौधरीः बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी मैं जल मंत्री जी का ही इस पे एक महत्वपूर्ण विषय है उसपे ध्यान खींचना चाहता हूं कि बहुत जगह ऐसा पाया गया है क्योंकि मैं बादली विधानसभा क्षेत्र से आता हूं वहां पे बहुत सी कच्ची कालोनियां हैं सुबह के समय यहां बहुत टाइम के समय जो हमारे लाइनमैन हैं वो पानी को जो है वो स्लो कर देते हैं जिससे जो वाटर सप्लायर हैं उनकी साठगांठ से वो अपना काम चला पाएं, जो बोतलों में पानी बिक रहा है उसको वो पैसे देते हैं या उसे ओबलाइज करते हैं जिससे मजबूरन लोगों को वो बोटल खरीदनी पड़ती है जब पानी नहीं आता और अध्यक्ष जी एक और चीज इसी पे मैं जो हमारी एनडीपीएल है जब गवर्नमेंट ने बिजली को एनडीपीएल प्राइवेट कंपनी के हाथ में दिया था तब सोचा था कि बड़ी सुविधाएं मिलेगीं लेकिन क्या किया जा रहा है, जब मीटर लगाने के लिए हम ओनलाइन जब ऐप्लीकेशन डालते हैं तो रिजेक्ट कर दी जाती है।

माननीय अध्यक्षः एक मिनट एक विषय पे रहिए। जल पर ही बात कीजिए ना।

श्री दीपक चौधरीः अच्छा जल पर ही बात करनी है। ठीक है जल पर मेरे को यही बोलना था। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी आपने बोलने का मौका दिया।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री कुलवंत राणा जी।

श्री कुलवंत राणाः अध्यक्ष जी धन्यवाद, अध्यक्ष जी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री जी ने जलबोर्ड का दुरूपयोग किया, अधिकारियों का, शासन का दुरूपयोग करके इस प्रकार का वातावरण पैदा कराकर, जानकर के कि भई बिल भेजो और बिल भेजने के बाद खुद कह दिया कि बिल माफ कर देगें भरने की जरूरत नहीं है। सदस्य नीति बनाने के लिए भी कह रहे हैं, नीति तो बनी हुई है बीस हजार लीटर फ्री पानी दिल्ली में है वो उसी नीति के तहत जो बिल किसी के भेजे हैं उनको रदद किया जाए और गुमराह करने का काम किया और डर पैदा किया जा रहा है,उसको जो है प्रशासन अभी भी जारी किए हुए है। उसके साथ साथ एक नोटिस जो ग्राउंड में बोरवेल वाटर का मैटर भी है। पूरी दिल्ली में जिन्होंने टयूबवैल लगा रखे हैं, जिन्होंने बोरवेल किया हुआ है उनको भी नोटिस जारी कर रहे हैं। हर जगह पूरी विधानसभा में, दिल्ली में भी ये एक नया विषय पैदा कर दिया है और एक और खौफ पैदा किया जा रहा है लोगों में, सबको नोटिस जारी कर रहे हैं उनके सीज कर रहे हैं, सील कर रहे हैं वो भी एक दिल्ली में एक बड़ी समस्या है और नीति पहले से ही इसके उपर है कि बीस

हजार लीटर पानी फ्री है उसके उपर उपर बिल लो, बीस हजार लीटर तक का माफ वही रहेगा और कौन सा रहेगा।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री अभय वर्मा जी।

श्री अभय वर्माः धन्यवाद अध्यक्ष जी, पानी के बिल को लेकर पिछले पांच साल हम लोगों ने बहुत सामने बैठकर हल्ला किया था।

मननीय अध्यक्षः इस पर ना अभी 5 मिनट के अंदर-अंदर जितने मेंबर्स होंगे जो बुलवाना है मेरे पास नाम है, नया नाम नहीं जोड़ा जाएगा और आदरणीय मंत्री जी ने अपना बयान इस विषय पर देने का मन बनाया है, तो अंत में माननीय मंत्री जी इस पर अपना वकतव्य देंगे। क्योंकि मुझे 280 चलाना है अभी और ये इतनी समय सीमा में इसको समाप्त करना है।

श्री अभय वर्माः अध्यक्ष जी सामने बेंच पर बैठकर इस बिल के बारे में चर्चा करते थे कि अनाप-शनाप बिल आ रहे हैं, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं तो यहां से मंत्री जी ने एक बयान दिया था कि हमने एक आम माफी योजना बनायी है और एलजी साहब फाईल को रोक के बैठे हैं। मैं आज चाहता हूं कि मंत्री जी सारे विषयों पे जांच करें क्योंकि उस समय सरकार एलजी जैसे एक सम्मानित संस्था को बदनाम करने का भी काम यहां बैठ के करती थी और कौन सी आम माफी योजना थी क्या थी ये सारी चीजें दिल्ली के लोगों के बीच में जाना चाहिए क्योंकि वो दिल्ली के

लोगों को भरमा के वोट लेना चाहते थे कि हमने ये पालिसी बना दी है हमने ये पालिसी बना दी है सबका आम माफी होना है बल्कि मेरा बयान है हाउस के अंदर कि जब आम माफी है तो सबको जीरो कर दो ना। सबका बिल जीरो कर दो तो वो जीरो नहीं कर रहे थे केवल वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे तो ये भी मंत्री जी के माध्यम से मैं जानना चाहूंगा कि इस राजनीति का पटाक्षेप होना चाहिए और आम आदमी पार्टी जो दिल्ली के लोगों को भरमाई है उससे उनका सच सामने आना चाहिए और सही मायने में अध्यक्ष जी एक बात कह के मैं बात पूरा करूंगा आज कल जल विभाग के लोग बिल ले के वारंट के रूप में जाते हैं कि देखो जी इतना बिल है अच्छा कोई भरने के लिए भी तैयार होता है तो वो कहते हैं भरो मत पांच दस हजार दे दो हम इसको आगे बढ़ा देगें तो इसपे संज्ञान ले के इस पूरे malpractice को रोकना चाहिए और one go एक settlement होना चाहिए ताकि लोगों को भी रिलिफ मिले और ये मसला भी solve हो। बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री राजकुमार भाटिया जी।

श्री राजकुमार भाटियाः आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं अपने साथी उमंग बजाज जी ने जो विषय उठाया है उस पे उनको साधुवाद देता हूं। ये पूरी दिल्ली का विषय है इस विषय में मेरा सबमीशन है कि एक व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठकर किस प्रकार से दिल्ली की जनता को राजस्व ना देने के लिए प्रेरित करता है

stopping people to submit their revenue to the State एक तरफ वो स्टेट का नुकसान कर रहे हैं दूसरी तरफ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा जब मंत्री जी इस पर संज्ञान लेगें तो आदरणीय मंत्री जी जिस व्यक्ति ने दिल्ली की जनता को बिल भरने से मना किया है ये सारे का सारा बिल जनता को तो माफ कर दिया जाए उसकी संपत्ति कुर्क करके उससे वसूला जाए जितना उसने दिल्ली को कहा है कि आप बिल मत भरो। आपको बिल भरने की जरूरत नहीं है और अभी मेरे एक साथी आपको बता रहे थे उस और इशारा कर रहे थे कि एक माफिया चल रहा है जो लोगों से सैटलमेंट के लिए कहता है और रोहिणी जैसे क्षेत्र में जहां फलैटों की बिकवाली रहती है जहां केवल फ्लैट बिकते हैं उन फलैटों में जो बिल है या छोटे छोटे मकान हैं उनके बिलों की सैटलमेंट को ले के अगर मंत्री जी इस पर विशेष ध्यान देगें तो फर्जी रसीदें छापकर भी लोगों के बिलों की सैटलमेंट की गई है। वहां पर उनको फर्जी रसीद दे दी गई उनको कह दिया कि आपका नो डयूज है क्योंकि जलबोर्ड में एक लंबा घाटा था और आउट स्टैंडिंग बिल दिखा के उन्होंने जो fiscal management कर रखा था उसका भी पर्दाफाश होना चाहिए, लेकिन मेरी पुरजोर अपील है कि जिस व्यक्ति ने दिल्ली की जनता को राजस्व ना भरने के लिए कहा है बिल ना भरने के लिए कहा है उसकी कुर्की के माध्यम से सारी दिल्ली के बिल लिये जाने चाहिए।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री करनैल सिंह जी।

श्री करनैल सिंहः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं मंत्री जी का ध्यान और सभी सदस्यों ने ये पानी का विषय उठाया। सबके बिल पेंडिंग हैं और वो बिल बढ़ते जा रहे हैं और आज सुबह मेरे पास कम से कम 30-40 बहने आईं कि इतने बिल हम कैसे भरेंगे और जब तक उस बिलों की सेटलमेंट नहीं होगी जब तक वो आगे भी बिल नहीं भरेंगे। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कुछ ऐसी समस्या का हल निकाला जाये ताकि जो आज का जो बिल है वो आज का भी नहीं भरेंगे और पूरे महीने का बिल भी नहीं भरेंगे। जिससे हमारे राजस्व के अंदर बहुत घाटा होगा। तो ऐसा कोई समस्या का हल निकाला जाये तो immediately जो बिल है इस महीने का जो मार्च का बिल है कम से कम वो भरने के लिए वो आ जाये ताकि एक व्यवस्था चलती रहे। पिछला जो बिल है उसको पेंडिंग करके उसका क्या समस्या का हल होगा वो बाद में हो सकता है। जो रेवेन्यु हमारा आज से जो रूक रहा है क्योंकि जैसे-जैसे उनका पिछला बिल जुड़के आता है। अभी डेढ़ लाख का तो इस महीने एक लाख बीस हजार का हो गया। तो वो सोचते हैं कि इतना कैसे भरें तो वो सबका सब रूका हुआ है। तो मेरा अनुरोध है मंत्री जी से कि उसका कोई ऐसा समस्या का हल निकाला जाए, ताकि immediately इस महीने का बिल या अगले महीने का बिल वो लोग रेगुलर भर दें। एक जो reasonable बिल है और पिछला जो इक्कठा है उसके लिए कोई पॉलिसी लगाने के

लिए उसमें बड़ा टाइम लगेगा। पॉलिसी बनाने में उसको माफ करना है या उसको आधा करना है उसके अंदर समय लगेगा। तो ऐसा कोई समस्या का हल निकाला जाए कि जो immediately जो बिल आ रहा है उसको भरा जाए। और राजस्व का घाटा ना हो। मैं आपके माध्यम से ये सवाल पूछा उसके लिए धन्यवाद करता हूँ, जय श्री राम।

माननीय अध्यक्षः अंतिम वक्ता माननीय सदस्य श्रीमती शिखा राय।

श्रीमती शिखा रायः धन्यवाद अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी विषय लगभग आ गए क्योंकि मुझसे पूर्व जो मैं रखना चाहती थी वो अभी करनैल जी ने रखा। लेकिन चूंकि ये विषय अभी आज आया और आज ही हमारे यहां ग्रेटर कैलाश में एक व्यक्ति के खिलाफ एफआइआर लॉज हुई है। जो जलबोर्ड का अधिकारी बनकर के उसने इस तरह से पॉज किया कि फर्जी जो है सबको रि-बिल्स दे दिये जो सारे फर्जी थे। वो लाखों का बात है। तो इस तरह से क्योंकि अब सब पैनिक के मूड में आ गए हैं कि अब इन बिलों का क्या करना है और लाखों के बिल हैं हमारे यहां तो झुग्गी कलस्टर के भी झुग्गीवासी का लाखों का बिल है। एक लाख, दो लाख इस तरह के कैंप के भी बिल हैं। तो सबको कोई-ना-कोई निदान चाहिए तो इस तरह के व्यक्ति आगे और ना बढ़ पायें कि अपने बिलों को वो सेटलमेंट के रूप में करवाने का करें तो जरूर इसपे कुछ विचार होना चाहिए। पिछले जो दो वर्षों से लगातार इनके

विधायक और ईवन मुख्यमंत्री साहब ने जब स्टेटमेंट देकर के उनको ये कह दिया कि आप मत भरिये तो बहुत से लोगों का वो दो सालों में इन्ट्रेस्ट और पेनल्टी जो मूल था उसके ऊपर बहुत ज्यादा हो गई है। तो ज्यादातर इसमें जो बिल में बढ़ी हुई वो हैं वो पेनेल्टी और इन्ट्रेस्ट हैं। तो इसके ऊपर विचार करके कि amnesty में हम क्या कर सकते हैं कितना कर सकते हैं उन बिलों का जरूर निदान करना चाहिए धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण जनहित का जिस मामले पर हमारे बीच में से बहुत सारे सदस्यों ने अपने विचार रखे। ये जो इन्फ्लेटिड बिल है इसका कन्क्लुजन ये है कि ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। जनता बहुत टेंशन में है क्योंकि पिछली सरकार ने बिलों के ऊपर 50-50 गुना, 100-100 गुना पेनेल्टी वगैरह लगा के, उसको वो पे करना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो पे नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बिल इतना हायर साइड पर है। तो इसमें सदस्यों की जो भावना यहां निष्कर्ष निकला है जिस पर मंत्री जी अपना वक्तव्य देंगे वो ये है कि इसमें एक वन टाइम amnesty स्कीम अगर सरकार विचार कर रही है तो निश्चित रूप से दिल्ली की जनता का बहुत बड़ा भला होगा। इस पर आदरणीय मंत्री जी श्री प्रवेश वर्मा जी सदन को संबोधित करेंगे।

श्री प्रवेश साहिब सिंहः तालियों पे डिपेंट करें कि राहत क्या मिलेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये जो लोग 10 साल सत्ता में रहे

ये इतने पाप करके गए हुए हैं कि हमको समय लगेगा इनको ठीक करते–करते। मगर ये जो सारे सदस्यों ने एक बात कही है कि 100–100 गज के मकान में भी लाखों रूपए के बिल आ रहे हैं। 25 गज के मकान में भी लाखों रूपए के बिल आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इलेक्शन से पहले जो सरकार थी उन्होंने ये बदमाशी करी है कि ऐसे लोगों के घरों में लाखों रूपए के बिल भेजकर उनको डराया जाए, धमकाया जाए और जो उस समय मुख्यमंत्री रहते थे वो ये कहते थे कि हमारी सरकार आयेगी तो हम सभी को माफ कर देंगे, बिल आपको जमा कराने की जरूरत नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयेगी तो आपको लाखों रूपए के बिल तो इस तरीके से उनको एक उनको डराने का भी काम किया। अभी हमारे सदस्य मारवाह जी कह रहे थे कि हमारे मान–सम्मान की रक्षा कीजिए क्योंकि नई–नई सरकार बनी है। तो मैं आप सभी को एक बात कहना चाहता हूँ कि आपका मान–सम्मान बढ़ायेंगे, कहीं पर भी मान–सम्मान आपका कम नहीं होने देंगे और इसके बारे में जो अभी एलपीएससी की बात करी लेट पेनल्टी सर्विस चार्ज की ये बहुत ही जो है ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज लगा रहे हैं तो हमने मुख्यमंत्री जी से भी बात करी थी। मुख्यमंत्री जी से बात हुई है और बहुत ही जल्दी आपको खुशखबरी भी देंगे। दिल्ली की जनता को और मैं आपको एक बात बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ जब तक इस समस्या का समाधान नहीं निकलता है तब तक एक भी कनैक्शन को काटेंगे

नहीं। कोई भी पानी का कनैक्शन नहीं कटेगा। अगर कोई बिल अपना जमा नहीं करा रहा है जिसके घर पे 25 गज, 50 गज में कोई कमर्शियल टावर की बात नहीं कर रहा मगर ऐसे छोटे घरों में अगर कोई बिल नहीं जमा कराता तो दूसरी बात इसमें जो मीटर रीडर हैं ये बात भी ठीक है अभय जी ने कही है कि जो मीटर रीडर है ये भी बहुत बड़ी बदमाशी करते हैं। अब ये जो है मैं सारे सदस्यों से कहूंगा कि आप भी जनता से कहिये, मैं भी दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूँ अगर कोई मीटर रीडर बदमाशी करता है कृपया सेटलमेंट में मत जाइये आपका कनैक्शन नहीं काटेंगे। हमें उसकी शिकायत कीजिए। हम ये सारी बीमारी को जड़ से खत्म करना चाहते हैं और इसमें मुझे ये भी कहना है कि जब हम लोग अपने घरों में पम्प चलाते हैं, मोटर के लिए पानी के लिए मोटर चलाते हैं तो ये जो मीटर हैं ये हवा खींचते हैं। जब वो हवा आती है उससे भी ये चलते हैं। तो भी बिल ये बढ़ता रहता है। तो मीटर भी ठीक करायेंगे। मीटर भी अच्छी ये लोगों ने पता नहीं कैसे मीटर लगाये हुए थे कितनी उसमें भी कोई इन्होंने करप्शन किया है। मगर मीटरों की भी जांच करायेंगे। अच्छे मीटर चलायेंगे। जो इस तरीके से फर्जी बिल ना बनायें। तो कुल मिलाकर मैं इस बात को समझता हूँ कि दिल्ली में पानी की समस्या बहुत ही गंभीर है लोगों को पानी भी नहीं मिल रहा। मगर हमारी पूरी कोशिश है कि इस समर में सारे लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी भी मिले। साफ पानी भी मिले। उनके फर्जी बिल भी ना

आयें। और जिन लोगों के अगर गलत बिल हैं उनको भी हम एक अच्छी खुशखबरी देंगे।

माननीय अध्यक्षः अब विशेष उल्लेख में माननीय सदस्य श्री तिलक राम गुप्ता जी अपना वक्तव्य रखेंगे।

विशेष उल्लेख (नियम-280) जारी....

श्री तिलक राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान मेरी विधानसभा त्रिनगर की ओर दिलाना चाहता हूँ कि उसके अंदर आने वाली जो झुग्गी-झोपड़ी हैं उनकी बहुत ही हालत खराब है। नालियां टूटी पड़ी हैं, ओवरफ्लो हो रही हैं। सड़कों के ऊपर पानी घूम रहा है और सड़कें टूटी हुई पड़ी हैं। और जितने भी टॉयलेट बने हुए हैं, टॉयलेट बंद पड़े हैं। टूटियां नहीं हैं उनके अंदर और उन टॉयलेट्स के ऊपर लोगों ने अवैध कब्जे किये हुये हैं। सभी निवासी बहुत परेशान हैं पानी की समस्या है पीने का पानी नहीं आता है, टैंकर मंगाते हैं तो कभी एक आता है कभी दो आते हैं कभी आते ही नहीं कई बारी, बहुत ज्यादा समस्या होने की वजह से पूरी जनता बहुत दुखी है और क्वॉलिटी भी बहुत खराब आ रही है पानी की इसलिये मेरी आपसे प्रार्थना है कि वहां पर साफ-सफाई का और पानी का इन्तजाम किया जाये और साथ में जो नालियां बनाने का और सड़क बनाने का इन्तज़ाम किया जाये इसलिये और जो पानी के बिलों की जो बात है वो तो मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया जल्दी से जल्दी खुशखबरी आयेगी बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री श्याम शर्मा।

श्री श्याम शर्माः माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का 280 पर बोलने का मौका दिया मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका ध्यान हरि नगर विधानसभा क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी, एमसीडी की सड़कों पर जो अतिक्रमण है पिछले आपदा पार्टी की सरकार से चल रहा है और हालत इतनी खराब है कि आप देखेंगे तो लोग वहां पर चल नहीं सकते ट्रैफिक जाम रहता है। इतनी स्थिति खराब हुई हुई है सर इन सड़कों और बिना लाइसेंस के अनेकों दुकानें, रेड़ी, पटरी चल रही हैं और बड़ी संख्या में ई-रिक्शा भी बिना लाइसेंस के चल रहे हैं। स्थानीय निवासियों की बड़ी समस्या बनी हुई है। इसमें ट्रैफिक जाम भी रहता है अध्यक्ष जी, मेरी आपसे इतना ही निवेदन है कि आपका हस्तक्षेप की आवश्यकता है इसमें कई ऐसे रोड़ हैं लाजवन्ती गार्डन मेन मार्केट, सुभाष नगर, नांगल राय मार्केट, हरि नगर घंटाघर। अध्यक्ष जी इन्होंने अपना घर भी वहां बना दिया है आप देखेंगे तो वहां रोड़ पर पीडब्ल्यूडी के रोड़ों पर घर बन चुके हैं छोटे-छोटे घर बनाकर इन्होंने वहां पर अपना रहना शुरू कर दिया है जिसके कारण ट्रैफिक निकल नहीं सकता, माँ-बेटी-बहन वहां से जा नहीं सकती पूरा एक-एक घंटा डेढ़-डेढ़ घंटा वहां पर जाम रहता है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इससे संबंधित जो भी इस विभाग से संबंधित सरकारी विभाग के लोग हैं उनको आप निर्देश दें कि इन पर जल्दी से जल्दी समाधान निकाला जा सके, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री अशोक गोयल जी।

श्री अशोक गोयलः माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे 280 के विशेष उल्लेख पर जो अवसर दिया आपका हृष्दय से आभार और आज जो स्ट्रे डॉग की जो समस्या है जो हमारी विधानसभा में विशेषकर बहुत ही ज्यादा है। वैसे तो डॉग इन्सान का सबसे अच्छा दोस्त है और डॉग ने ही जो हमारे पांडवों के राजा थे युधिष्टिर को स्वर्ग का रास्ता भी दिखाया कि पहले ऐसा एनिमल है जिसको कि इन्सान अपने घर में रखना शुरू किया लेकिन जो दिल्ली में और मॉडल टाउन विधानसभा में विशेषकर स्ट्रे डॉग एक आज बड़ी समस्या बन गया है 6 से 8 लाख स्ट्रे डॉग आज दिल्ली में हैं जिनको प्रोपर रहने के लिये शैल्टर नहीं मिलता प्रोपर खाना नहीं मिलता Prevention of Cruelty to Animal Act, 1960 के अनुसार उनको शैल्टर मिले इसका भी प्रोविजन किया गया है लेकिन हम सब देखते हैं कि ये एक सपना है उनको ऐसा मिलता नहीं है और उसके अभाव में उनको जब प्रोपर खाना नहीं मिलता प्रोपर शैल्टर नहीं मिलता तो वो इन्सान पर अटैक भी करते हैं और उनको बाइट भी करते हैं। पिछले 6 महीनों में करीब-करीब दिल्ली में एक लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों को स्ट्रे डॉग्स ने बाइट किया है ये सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल के अध्यक्ष जी आंकड़े हैं और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल और सफदरजंग हॉस्पिटल इसमें हर रोज़ 100 से 200 बाइट के केसिज़ आते हैं और जब मैं मॉडल टाउन विधानसभा के अलग-अलग पार्कों में जाता हूं मैं अभी कल ही नागिया पार्क में

गया वहां पर उन्होंने, दौरा पार्क का करने गया था लेकिन हमारी एक बहन ने बताया कि ये डॉग है और ये हर तीसरे दिन किसी को काटता है लेकिन स्थिति इतनी विचित्र है कि कानून ऐसा है कि उस डॉग को ले भी जाते हैं उसको स्टेरिलाइज भी करते हैं लेकिन वहीं छोड़ते हैं और स्टेरिलाइज करने के बाद भी वो काटता है चाहे वो गोटे वाला पार्क हो, मॉडल टाउन में राणा प्रताप बाग में हाथी वाला पार्क हो, मालवा टैक्सी स्टैंड वाला पार्क हो जब भी हम रूप नगर में एक हमारे मित्र हैं चार्टड एकाउंटेंट उनको एक ही कुत्ते ने तीन बार काट लिया है और इतनी विकट समस्या है ये कि इसको लेकर निश्चित रूप से सरकार को जरूर कुछ करना चाहिये। एमसीडी इसको लेकर कुत्तों को लेकर जाती है उनका नसबंदी करती है और उससे ये समस्या बताती है कि इससे अब कुत्ते बढ़ेंगे नहीं लेकिन कुत्ते बढ़ते जा रहे हैं इसका मतलब जो नसबंदी की जा रही है माननीय अध्यक्ष जी वो भी उचित नहीं है और कम से कम, कम से कम जो कुत्ते अटैक करते हैं बाइट करते हैं उनके ऊपर कोई ना कोई सोल्युशन माननीय मंत्री जी जरूर निकालना चाहिये ये पूरे मॉडल टाउन विधानसभा के साथ-साथ कमला नगर, शक्ति नगर के साथ-साथ पूरे दिल्ली की भी ये समस्या है इस पर जरूर आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को संज्ञान लेकर इसको कुछ करना चाहिये, माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का अवसर दिया बहुत-बहुत आभार।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री चंदन कुमार चौधरी।

श्री चंदन कुमार चौधरीः धन्यवाद अध्यक्ष जी आपने मुझे 280 पर बोलने का मौका दिया इसके लिये आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष जी, मेरी विधानसभा जो है फुली अनॉथराइज है जहां पर लगभग 8 से 10 लाख की आबादी है और आवाजाही के लिये मात्र तीन रास्ते हैं तीनों रास्तों पर पूरा इन्क्रोचमेंट है जो बहुत माफियाओं के द्वारा छोड़ा गया है उस पर नाबालिग मुसलमान के बच्चे रेड़ी पटरी वाले मुसलमान रोहिंग्या मुसलमान और एचआर नम्बर की गाड़ियां जो पिछले विधायक के गुर्गे के द्वारा चलाया जा रहा था आज भी उसी तरह की अव्यवस्था बनी हुई है। तीनों रास्ते इन्क्रोच किये हुये हैं चलने का रास्ता नहीं है यदि हम भी घुसते हैं तो दो-दो घंटे का जाम लग जाता है। इस प्रकार की अव्यवस्था हमारे क्षेत्र में हो रही है और गष्ह मंत्री जी अभी कहीं चले गये हैं मैं गष्ह मंत्री जी के संज्ञान में देना चाहता हूं कि पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करके ये जितने ई-रिक्शा हैं ये जो रोहिंग्या मुसलमान और नाबालिग मुसलमान के द्वारा चलाये जा रहे हैं उनका मकसद रोज़ी-रोटी चलाने का नहीं है इनके माफियाओं के द्वारा सिर्फ ये मकसद होता है कि अपनी कमाई करो और उससे रिक्शा चलवाओ और वो जो रिक्शा चालक है वो सिर्फ इसलिये रिक्शा चलाता है उसको स्मैक और गांजा पीने का पैसा मिल जाये और जिस दिन वो नहीं मिल पाता है उस दिन वो चाकू और छिना-झपटी के द्वारा वारदात करते हैं। इस तरह के वारदात हमारे यहां बहुत ज्यादा चल रहे हैं इसको आपके संज्ञान में डालना चाहता

हूं कि जल्द से जल्द इसकी कार्यवाही हो। एक हमारा क्षेत्र तुगलकाबाद एक्सटेंशन है जहां पर पीडब्ल्यूडी का भी रोड़ है और हमारे दूसरे डिपार्टमेंट के द्वारा भी रोड़ बनाये जाते हैं वहां पर चार-पांच स्कूल एक साथ हैं स्कूल की बाउंडरी के साथ-साथ अध्यक्ष जी इतने इन्क्रोचमेंट हैं खराब गाड़ियां हों या कमर्शियल व्हीकल हो ट्रक हो, वो सारा जाम करके वहां के बच्चों को जाने का रास्ता नहीं मिलता है अभी हमने प्रिंसीपल से बैठक किया था प्रिंसीपल ने आग्रह किया कि सारी व्यवस्था तो हम लोग सुदष्ढ़ कर लेते हैं लेकिन ये अव्यवस्था जो है हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं इसके लिये आप यदि कर देंगे तो हमारे बच्चों के लिये सुविधा होगी, आये दिन वहां वारदात होते हैं, बच्चों को चाकू मारा जाता है और हमारे लोग वहां पर बहुत ही असहज महसूस कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री को भी संज्ञान में देना चाहता हूं कि स्कूल के इर्दगिर्द आसपास कोई इनक्रोचमेंट न हो और इस व्यवस्था को बनाकर हम अपने बच्चों को एक अच्छा स्वभाव दे सकें कि वो आएं स्कूल में पढ़ने के लिए और अच्छी शिक्षा लेकर के जाएं। एक और अहम मुद्दा आपके संज्ञान में देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय की हमारा इलाका जो है बाउंड्री जो है वो फोरेस्ट का है फोरेस्ट के लोग आए दिन उनको धमकी देते हैं घर तोड़ने की धमकी देते हैं और जो फोरेस्ट का दूसरा इलाका है जहां खाली जमीन है वहां माफियाओं के द्वारा पार्किंग किया जाता है उस चीज को वो नहीं काम करते हैं लेकिन फोरेस्ट के द्वारा हम सभी जनता को जो

आम जनता जो की ग्रामसभा की जमीन पर बसी हुई है जो पहले ग्रामसभा की जमीन थी 2019 के बाद फोरेस्ट को अलॉट किया गया है उसको तोड़ने की धमकी भी देते हैं और आए दिन तोड़ देते हैं। तो मैं आपके संज्ञान में इसलिए डाल रहा हूं की जल्द से जल्द इस पर सुनवाई हो और हमारे संगम विहार की जनता के लिए एक वरदान साबित हो बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री ओम प्रकाश शर्मा जी।

श्री ओम प्रकाश शर्मा: धन्यवाद अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान गाजीपुर सब्जी मंडी में अतिक्रमण व भारी अनियमितता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह एक गंभीर समस्या बन चुकी है जो न केवल व्यापारियों और किसानों बल्कि उपभोग्ताओं के लिए भी परेशानी उत्पन्न कर रही है। इस मंडी में अतिक्रमण बहुत बड़ी समस्या है। मंडी क्षेत्र में कई स्थानों पर व्यापारियों और अन्य लोगों के द्वारा अनधिकृत रूप से दुकानें सड़कें और गलियां घेर ली गई हैं जिसके कारण मंडी में घुटन जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे आवागमन में काफी समस्या होती है। सब्जियों का रख-रखाव भी प्रभावित हो रहा है। मंडी में सफाई जल-निकासी अन्य बुनियादी सुविधाओं का नितांत अभाव है। जगह-जगह कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। जलभराव की समस्या भी उत्पन्न हो रही है जिससे संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ रहा है। यह मंडी के समग्र व्यापार और सुरक्षा को प्रभावित कर रहा है। मंडी में कई स्थानों पर व्यापारी व

दुकानदार बिना लाइसेंस और उचित पंजीकरण के कारोबार कर रहे हैं। यह व्यवस्था और अनियमितता व्यापारिक माहौल को खराब कर रही है और मंडी में माफियाओं के द्वारा अवैध उगाही की जा रही है। अध्यक्ष जी मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विनम्र निवेदन है कृप्या इन समस्याओं के समाधान के लिए जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठाएं ताकी व्यापारी, किसान और उपभोग्ता सभी को सुविधा हो और मंडी की स्थिति सुधरे, मंडी का विस्तार किया जाए। पिछले 10-12 साल में यह मंडी जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है इसके ऊपर निवेदन है कि मंत्री जी संज्ञान लें, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री जितेन्द्र महाजन जी।

श्री जितेन्द्र महाजनः धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से लोक निर्माण विभाग के माननीय मंत्री जी की ओर एक महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, रोहताश नगर विधानसभा में एक लोनी रोड है यह वह लोनी रोड है जिसके ऊपर पहले एक प्रस्ताव आया था की दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस-वे लोनी रोड से होता हुआ निकलेगा मगर आपदा सरकार के कारण उस प्रस्ताव को बदलवाया गया और वह हाइवे कहीं और से निकाला गया। माननीय अध्यक्ष जी, यह रोड रोहतास नगर विधानसभा, बाबरपुर विधानसभा और गोकलपुरी विधानसभा तीन विधानसभाओं की लाइफ-लाइन है और यह रोड शाहदरा से शुरु होकर सहारनपुर तक ये रोड जो जाता है। राजस्व विभाग के अनुसार

इसकी जो चौड़ाई है वो 66 फुट है। मास्टर प्लान के अंदर ये डेढ़ सौ फुट का रोड प्रस्तावित है। मगर वर्तमान में इस रोड की चौड़ाई 40 फुट के आसपास है जिसके कारण से लोगों को आवाजाही में परेशानी होती है, एंबुलेंस निकलना भी बड़ी मुश्किल हो जाता है और हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। मेरा आपसे अनुरोध है कि माननीय पीडब्लूडी मंत्री जी के संज्ञान में ये लाया जाए और लोनी रोड को जल्द से जल्द चौड़ा किया जाए ऐसा मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री प्रद्यूम्न सिंह राजपूत।

श्री अभय वर्माः आधा घंटा 280 बढ़ा लें ताकी अपने..

माननीय अध्यक्षः नहीं ऐसा है कि 280 का समय तो एक घंटा ही रहेगा लेकिन 5-7 मिनट तो इसको चलने देंगे।

श्री अभय वर्माः अध्यक्ष जी 15 तक जिनके लॉटरी लग गये हैं बहुत मुश्किल से लॉटरी में आता है 15 तक जितना समय लगे उतना दे दें प्लीज मेंबर्स बड़े मेहनत से लगाते हैं, बहुत मेहनत से नंबर आता है।

माननीय अध्यक्षः अच्छा तो इसमें न संक्षिप्त रखें तो मुझे लगता है अगले 15 मिनट में सब हो जाएगा। तो इसमें माननीय सदस्य श्री प्रद्यूम्न सिंह राजपूत जी।(अनुपथित) माननीय सदस्य श्री अजय महावर जी।

श्री अजय महावरः धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने 280 में बोलने का मौका दिया। मेरे यहां पर घोंडा विधानसभा में पार्किंग की एक बड़ी समस्या है। दिल्ली में अभी सबसे ज्यादा जिस प्रकार सीवर-पानी की समस्या है तो उसके अलावा अगर देखें तो पार्किंग और जाम की भारी समस्या है। 90 परसेंट से ज्यादा व्हीकल्स वो सड़कों पर गलियों में खड़े होते हैं दोनों साइड खड़े हो जाते हैं और उसका आने-जाने का रास्ता लगभग बहुत दिक्कतों में आता है और जिसके कारण आए दिन झगड़े, मारपीट, सर फुटव्वल तक की नौबत आ रही है जो थाना तक पहुंचती है। पिछले सदन के दौरान भी मैंने एक आवेदन किया था ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जी को भी की हमारे यहां दिल्ली सरकार ने पिछली ने कहा था की कुछ मल्टी लेवल पार्किंग हम बनाएंगे तो हमारे यहां एक मल्टी लेवल पार्किंग की बेहद आवश्यकता है और मेरा एक और सुझाव सरकार को था की जो यमुना विहार डिपो है उस डिपो कई एकड़ में फैला हुआ है लेकिन अंदर से उस डिपो का कोई ऑपरेशनल पार्ट नहीं है वहां से कोई बस नहीं चलती वो सिर्फ कुछ सौ बसों का पार्किंग स्लॉट बना हुआ है तो जब आलरेडी डिपो पार्किंग स्लॉट बना हुआ है तो उसी पर मल्टी लेवल पार्किंग बना दिया जाए नीचे बस पार्किंग का ही तो काम हो रहा है उसके ऊपर कई मंजिल बन जाएंगी तो हजारों गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी उससे काफी राहत मिलेगी। डीडीए की भी पार्किंग लैंड यूज वाले प्लॉट हैं जिसको पीपी मॉडल पर डवलप किया जा सकता है क्योंकि डीडीए बनाता नहीं है और

कोई सीधा वहां पर आता नहीं है तो मेरा आग्रह है कि दिल्ली सरकार हमारे यहां की इस समस्या को समझते हुए यमुना विहार में जो डिपो है और यमुना विहार में एमटीएनएल ग्राउंड में जो डीडीए का मार्किट है एमटीएनएल ग्राउंड के नाम से उसमें एक बड़ा मल्टी लेवल पार्किंग का प्लॉट है। इसके अलावा भी अन्य प्लॉट वहां उपलब्ध हैं जो डीडीए के माध्यम से उन्हें लेकर के उसको डवलप कर सकते। पार्किंग की आप अगर अध्यक्ष जी आपके माध्यम से अगर मंत्री जी को कहें तो मेरे यहां एक बड़ी समस्या साल्व हो जाएगी हम इसके लिए सदैव आपका आभारी रहेंगे।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री प्रद्यूम्न सिंह राजपूत।

श्री प्रद्यूम्न सिंह राजपूतः अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से दिल्ली की माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जब देश में आपातकाल का काला अध्याय लिखा गया था तो पूरे देश में तत्कालीन निर्दयी सरकार के खिलाफ जन आन्दोलन चला था। लोग जेल गए उनके परिवार सड़कों पर आ गए बच्चों की पढाई छूट गई। आन्दोलनकारियों की नौकरी छूट गई। काम धंधे बन्द हो गए। माननीय अध्यक्ष जी, आपातकाल का काला अध्याय समाप्त होने, लोकतंत्र बहाल होने पर इन प्रताड़ित आन्दोलनकारियों को विभिन्न प्रदेशों जैसे हरियाणा, राजस्थान व अन्य राज्यों में मासिक पेंशन देने की योजना लागू की गई थी। किन्तु अध्यक्ष जी दिल्ली में अभी

तक इन जो लोकतंत्र के प्रहेरी है जिनको कोई पेंशन नहीं दी गई इनमें से काफी लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है लेकिन इनके परिवारों को यातना सहनी पड़ी। अध्यक्ष जी मेरा अनुरोध है दिल्ली में इन आन्दोलनकारियों के लिए समुचित मासिक पेंशन लागू की जाए। आपने बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री संजय गोयल जी।

श्री संजय गोयलः माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे अवसर प्रदान करने के लिए। माननीय अध्यक्ष जी मेरी विधान सभा में राशन कार्ड को लेकर आज एक विषय मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। मेरी विधान सभा में कार्ड होल्डर की संख्या 21 हजार 98 है और कार्ड मैम्बर्स जो है जिसमें 89 हजार 198 हैं। लगभग 30 परसेंट क्योंकि मेरी विधान सभा में गरीब लोग ज्यादा रहते हैं। झुग्गी बस्ती भी है और below poverty line के लाईन के सदस्य ज्यादा रहते हैं। जो पेंडिंग हमारे तीन-तीन साल से चार-चार साल से जो राशन कार्ड बनने है वो अभी तक पेंडिंग हैं। पेंडिंग होने के नाते जो वहां पर पीआरओ बैठते हैं जिस तरह से उनको प्रताडना दी जाती है। क्योंकि गरीब लोग है उनकी कोई सुनता नहीं है और पिछली सरकार ने लगातार जिस तरह से मुद्दे पिछली सरकार के सामने सभी मीडिया के माध्यम से आये किस तरह से राशन मंत्री ने इस तरह का व्यवहार किया। ऐसे व्यवहार आज के वो अधिकारी करते हैं और वो रिश्वत मांगते हैं और साथ में जो नये राशन कार्ड हैं वो 18 सौ पेंडिंग राशन कार्ड पैंडिंग पड़े

हुए है पिछले चार साल से और साथ में जो नए नाम ऐड होने है लगभग वो 14 सौ पड़े हुए हैं। पॉलिसी है कि पहला राशन कार्ड की डेफिशियेंसी खत्म करके तभी दूसरा राशन कार्ड आयेगा। यदि पहली कार्ड को ये रिजक्ट किया जाता है तो उसका नम्बर 14 सौ के बाद में 1401 नम्बर काउंट होता है। जो कि बहुत गलत है। ये गरीब लोग है और ये गरीब होने के नाते इनको अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए जो पीआरओ जो होना चाहिए। मेरा तो माननीय मंत्री जी को सुझाव है वहां एक सीसीटीवी कैमरा जो वहां अधिकारी बैठते हैं रिस्पशन पर वो होना चाहिए। जिससे कि उसके व्यवहार को देखा जाए किस तरह से वो व्यवहार करते हैं। बार-बार दौडाते हैं पेपर के नाम पर और दूसरी बात क्योंकि आज दिल्ली के अंदर मिनिमम वेजिज एक्ट जो है लागू है। वो 18 हजार रूपये का है। लेकिन आज below poverty line आपके आठ हजार मात्र साढ़े आठ हजार रूपये यदि आपकी इन्कम है तो आपको वो राशन कार्ड बनेगा। तो इसीलिए इन दोनों में देखिये कितना डिफरेंस है और जो 18 हजार मिनिमम वेजिज एक्ट है उसके अंदर भी आपके वो परिवार अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाता क्योंकि कमाने वाला एक होता है तो इसीलिए इस पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। below poverty line जो है जो इसका आवेदन है एक लाख रूपये का जो सर्टिफिकेट है इसको भी हमको बढाना चाहिए। और साथ में जो क्लीयरेंस है पेंडिंग जो क्लीयरेंस है उस पेंडिंग क्लीयरेंस को रिजेक्ट ना करके जो दूसरे

अन्य है कि एक खत्म एक को पहले करेंगे क्लीयर फिर दूसरा तब आयेगा वो पॉलिसी को भी अपना चेंज करना चाहिए और साथ में ही हमारे जितने पेंडिंग राशन कार्ड है वो तुरन्त के तुरन्त अप्लाई करें। क्योंकि अब देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय मोदी जी पूरे देश के अंदर सभी को राशन फ्री दे रहे हैं तो उनकी सरकार ने नहीं दिया तो इसी लिए जब राशन फ्री मिल रहा है तो राशन कार्ड की पेंडेंसी जीरो होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।

माननीय अध्यक्षः श्री विरेन्द्र सिंह कादियान(अनुपस्थित)। विपक्ष के सदस्य लगाकरके और गायब हो जाते हैं, भाग नहीं लेते चर्चा में। अभी कार्यवाही भी दस के लगभग दस के खिलाफ़ की गई थी निष्कासन की। लेकिन उसके बाकी के कोई सदस्य यहां पर उपस्थित नहीं है। अब मैं माननीय सदस्य श्रीमती शिखा राय को।

सुश्री शिखा रॉयः धन्यवाद अध्यक्ष जी मुझे ये मौका मिला। अध्यक्ष जी, मेरे ग्रेटर कैलाश विधान सभा में आउटर रिंग रोड लगती है। उसके ऊपर ग्रेटर कैलाश-2 को जाने का जो एकमात्र रास्ता है, उस पूरे जीके-2 के एन्ट्री एक ही स्थान से होती है जो आगे चल करके पूरा अलकनंदा अपार्टमेंट्स यानि एक पूरा वार्ड जो चितरंजन पार्क है उसका एन्ट्री प्वाइंट एक ही है। उस आउटर रिंग रोड पर सावित्री फ्लाई ओवर के नाम से एक फ्लाई ओवर है जो वन वे है। जब से ये बना है faulty इसका डिजाईन उस समय हुआ कि उसको केवल एक जो है एक तरफ से जाने का रखा

गया। यानि नेहरू प्लेस से आते हुए आप चिराग दिल्ली की तरफ जाते हैं towards airport तो वो जाने है लेकिन उधर से आने का नहीं बना हुआ है। जिस के कारण हर रोज पीक ऑवर्स के अलावा भी वो एक ऐसा bottleneck का प्वाइंट बनता है जिससे किउ जाम पूरे रिंग रोड में पीछे तक उसका असर होता है कि शाम को पीक आवर्स में वो रोड एयरपोर्ट तक जाम हो जाती है। खास कर जब दूर्गा पूजा के दिन होते हैं आप जानते है चितरंजन पार्क एक ऐसा क्षेत्र हैं जिसमें दूर्गा पूजा के पांच दिन बहुत ही भंयकर जो है वो जाम इस लिए होता है क्योंकि बहुत सी दुनिया पूरी दिल्ली भर से उस क्षेत्र में पूजा के लिए आती है। उस समय तो स्थिति ऐसी होती है कि तीन तीन घंटे उस ग्रेटर कैलाश-2 की एंट्री पर residents को लग जाते है कि वो उसको क्रॉस कर सकें। इसलिए मेरा माननीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब से ये आग्रह है कि पिछले पन्द्रह सत्रह सालों से एक ऐसी समस्या ये मुहंबांहे खड़ी है उस क्षेत्र में जिसका समाधान वहां के लोगों को नहीं मिल रहा है। ये केवल ग्रेटर कैलाश नहीं पूरे commuters जो उस रोड पर निकलते हैं उस रिंग रोड में, उसके लिए है। मेरा निवेदन रहेगा माननीय मंत्री जी से कि इस साल की परियोजनाओं में इस फ्लाईओवर को अगर डबल लेन करने का वो प्रावधान इसमें देते है, उसको योजनाओं में लेते हैं तो ये उस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा एक देन होगी जो ग्रेटर कैलाश को ही नहीं मैं उस रोड पर

चलते हुए प्रत्येक commuter के लिए भी एक उनको inconvenience जो होती है उसका समाधान होगा। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री सतीश उपाध्याय (अनुपस्थित)। माननीय सदस्य श्री अभय वर्मा जी।

श्री अभय वर्मा: धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि विकास मार्ग से जाते वक्त लक्ष्मी नगर मैट्रो स्टेशन से जो मदर डेयरी रोड शुरू होता है उसके कॉर्नर पर हजारों की संख्या में बस के इंतजार में लोग खड़े रहते हैं। वहां पर बस शेल्टर नहीं होने के कारण बारिश में और तपती धूप में लोगों को बहुत परेशानी होती है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह कर रहा हूं कि उस कौने पर जो लक्ष्मी नगर मैट्रो स्टेशन है जहां से मदर डेयरी शुरू होता है जो ऑलरेडी बस स्टेंड के रूप में इंगित है लेकिन बस स्टॉप वहां पर शेल्टर नहीं लगाया हुआ है। तो मेरा सिर्फ आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह है कि वो बस शेल्टर लगाएं ताकि लोगों को धूप से बचने का मौका मिले और बारिश के समय में भी बहुत दिक्कत होता है। अध्यक्ष जी वहां पर बहुत सारी दुकान भी है जिसके कारण लोगों को परेशानी भी होती है कि वो खड़ा कहां हो। क्योंकि सारी बसें विकास मार्ग से जब मदर डेयरी की तरफ मुडती है तो वहीं पर रूकती है। मैं ये हजारों की संख्या कह रहा हूं। शाम को कभी आपको फोटो दिखाऊंगा तो आपको लगेगा इतने सारे लोग बस का इंतजार करते हैं। तो इसलिए

वो बहुत महत्वपूर्ण जगह है। डीडीसी जितना जल्दी हो सके वहां बस शेल्टर बना दे ताकि वहां लोगों को ठहरने, बैठने और धूप और बरसात से बचने का मौका मिल सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री सतीश उपाध्याय।

श्री सतीश उपाध्यायः धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी का ध्यान एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार द्वारा ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के तहत जरूरतमंद बच्चों को स्कूल में प्रवेश देने का प्रावधान है। अब इस प्रावधान में जो उन्होंने नियम लिखे हुए है उसमें लिखा हुआ है बीपीएल/एएवाई राशन कार्ड, फूड स्क्योरिटी कार्ड, issued from GNCT of Delhi are eligible under economic weaker section for applying in these private unaided recognized schools for admission of their ward under economic weaker section category. अब सकूर्लर के प्वाइंट नम्बर-11 ए में दिया गया है कि बीपीएल/एएवाई, राशन कार्ड फूड स्क्योरिटी कार्ड धारको को स्कूल में प्रवेश देने का प्रावधान है। हमारे संज्ञान में ये बात आई है कि फूड स्क्यूरिटी कार्ड के ऊपर लोगों को प्रवेश देने से मना किया जा रहा है। उसको वो प्रवेश नहीं दे रहे हैं और जब लोग जाते हैं तो उनको इसके लिए मना करते हैं। तो इसका संज्ञान आदरणीय शिक्षा मंत्री जी को इसमें लें और एक आदेश ईशू करें कि फूड स्क्योरिटी कार्ड जो कि इसमें ऑलरेडी दिया है लेकिन उसके बाद भी लोगों को वीकर सैक्शन में इकोनोमिक वीकर सैक्शन में प्रवेश

नहीं दिया जा रहा। बल्कि कुछ टाउट्स हैं जो फर्जी सर्टिफिकेट बना करके जो लोगों को परेशान करके, लोगों से पैसा ले करके और उनको प्रवेश दिलाने का काम करते हैं। लेकिन जिन लोगों को मिलना चाहिए उनको डिनाई किया जा रहा है इस पर संज्ञान लिया जाये, इस मामले पर उचित कार्रवाही भी की जाए।

माननीय अध्यक्षः सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात पर चर्चा जारी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री, वित्तमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2025 को प्रस्तुत 31 मार्च 2021 को समाप्त हुई वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के दिल्ली में वाहन वायु प्रदूषण रोकथाम और श्मन पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 2) पर आगे चर्चा होगी। मैं आज माननीय सदस्य आपके समक्ष फिर ये विषय रखना चाहूंगा कि सीएजी रिपोर्ट वर्षों तक पूर्व सरकार ने दबाकर रखी और पूरे सदन में पूरे 5 वर्ष तक एक भी रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं रखी गयी और अगर दस वर्ष का कार्यकाल लगाया जाए तो एक भी पीएसी ने रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं रखी और आठवीं विधानसभा में जब सीएजी की रिपोर्ट्स लायी जा रही हैं तब भी विपक्ष उस चर्चा से नदारद हैं, चर्चा से भाग रहा है यानि की भ्रष्टाचार के संगीन मामले और अव्यवस्था और कुशासन के प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ सीएजी की रिपोर्ट यहां है, लेकिन बहुत ही पीड़ादायक है कि सिर्फ सीएजी की रिपोर्ट की चर्चा से भागने के लिए तरह तरह से

षडयंत्र करके सदन की कार्यवाही को बाधित किया जाता है और आज भी बाधित करने वाले सदस्यों की संख्या जिनपर कार्यवाही हुई है उसके अलावा विपक्ष की एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी भी है जिन पर कोई चेयर से निर्देश नहीं हुआ था निष्कासन का लेकिन वो भी सदन में इस महत्वपूर्ण मौके पर उपस्थित नहीं हो रहे हैं। ये दिल्ली की जनता देख रही है। मैं सत्ता रूढ़ दल के सदस्यों को बधाई दूंगा कि वो हर चर्चा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और आज भी लगभग अभी तक 25 सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखें हैं। जिसमें से सत्ता रूढ़ दल के सदस्यों ने जहां 25 के करीब सदस्यों ने विचार रखे हैं वहीं विपक्ष का एक भी सदस्य सदन की कार्यवाही में सहयोग करने के लिए यहां पर उपस्थित नहीं हुआ है। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले माननीय सदस्य श्री संजय गोयल जी चर्चा को शुरू करेंगे।

सीएजी रिपोर्ट (वाहन वायु प्रदूषण) पर चर्चा

श्री संजय गोयलः माननीय अध्यक्ष जी, सीएजी रिपोर्ट पर आपने बोलने का मौका दिया इसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से पिछली सरकार ने अनियमितताओं की, अव्यवस्थित अनियमितताओं को जो व्यवस्थित करना चाहिये थे केजरीवाल सरकार को एक एक डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ देखने को नहीं मिलता। और जिस तरह से एयर पॉल्यूशन दिल्ली के अंदर बढ़ता चला गया क्योंकि लगातार 2015 से 2025 तक केजरीवाल जी की सरकार रही जो काम करने दे वो काम किये नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार में

लिप्त रहे कहां से पैसे को लिया जाये और कहां से पैसे को अन्य राज्यों के चुनावों में खर्च किया जाये उस पर ध्यान रहा और किसी भी इनके जो मंत्री थे वो भी इसमें अपने केजरीवाल जी को खुश करने में लगे रहते थे। इसी वजह से दिल्ली के अंदर जो परेशानी बढ़ती चली गयी और एयर पॉल्यूशन इतना हो गया कि हमारे जो दिल्ली के निवासी है ये मजबूर हो गये इन तीन महीने मे सोचने के लिये कि अन्य राज्यों में जाया जाये और वहां हम वहां रहें और दिल्ली अब रहने के लायक नहीं बची है। और दूसरी तरफ हमारी केंद्र की मान्य मोदी जी की सरकार जिन्होंने पूरी दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन कम हो उसके लिये अनेकों अनेक व्यवस्थायें की, इस्टर्न पेरीफेरल हो या वेस्टर्न पेरीफेरल हो चाहे दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेस वे हो, चाहे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे हो और चाहे अभी दिल्ली का देहरादून एक्सप्रेस वे तैयार होने की तैयारी पर है अगले तीन महीने में ये चालू हो जाएगा और चाहे यमुना के दोनों तरफ 11 बड़े-बड़े पार्क एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए माननीय मोदी जी की सरकार के माध्यम से, डीडीए के माध्यम से यहां बनाए गए, लेकिन दिल्ली की सरकार ने चोर सरकार ने कोई भी काम नहीं किया। मैं जब इस रिपोर्ट को पढ़ रहा था अनेकोनेक विषय मैंने देखने को मिले और इसमें सीधे-सीधे कहा गया कि पार्किंग की व्यवस्था दिल्ली सरकार को करनी चाहिए थी, दिल्ली के अंदर एलीवेटेड पार्किंग व्यवस्था की जा सकती थी, अनेकोनेक डीडीए के ग्राउंड, डीडीए के मैदान पड़े हुए थे जिन पर उनका

सदुपयोग करके पार्किंग व्यवस्था की जा सकती थी क्योंकि लोगों को मजबूर होने के लिए सड़क पर अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए मजबूर होना पड़ा जिसकी वजह से सड़कों पर ट्रैफिक जाम होता था और ट्रैफिक जाम होने की वजह से माननीय अध्यक्ष जी वो पॉल्यूशन का लेवल बढ़ जाता था। ऐसे ही वाहन मुक्त ग्रीन जोन बनाना था वो भी इन्होंने इस पर भी विशेष ध्यान नहीं दिया और दिल्ली की यदि हम बात करें गैर मोटर चालित परिवहन, जोकि तैयार करना था क्योंकि दिल्ली 1483 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से केवल एनडीएमसी क्षेत्र में है। न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी जो क्षेत्र है उसमें से मात्र 40.27 किलोमीटर 3 परसेंट तक को ही गैर मोटर चालित क्षेत्र घोषित किया गया, जबकि दिल्ली के अंदर अनेकोनेक जगह पर गैर मोटर चालित परिवहन व साईकिल की व्यवस्था के माध्यम से या पैदल चलने के लिए क्षेत्र को नियमित किया जा सकता था। साथ में माननीय अध्यक्ष जी जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं ट्रैफिक सिग्नल दिल्ली के अंदर 2020 तक दस सौ उन्नतीस ट्रैफिक सिग्नल थे और दस सौ अठारह कांउट डाउन टाइमर थे, जिनमें से 40 परसेंट कांउट डाउन टाइमर वर्क में नहीं थे जिसकी वजह से चौराहों पर जाम लगता था और उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन भी बढ़ा और जग-जागरूकता अभियान इन्होंने चलाना था, केवल 11 दिन प्रिंट में सिर्फ आपके चलाया गया कि किस तरह से पॉल्यूशन को कम करना है, दिल्लीवासियों का क्या दायित्व है इस विषय में भी बताया नहीं गया, सिर्फ चौराहे पर

अपने जो कार्यकर्ता थे आम आदमी पार्टी के उनको खड़ा कर दिया जाता था, ये काम उन्होंने किया। एक उनको, क्योंकि पेमेंट भी करनी होती थी क्योंकि कार्यकर्ता को खुश करना था उनको। और एक नाम पर वाहनों के पंजीकरण संख्या पर प्रतिबंध, एक नाम पर ज्यादा मान लीजिए मेरे नाम पर एक से ज्यादा पंजीकरण की व्यवस्था प्रतिबंध लगाना था क्योंकि आज दिल्ली में एक-एक के पास 4-4 वाहन हैं, अनेकों अनेक काम कर रहे हैं उस पर भी इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, उसका, प्रतिबंध के साथ-साथ उच्च पंजीकरण शुल्क और सड़क कर लगाना था लेकिन उस पर भी ध्यान नहीं दिया।

साथ में कलस्टर की जो खराब बसें थी 1189 बसों को जोकि 30 मिनट में होना चाहिए था सड़क से हटाने का, लेकिन वो दो से चार घंटे तक, पांच घंटे, छः घंटे में सड़क से हटी जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हुआ। ऐसे ही डीटीसी की 139 बसों के साथ-साथ 3 लाख 57 हजार खराब बस जो है, ये जो हटाने का लक्ष्य था वो भी 30 मिनट से ज्यादा रहा, वो भी दो से चार घंटे रहा जिसकी वजह से रोड पर ट्रैफिक जाम रहा। 2021 तक क्योंकि रजिस्टर्ड व्हीकल 1 करोड़ 30 लाख थे और उस पर भी कोई व्यवस्था नहीं की क्योंकि डीजल के व्हीकल दिल्ली में बार-बार बढ़ते रहें।

दिल्ली में जो एंट्रेंस है पर ट्रांसपोर्ट नगरों का विकास करना था। दिल्ली के अंदर 128 आपके एंट्रेंस पॉइंट हैं जिस पर ट्रांसपोर्ट

नगर हमको व्यवस्थित करने थे उस पर भी दिल्ली की सरकार ने कोई काम नहीं किया पिछली वाली सरकार ने।

साथ में जो ई-व्हीकल बोर्ड बनाना था, ई-व्हीकल आपके सैल बनाना था उसको गठन नहीं किया जबकि उनको गठन करना चाहिए था जिसके लिए 50 करोड़ का बजट में प्रोवीजन किया गया था लेकिन वह अनयूटिलाइज रह गया। और एक बार 3 करोड़ 74 लाख रुपये के करीब इन्होंने एक प्रोवीजन भी किया जिसका भी उपयोग नहीं हुआ जिसकी वजह से आपके ई-व्हीकल दिल्ली के अंदर तादाद नहीं बढ़ी क्योंकि इनको सारा चेक करना था, कितनी कहां-कहां, कैसे-कैसे ई-व्हीकल्स को बढ़ाया जाए। और साथ में सितंबर में, सितंबर में 2020 में 1 लाख 17 हजार ई-व्हीकल हुए और वो भी चार्जिंग स्टेशन की कमी होने की वजह से उनको भी ई-व्हीकल खरीदने के लिए उनको सोचना पड़ा कि हमने ये ई-व्हीकल क्यों खरीदे, ये चार्जिंग स्टेशन लगाने का काम भी उन्होंने करना था लेकिन वो नहीं कर पाये।

जो 128 आपके प्रवेश स्थल हैं जिन पर केवल मात्र 7 स्थानों पर प्रवर्तन टीम, एनफोर्समेंट जो टीम है जो चेक करने की थी लगाई गई और मात्र उसमें 292 कर्मचारी थे और जोकि सिर्फ पैसे कलेक्ट करते थे और पैसे कलेक्ट करके केजरीवाल को देते थे और केजरीवाल फिर दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ता था, वो. और भ्रष्टाचार का काम करता था जिसमें से 80, आपके 13 प्रवेश स्थलों पर 80 परसेंट कमर्शियल व्हीकल दिल्ली में आते थे जिनको

कई बार एलाऊ नहीं होता था दिल्ली में आने के लिए और साथ में उनके जो पेपर्स चेक करने होते थे कि इसके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है या नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनके अधिकारी सिर्फ भ्रष्टाचार करते थे और एक से 5 हजार, 10 हजार, 20 हजार, 50 हजार रुपये, लाख रुपये तक की रिश्वत लेते थे।

इसी तरह से प्रणाली बिल्कुल ठीक नहीं थी। जब्तीकरण जो स्थल थे उसकी क्षमता मात्र दिल्ली में 4 हजार थी उस स्थान की क्षमता और लेकिन आपके 41 लाख व्हीकल 2021 तक, उनको जब्त करना था, 2018-19 में 36.11 हो गए, जिसमें 2 लाख 26 हजार को अपंजीकृत किया गया कि ये रोड पर चलने के लिए नहीं हैं जबकि 36 लाख को अपंजीकृत करना चाहिए था मात्र .06 परसेंट। ऐसे ही 2019-20 में 38.69 लाख व्हीकलों को आपके अपंजीकृत करना चाहिए था, मात्र 50 हजार व्हीकल अपंजीकृत किये गये, जोकि मात्र .01 परसेंट है। ऐसे ही 2020-21 में 41.55 लाख आपके अपंजीकृत करने थे, मात्र 22 हजार, सिर्फ मात्र 22 हजार, .01 परसेंट अपंजीकृत किये गये।

इसी तरह से बुराड़ी जो निरीक्षण केंद्र था जो कि 90 परसेंट दिल्ली के व्हीकल की फिटनेस करता था, जहां आपके 800 वाहन प्रत्येक दिन, आपके कार्य दिवस, जो 300 कार्य दिवस के ऊपर प्रत्येक दिन करना था, एक इंस्पेक्टर 100 से 140 आपके वाहन को चेक करने का नियम था लेकिन वो इंस्पेक्टर्स आपके व्हीकल का फिटनेस करते थे मात्र 5 मिनट में, 5 मिनट से कम समय में

भी कैसे करते थे, हमें पता नहीं क्योंकि पैसे मिलते थे, पैसे लेकर सब फिटनेस हो जाती थी, इस वजह से भी पॉल्यूशन बढ़ने का एक कारण रहा।

इसी तरह से एक वाहन निरीक्षण इकाई जो स्वचालित थी और जोकि आपके झुलझुली में लगाई गई थी जहां 50 हजार व्हीकल को चेक करने का कार्य रखा गया था पूरे साल के अंदर और झुलझुली के अंदर 300 दिन में 167 वाहन प्रतिदिन चेक करने थे, मात्र एक साल 56, एक साल 75 और दूसरे साल जब उल्टा संख्या बढ़नी चाहिए थी मात्र 24, ट्वेंटी फोर वाहन पर-डे ही चेक हो पा रहे थे 167 में, जो झुलझुली में करोड़ों रुपए के स्वचालित निरीक्षण इकाई जो है आपके लगाई गई थी उसका भी सदुपयोग नहीं किया गया जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ा।

ऐसे ही साथ में ग्रामीण जो बसें चलती थी, ग्रामीण सेवा जो चलती थी, जो 6 हजार 153 थी उसमें से मात्र 34 सौ 76, दो महीने में एक बार चेक होनी चाहिए थी वो फिटनेस लेकिन वो दो महीने क्या साल में एक बार भी चेक नहीं होती थी तो स्थिति ऐसी थी कि टोटल मिलाकर पॉल्यूटेड धुंआ ही धुंआ, धुंआ ही धुंआ दिल्ली के अंदर कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, ये थी केजरीवाल की, जो पढ़े लिखों की सरकार थी, आईआरएस ऑफिसर थे, जो अपने आपको कहते थे कि हम दिल्ली को बेहतर कर देंगे लेकिन दिल्ली को लूटने में इन्होंने समय बर्बाद कर दिया और दिल्ली की स्थिति ऐसी कर दी कि सांस लेना दूर्भर हो गया है।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस रिपोर्ट पर ये ही कहूंगा कि इसको तुरंत इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो अपने आपको बड़े-बड़े ऑफिसर्स कहते हैं, जिनकी डयूटी थी, ठीक है सरकार सोई हुई थी लेकिन आपका काम था दिल्ली की व्यवस्था को सही करने का, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री ओम प्रकाश शर्मा जी।

श्री ओम प्रकाश शर्माः धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, बोलने का मन तो बहुत है लेकिन हाउस सारा खाली है, न कोई विरोध करने वाला है और न समर्थन वाला है।

माननीय अध्यक्षः समर्थन वाले तो हैं।

श्री ओम प्रकाश शर्माः तो आज मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आपने मुझे कैग की पर्यावरण की रिपोर्ट के ऊपर बोलने का मौका दिया। मैं बड़े बुजुर्गों से अकसर सुनता रहा हूं, अध्यक्ष जी मैं आपका ध्यान चाहूंगा। अध्यक्ष जी कार और सरकार दारू पीकर नहीं चलानी चाहिए। अगर कार और सरकार दारू पीकर चलाई जाएगी तो उसके गम्भीर परिणाम होंगे। जब दारू पीकर सरकार चलेगी तो जेल भी जाना पड़ेगा और समय-समय पर जो ऑडिट होता है वो भी नहीं होगा। जो कैग रिपोर्ट आएगी उसके पैरे बनने तो दूर उस कैग रिपोर्ट को छुपाकर रखा जाएगा और इन सबके बाद जब सरकार

बदलेगी, तो उस कैग रिपोर्ट का जो खुलासा होगा उससे ये पता लगता है कि किस प्रकार पिछली सरकारों ने दिल्ली की जनता की सांस, सांस एक ईश्वर प्रदत्त ऐसी चीज है जो रिदम है, जो एक मधुर संगीत की तरह आदमी सांस लेता है, उस सांस को जब चीत्कार में बदलने का काम इस आप सरकार ने किया, इसके लिए इनकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। इन्होंने लोगों की सांसों के साथ खिलवाड़ किया है। अभी बहुत से आंकड़े मुझसे पूर्व सदस्यों ने दिये, पर्यावरण में कितना प्रदूषण है उसको नापने के जितने इन्स्ट्रूमेंट थे, वो सब जितने भी instrument थे वो सब नकली थे, जाली थे और जिस पैमाने का उनका होना चाहिए उस पैमाने के नहीं थे, तो प्रदूषण नापने का कोई अथोंटिक पैमाना पिछले 10–12 साल से दिल्ली में नहीं रहा। फिटनेस सर्टिफिकेट डीटीसी की बसें हों, चाहे प्राइवेट व्हीकल हों, सब इन्होंने धल्लू धारा करके, क्योंकि डीटीसी की बसें ये खरीद नहीं पाए, पुरानी जो डीजल की बसें थी जिनसे प्रदूषण होता था, बसों के अभाव में उनको नकली फिटनेस सर्टिफिकेट देकर दिल्ली की सड़कों पर चलाया गया जिससे की दिल्ली का पर्यावरण और ज्यादा खराब हुआ। दिल्ली के बॉर्डर्स पर आईएसबीटी डेवलप करने थे, जिससे दूसरे स्टेट की सड़कें बॉर्डर तक रह जायें, दिल्ली में नहीं आएं, उन आईएसबीटी पर भी पुरानी सरकार काम नहीं कर पाई। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की यदि हम बात करें, बसें तो ये खरीद नहीं पाए, नकली फिटनस देते रहे। जब–जब नई बसें खरीदने का मामला

आया तो उसमें आकंठ भ्रष्टाचार में ये डूब गए। बसें खरीदना तो दूर जिन बसों को मोटरसाइकिल को, कार को जब हम खरीदते हैं, कहीं तीन साल, कहीं दो साल, कहीं 5 साल की वारंटी होती, इन्होंने जिस दिन बस को खरीदने का मसौदा तैयार किया उसी दिन से एएमसी देने का जो प्रावधान किया, इसके लिए आप और हम सब मिलकर, हमने पोस्ट–टू–पीलर इनकी कम्पलेंट की और ये जो बात आज हो रही है कैग की रिपोर्ट, कुछ लोग कहते हैं कि आपने कैग की रिपोर्ट पहले पढ़ ली इसलिए आप बोल रहे हैं। कैग की रिपोर्ट किसी का रहस्योद्घाटन नहीं कर रही है। हम इस सदन में जब हम विपक्षी थे, विपक्ष के सदस्य होने के नाते तब की तत्कालीन सरकार के काले कारनामों को जो उजागर करते थे, उन काले कारनामों के ऊपर कैग ने मोहर लगाई है इसके अलावा कैग रिपोर्ट और कुछ नहीं है। बसें आप ला नहीं सके, मैट्रो के विस्तार में आप बाधक बने, मोनो रेल का आपको विचार नहीं आया, इलैक्ट्रीक ट्रोली आप समझ नहीं पाए क्या चीज है और यदि मैं इवी की पोलिसी की बात करूं तो एक साल केवल आपने बात करके, ईवी की पोलिसी को भी डिस्कार्ड कर दिया जिससे कि दिल्ली में ईवी की जो इलैक्ट्रीकल कारों का जो आज जितनी मात्रा में सड़कों पर होनी चाहिए उतनी सड़कों पर नहीं है, इसका कोई जिम्मेदार यदि है तो पिछली सरकार की ईवी पोलिसी है। अब हम बात करें, एक जांच केंद्र में 76 हजार 865 मामले टैस्ट कर दिए। अरे भाई, एआई आ गया एक मिनट के अंदर एक टैस्ट आप

कर नहीं सकते। पैसे लेकर सर्टिफिकेट बांटने और बेचने का काम आपने किया। झुलझुली में स्वचालित वाहन निरीक्षण का जो काम था 167 की जगह केवल 24 गाड़ियों का हुआ और बुराड़ी में तो कमाल ही हो गया कोई इक्यूपमेंट नहीं है इंसपैक्टर ने देखा, दलाल ने पैसे दिए और उसने कहा फिटनैस सर्टिफिकेट ओके। चार्जिंग के प्वाईंट का नितांत अभाव है। वायु गुणवत्ता के लिए भारी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ। गाड़ियां चलाईं, स्मॉग टावर लाए इस मौके पर मैं एक बात और कहना चाहता हूं आज से दस बारह साल पहले जब हम अखबार पढ़ते थे तो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानियों के अंदर दिल्ली की राजधानी का शुमार होता था और दूसरे नंबर पे जो राजधानी विश्व की आती थी वो चीन की होती थी। चीन ने पर्यावरण पर पिछले पांच सात साल में जो काम किया उन्होंने अपनी स्थिति सुधार ली लेकिन ये भ्रष्टाचारी सरकार smog tower लगाए उसमें पैसे खा गए, Odd Even के अंदर अपने कार्यकर्ताओं को लगाया उनके पैसे खा गए। लोगों की सांस के उपर जहरीली गैसें छोड़ने से लोगों को हृदय रोग हो गए हैं, फेफड़े खराब हो गए, किडनी खराब हो गई। तो ये कैसी सरकार थी जो सांस से लेकर हर अंग प्रत्यंग को जिसने विकृत करने का कार्य किया ऐसी सरकार की निंदा इस सदन में की जानी चाहिये। शीशे की नाप का कोई पैमाना पर्यावरण में कितना शीशा है उसको नापने का कोई इंस्ट्रूमेंट न इनके पास पहले था न आज है। पराली घोल की कहानी आपने सुन ही ली है 40 हजार की पराली और करोडों का

विज्ञापन। डाटस संकलन में भी इन्होंने बेईमानी की। जो आदमी बीमारी को ढूंढने का सही तरीके से प्रयास नहीं कर रहा वो आदमी उस मर्ज की दवाई नहीं दे सकता ये मेरा कहना है। तो आज दिल्ली में जो सांसों के उपर जो प्रतिबंध लगाया लोगों के अंग प्रत्यंग खराब करने का जो कार्य चल रहा है दिल्ली की जनता दिल्ली की सरकार से बहुत उम्मीदें करती है मैं ये समझता हूं कि भ्रष्टाचारियों ने दारू पीकर जो दिल्ली का नाशकिया है इन सब चीजों को संज्ञान में लेते हुए दिल्ली की जनता को खुली हवा में सांस लेने का मौका मिले उसके फेफड़े, उसकी लीवर उसका हार्ट स्वस्थ रहे, इसके लिये हमारी सरकार पूरी ताकत के साथ काम करेगी और दिल्ली को मेरी दिल्ली प्यारी दिल्ली स्वच्छ दिल्ली और दिलवालों की दिल्ली बनायेगी। जय हिंद जय भारत।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री अजय महावर।

श्री अजय महावरः धन्यवाद अध्यक्ष जी सीएजी रिपोर्ट पर आपने बोलने का अवसर दिया मारवाह जी का टाईम भी मुझे दे दिया जाये।

माननीय अध्यक्षः इनके बाद आपका।

श्री अजय महावरः अध्यक्ष जी ओम प्रकाश जी अभी कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि पिछले सालों में जब हम लोग विपक्ष में बैठकर के आपके नेतष्त्व में भी बहुत सारी बातें जब सदन में पिछली सरकार की कारगुजारियों को रखा प्रदूषण के

संबंध में भी तो वही डॉक्यूमेंट आज सही मायने में साबित हुआ कि हम सबकी एक एक बात ठीक थी। आदरणीय अध्यक्ष जी,

"पिछली सरकार ने दिल्ली का क्या हाल कर दिया
पिछली सरकार ने दिल्ली का क्या हाल कर दिया
हर इंसान का सांस लेना भी मुहाल कर दिया।"

आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली को क्या दिया जैसा मेरे साथियों ने भी बताया दिल्ली की सब से प्रदूषित राजधानी बना दी। सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि दिल्ली गैस चैंबर में तबदील हो गयी है अध्यक्ष जी। और पूरी दुनिया में दिल्ली चूंकि राजधानी है इसके कारण हमें शर्मिंदगी झेलनी पड़ी लेकिन इस सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी। प्रदूषण में पराली की 38 परसेंट हिस्सेदारी है। उस 38 परसेंट में 78 परसेंट मामला पंजाब का है। और जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनी थी पंजाब में तब तक ये सारा रोना धोना और सारा ठीकरा पंजाब पर फोड़ा करते थे। पराली के जब पिछले मामले हैं पिछले वर्ष भी 10,693 मामले आये पराली के जिसमें पंजाब का 4,394 मामला था। उससे पिछले साल 5,140 मामले पंजाब के आये और ये बार बार हरियाणा पे ठीकरा फोड़ते हैं। हरियाणा का मामला पराली का मात्र 870 आया। लेकिन जब से पंजाब में सरकार आयी इन्होंने सारा मामला डायवर्ट करने का प्रयास किया। ऑड इवन, रेड लाइट ऑफ-ऑन ये इनका भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया क्योंकि जैसा पिछले

साथियों ने कहा तखतियां लेकर खड़े कर कर करोड़ों की पेमेंट इन्होंने दे दी लेकिन उसका कोई हिसाब–किताब लेखा–जोखा जनता को नहीं दिया और वो सारी अनियमिततायें सीएजी की रिपोर्ट में आ रही हैं। वायो डि–कम्पोजर दवाई बनाई इन्होंने कहा कि पराली से खाद बना देंगे। पूरी दुनिया को बड़ी–बड़ी बातें की। उसका रिजल्ट भी सबने देखा कि 40 हजार की दवाई पहली बार बनाई जो 15 करोड़ का विज्ञापन और अगले साल 22–23 में इन्होंने 46 लाख रूपए की दवाई छिड़काव की और उसमें भी साढ़े सात करोड़ का विज्ञापन कुल मिलाकर के 23 करोड़ का विज्ञापन यानि एक करोड़ की भी दवाई नहीं और 23 करोड़ का विज्ञापन और रिजल्ट सबसे बड़ी बात है रिजल्ट सुनिये। एक छटांक भी खाद नहीं बनी उस दवाई से। ऐसी बेशर्म सरकार है इस पर तो कार्यवाही होनी चाहिए कि आखिर ये इतना बड़ा काम, इतना बड़ा घोटाला हुआ कैसे। दिल्ली उच्च न्यायालय की आगाज पर इन्होंने स्मॉक टावर लगाये। वो भी अपने आप इन्होंने संज्ञान नहीं लिया। 13 जनवरी, 2020 को माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया तब इन्होंने 23 अगस्त 2021 को एक एन्टी स्मॉग टावर लगाया कनॉटप्लेस में लागत 23 करोड़ रूपए। 40 पंखे बंद के बंद रिजल्ट जैसे खाद का जीरो रहा वैसे इसका भी जीरो। कोई असर नहीं हुआ इसका। इन्होंने कहा केजरीवाल जी ये ही सदन में खड़े होकर के कहते थे अरे हमें तो पता है हम कृत्रिम बारिश करायेंगे। हेलीकोप्टर से बारिश करायेंगे ये इस सदन में कहा है। क्या किसी ने हेलीकोप्टर देखा क्या

बारिश करते हुए। कैसा नकली आदमी था। इतना नकली आदमी मैंने अपने जीवन में नहीं देखा अध्यक्ष जी। इन्होंने कोई हेलीकोप्टर से बारिश नहीं कराई कोई कृत्रिम बारिश नहीं कराई और सिर्फ जुमले करते रहे। यहां भी किसी की कोई अकाउंटीबिल्टी नहीं जैसे खाद में नहीं, जैसे एन्टी smog टावर में नहीं। कोई अकाउंटीबिल्टी। अच्छा आजकल ये लोग क्या करते हैं। जब भी आती है कोई बात कहते हैं पटाखे बैन कर दो बस। क्योंकि इनको तो एक धर्म विशेष से नफरत लगती है। पटाखे बंद कर दो। एक दिन पटाखे जलते हैं उसी के पीछे लगे रहते हैं, जबकि ग्रीन पटाखों के लिए ना तो प्रोडक्शन के लिए, ना ट्रेडिंग के लिए कोई प्रोत्साहन देने का काम इन्होंने नहीं किया। वैसे तो एक विशेष धर्म में जब बकरा ईद बनाते हैं तो लाखों जानवर कटते हैं, क्या उससे प्रदूषण नहीं होता। Solid waste management में वो एक बड़ा रूकावट पैदा नहीं करता। वो करता है लेकिन उससे सरकार को क्या लेना देना क्योंकि उन्हें तो तुष्टीकरण की राजनीति ही करनी है। इन्होंने सौर ऊर्जा, commercial vehicle, electrical vehicle के प्रोत्साहन के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाये। सब विभागों में अनियमितता बनी रही और एक साथी कह रहे थे केंद्र सरकार का तो इस सदन को धन्यवाद करना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का और केंद्र सरकार का आज आपके माध्यम से अध्यक्ष जी हम धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरीफेरल रोड बनायी दिल्ली में अनेक हाईवेज बनाये, 1500 इलैक्ट्रीकल बसें देने का

काम किया और बांसेरा हो या असिता ईस्ट हो, वनस्थली होया बदरपुर का इफ्को पार्क हो ऐसे पर्यावरण के बड़े-बड़े काम केंद्र सरकार ने किये इतनी बसेज दीं इसके लिए इस सदन की ओर से नरेन्द्र मोदी जी का और केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं। लगभग डेढ़ हजार करोड़ का ग्रीन सेस टैक्स इन्होंने इकट्ठा किया पर खर्चा क्या किया, इकट्ठा किया रुपया खर्चा अट्ठन्नी भी नहीं और जो अट्ठन्नी थी उसमें से भी मैक्सीमम विज्ञापन ही विज्ञापन तो उन्होंने विज्ञापनों से ही फुर्सत नहीं थी। कल एक साथी कह रहे थे हमारे हरीश खुराना जी की आठ नौ सिगरेट, मैंने हिसाब लगाया जाकर घर में, अच्छा कई लोग कहते थे अध्यक्ष जी कि ये फ्री में बिजली देता है, पानी देता है। मैंने पूछा कई लोगों से तो उन्होंने कहा कि फी में दिल्ली को जो ओमप्रकाश जी कह रहे थे लंग्स के फेफड़े के अस्थमा के, सांस की बीमारियां दी इस आदमी ने प्रदूषित हवा के माध्यम से, प्रदूषित पानी के माध्यम से और जब हिसाब लगाया मैंने तो मैंने देखा कि जितना 80 से 90 सिगरेट बीड़ी का धुंआ हमारे फेफड़ों में ये फ्री जबरदस्ती का रोज-रोज ठूंस रहा है, जिससे पूरी दिल्ली बीमार हो गयी है, खांस रही है। बहुत सारी एजेंसीज में इन्होंने कभी भी कोर्डिनेशन नहीं किया, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जो निर्माण एजेन्सियां हैं, परिवहन विभाग है, ट्रैफिक पुलिस है, नगर निगम है, बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं। किसी में इन्होंने जन भागीदारी नहीं बनायी और कोई अकांउटीबिलिटी क्रिएट नहीं की। हजारों डीटीसी की बसें एक्सपायरी डेटेड एक्सटेंडेड

चल रही हैं, एक बस खरीद नहीं पाये, इसीलिए हमने मोदी जी का धन्यवाद किया कि इलैक्ट्रिक बसें देकर कुछ तो हल्का किया है। और अंत में अध्यक्ष जी जैसा आपने सौर ऊर्जा के लिए 100 परसेंट सौर ऊर्जा के लिए विधानसभा को 100 डेज का आपने कमिटमेंट लिया है वैसे ही मेरा आपसे निवेदन है अध्यक्ष जी कि ई चार्जिंग के लिए भी आप, इलैक्ट्रिकल गाड़ियों के लिए अगर विधानसभा में इसका प्रोविजन करेंगे तो ये भी एक अच्छा संदेश जाएगा और इसके लिए एक अच्छा पर्यावरण के लिए संदेश जाएगा। इको फ्रेंडली सिस्टम असेम्बली में बनाया जाए। इसके लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से और एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं कि:

"आओ सब मिलकर ये कसमें खाएं,
वायु प्रदुषण से दिल्ली का जीवन बचाएं।"

अध्यक्ष जी बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री तरविंदर सिंह मारवाह।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः अध्यक्ष जी घड़ी की तरफ मत देखना, घड़ी जरा ध्यान रखना, घड़ी की तरफ मत देखना। तो इसलिये क्योंकि जरा मामला ऐसा है ना जी मामला जीवन का है। अध्यक्ष जी, दिल्ली की बात करने जा रहे हैं दिल्ली को दिलवालों की दिल्ली कहते हैं और दिल्ली हिन्दुस्तान की राजधानी है। वो दिन बड़ा ही दिल्ली के लिये कलंकित दिन था जिस दिन दिल्ली

में एक नातजुर्बेवाले को सरकार बनाने का मौका मिल गया। अध्यक्ष जी दिल्ली में आप भी शुरू से रह रहे हैं, सुनो हम तो बाद में पैदा हुये थे। हां, क्योंकि आप तो पुराने हैं ना हम तो बाहर से आये थे ना। आप तो दिल्ली वाले हो हम तो बाहर से पाकिस्तान से आकर यहां रिफ्यूजी आये थे लेकिन हमसे कहते हैं आपको तजुर्बा है दिल्ली के बारे में। दिल्ली 14 सौ 83 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है दो करोड़ की आबादी दिल्ली में आज गिनें तो दो करोड़ से भी ज्यादा ही है अध्यक्ष जी। ये तालियां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के लिये बजाई जा रही हैं मैं बता दूं अध्यक्ष जी मेरे लिये नहीं बजाई जा रहीं। बता दो तो ठीक रहता है ना अध्यक्ष जी को भी पता लगना चाहिये। अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी केजरीवाल के बारे में आज में खोलूंगा तो आप भी हैरान हो जाओगे ये करता क्या रहा है। 2014 से लेकर 2025 जनवरी तक जो असली जान की बात होती है हर आदमी को अपनी जान से प्यारी कोई चीज़ नहीं होती कोई भी व्यक्ति हो उसको सबसे पहले अपनी जान प्यारी होती है चाहे कोई खरबोंपति हो चाहे किसी को पता ही नहीं मेरे पास कितना पैसा है उसको जान सबसे पहले चाहिये। इस व्यक्ति ने केजरीवाल ने लोगों की जान पर खेला है। इसने 10 साल जो असली व्यक्ति की सांस के लिये इसने कुछ नहीं सोचा सिर्फ रिश्वतखोरी कहां से पैसा आना है इसने लोगों की जान को भी दांव पर लगा दिया मतलब जान को भी दांव पर लगा दिया। यहीं तक नहीं अध्यक्ष जी 2024 में जो दिल्ली के प्रदुषण का था 484 तो खातों में है लेकिन असली साढ़े पांच सौ से भी ऊपर गया है।

700 तक भी गया और उसके बाद केजरीवाल ने 11 साल में इसके लिये कोई नीति नहीं बनाई अध्यक्ष जी, नीति के अलावा जो पराली को गलाने के लिये decomposer solution बनाने की घोषणा की उसके प्रचार में अध्यक्ष जी उसके प्रचार में करोड़ों रूपया लगाया लेकिन अध्यक्ष जी बड़ी शर्म की बात है कि दिल्ली वालों के लिये वो लगा ही नहीं और ये बड़ी-बड़ी अखबारों में अपना प्रचार देता रहा। आज तक उसका कोई पता नहीं है अध्यक्ष जी और सबसे बड़ी बात उसके लिये शर्म की बात है कि दो साल पौने दो साल पंजाब की सरकार रही और ये कहता था कि पंजाब से धुआं आता है लेकिन इसने पौने दो साल पंजाब के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, कोई स्टेटमेंट नहीं दी इसने कि धुंआ पंजाब से आ रहा है ये हरियाणा की तरफ ले गया उसे मतलब हर बात पर राजनीति की है हर बात पर इसने झूठ बोला है जो इसको सज़ा मिल गई जेल जाने की सज़ा मिली। अध्यक्ष जी, वो लोगों ने जो लोगों का नुकसान हुआ जो लोगों को इसने गुमराह किया ये जेल जाने की सज़ा उसकी थी। जहरीली हवा से दिल्लीवालों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा अध्यक्ष जी। एनसीआर की बड़ी आबादी इस प्रदूषण की वजह से फेंफड़ों की बीमारियों का शिकार हो चुकी है। इसने कोई भी जो लोग सिगरेट पीते हैं उसके लिये भी कोई जगह तय नहीं की थी कहां-कहां सिगरेट पी सकते हैं। अध्यक्ष जी, इसने सबसे बड़ी बात प्रदूषण तो एक महीने के लिए थोड़े ही आता है प्रदूषण तो रोज ही होता है अध्यक्ष जी।

जो इसने पानी की गाड़ियां लगाई वो सिर्फ दो महीने के लिए लगाई हैं बड़े ही शर्म की बात है एक तरफ तो लोग प्रदूषण से फेफड़े अपने कमजोर कर रहे हैं लेकिन इसने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और इसने दो महीने सिर्फ इसने और कई बार अध्यक्ष जी बड़े अचंभे की बात है दिल्ली में दिन को भी अंधेरा हो जाता था अध्यक्ष जी ये बड़े अचंभे की बात है जब प्रदूषण होता था। दिन में, दिन में अंधेरा कभी नहीं देखा दिल्ली वालों ने लेकिन इसके समय दिल्ली वालों ने दिन में अंधेरा देखा है अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, जो बीमारियां अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी, स्ट्रोक, निमोनिया, फेंफड़ों का कैंसर ये बीमारियां लोगों में अध्यक्ष जी हर तीसरा आदमी बुखार में आ जाता था, हर तीसरे आदमी को कैंसर की बीमारी का सामना करना पड़ा सिर्फ प्रदूषण से। हर तीसरे आदमी को अध्यक्ष जी पता लगता था जब कैंसर पूरे में फैल जाता था तब व्यक्ति को पता लगता था उसको जान से जाना पड़ा। अध्यक्ष जी, दिल्ली में प्रदूषण के कारण रोज 30-35 मौतें हुई हैं अध्यक्ष जी ये डाटा बता रहा है और सीएजी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें साफ-साफ लिखा है कि सरकार ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। सरकार जब बनी थी 2014 में तो सरकार ने सबसे पहले कहा था कि मैं 10 हजार 12 हजार बसें लेकर आउंगा इसने कहा था लेकिन बसें कहां गईं टैंडर भी हो गई बसों का पता ही नहीं अध्यक्ष जी। उसको छोड़ो इसने कहा मैं सीएनजी की बसें लेकर आउंगा, इसने कहा मैं इलेक्ट्रिक बसें लेकर आउंगा वो बसें

गई कहां टैंडर भी लग गये बसों वालों ने जिन्होंने टैंडर लगाये उनमें जुर्माना भी लग गया लेकिन जुर्माना वसूल नहीं हुआ अध्यक्ष जी। जब बसें नहीं थी तो लोग तो टू-व्हीलर में चलेगे ही चलेंगे। वो पुराना लमरेटा लेकर दूसरा बजाज लेकर जो 5 हजार, 7 हजार गरीब आदमी के पास पैसा कहां है। लोगों ने यूपी में गये 5-7 हजार का ले आये दिल्ली में हवा-हवा-हवा प्रदूषण चलता रहा लेकिन किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। अध्यक्ष जी घर बैठे फिटनेस इसके समय में आपने देखा होगा की घर बैठे फिटनेस। दलाल घर आकर पैसे ले जाते थे और फिटनेस आपकी शाम को फिटनेस का कागज दे जाते थे। जो प्रदूषण को चैक करता है पेट्रोल पंपों पर कभी किसी का प्रदूषण चैक नहीं हुआ सिर्फ आप पैसे दो और आपको उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा घर बैठे अध्यक्ष जी ये इसकी सरकार की कमजोरियां जो थी उसी करके दिल्ली में जो हालात बने हैं आज दिल्ली में जो हालात बने हैं हमारी मुख्यमंत्री जी ने आते ही मैं उनका धन्यवाद करता हूं दिल्ली की जनता की तरफ से की जो उन्होंने वाटर जो टैंकर चलेंगे दिल्ली में दो महीने का जो टैंडर होता था अब पूरा साल दिल्ली की सड़कों में वाटर टैंकर चलेंगे ये हमारी ऐतिहासिक मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है अध्यक्ष जी। ये कोई छोटा फैसला नहीं है अध्यक्ष जी ये बहुत बड़ा छिड़काव का एक तो दिल्ली सुन्दर होगी साथ में ही प्रदूषण खत्म होगा और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम हर लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि हमारी सरकार ईमानदार सरकार है। हमारी सरकार बने हुए दो

महीने हुए हैं कितने बड़े-बड़े फैसले हो गये किसी ने सपने में नहीं सोचा था की दिल्ली में एक लाख करोड़ का बजट आ जाएगा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। विपक्ष ने अध्यक्ष जी इसको भी जुमला कहा क्योंकि उनके पास कोई टाइम ही नहीं है, उनके पास समय ही नहीं है वो काम की बात करना ही नहीं चाहते क्योंकि बेईमानी का घड़ा पूरा भरा हुआ है अध्यक्ष जी उनके यहां तक भरा हुआ है। कोई ऐसा मंत्री नहीं, कोई ऐसा एमएलए नहीं जो करप्शन के चार्ज में उसके ऊपर कोई न कोई चार्ज न लगा हो। अध्यक्ष जी बड़ी मुझे पता है आपकी हल्की-हल्की गर्दन हिल रही है।

(समय की घंटी)

श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः लेकिन मैं और ज्यादा नहीं समय लूंगा आपके लिए कुछ और भी लेकर आया हूं वो भी सुना दूंगा मैं क्योंकि अध्यक्ष जी सबसे बड़ी बात है कि जानलेवा हमले वाले चीजों पर भी रिश्वत खाई है। 20 करोड़ का जो वो लगाया था एक साल में आज वो कबाड़िये उठाकर ले जा रहे हैं और उसकी ऐड में कितना खर्च किया वो तो खुराना जी ने डिटेल में बता दिया है। हर चीज में रिश्वत लोगों की जान में रिश्वत, इससे बुरी केजरीवाल क्या बात हो सकती है, तू तो दिल्ली का मालिक कहता था। अध्यक्ष जी असली बात जो रह गयी है, अध्यक्ष जी, कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि प्रदूषण पर कोई समझौता करता है मुख्यमंत्री, क्योंकि ये जो है, ये लोगों की जान से है। हमारे

बच्चों के हैं जो छोटे बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी उम्र कम हो रही है, 11 साल में जो बच्चे ने अपने जीवन 100 साल पूरे करने थे, 90 साल पूरे करने थे, 80 साल पूरे करने थे उसकी दस साल उम्र इस केजरीवाल के समय में कम हो गयी है अध्यक्ष जी, बड़े ही शर्म की बात है कि आपने उन चीजों से समझौता किया, उन चीजों से रिश्वत खायी, सबसे पहले बसों में जो खायी, जो आपने जो बना रखे हैं जहां फिटनेस में खायी। अपने मतलब के व्यक्ति लगा रखे थे आपने किससे खायी, जो पट्रोल पंपो में जो प्रदूषण चैक करते हैं घर बैठे, क्योंकि दलाल आते थे, दलाल आप तक पैसा पहुंचाते थे अध्यक्ष जी, बहुत शर्म की बात है। अध्यक्ष जी, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आप इसका कोई लिहाज मत करना, जितनी भी रिपोर्टें आ रही हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा था रैलियों में कि सबसे पहले हम सीएजी की रिपोर्टें लाएंगे और बड़े शर्म की बात है दिल्ली विधानसभा में कि 11 साल में कोई सीएजी की रिपोर्ट पटल पर नहीं आयी इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। विपक्ष के लिए जो आज बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि मतलब 11 साल सीएजी की रिपोर्टों को दबाये रखा।

(समय की घंटी)

श्री तरविंदर सिंह मारवाहः हाई कोर्ट के फैंसले को भी नहीं माना, इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती अध्यक्ष जी। मैं आपको एक इसके बारे में कुछ सुना भी देना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी

भी उम्र हमने बढ़ानी है। खुश रहोगे तो उम्र बढ़ेगी। तो इसलिए मैं आपके लिए स्पेशल कुछ न कुछ लेकर आता हूँ वो इसलिए आपके लिए। आज पिछली बार कुछ और था इस बार कुछ और है, सूद साहब जरा थोड़ा ध्यान दो, असी सूद साहब बड़ा बिजी हैं। रोटी पिक्चर आयी थी, आयी थी ना, राजेश खन्ना अध्यक्ष जी, रोटी पिक्चर आयी थी और लोगों ने सुना भी है राजेश खन्ना 'नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा।' सुनने की है, 'कहां कदरदान हमें ऐसा मिलेगा।' अध्यक्ष जी मैं कहना चाहता हूँ, 'नाच केजरीवाल तुझे रिश्वत का पैसा मिलेगा, कहां गद्दारों में हमें एक ऐसा इंसान मिलेगा।' अध्यक्ष जी, दूसरा उसने कहा घुंघरू बनाकर पैरों में बांध ले, सुन लें, अध्यक्ष जी, 'घुंघरू बनाकर पैरों में बांध ले, कहां मेहरबान हमें ऐसा मिलेगा।' अध्यक्ष जी, केजरीवाल सोने के घुंघरू लाकर पैरों में बांध ले, पैरों में बांध लिये, तेरे को खूब रिश्वत का पैसा मिलेगा, ऐसा मौका ना तेरे को बार-बार मिलेगा, क्योंकि एक ही बार तूने सारे दिल्ली को लूट लिया है। अध्यक्ष जी, तीसरा।

(समय की घंटी)

श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः अध्यक्ष जी, मौसम रंगीन है।

माननीय अध्यक्षः कॉनक्लूड करिये।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः 'मौसम रंगीन है आशिक शौकीन है, तू जो चाहे कर ले, मौका हसीन है, फिर कब नादान, हमें ऐसा मौका मिलेगा, पैसा मिलेगा।' अध्यक्ष जी इसमें तो बड़ा काम

की चीज आयी है, बड़े काम की चीज है, अध्यक्ष जी इससे तो कई मेरे मेम्बर नाच गाना ना शुरु कर दें यहीं पर, इसलिए मैं उनको रोकूंगा, मैं उनको रोकूंगा। मौसम रंगीन है केजरीवाल तू तो शौकीन है, तू जो चाहे कर ले, अपने आलीशान 45 करोड़ के बंगले में मौका फिर कब तुझे ऐसा मिलेगा। 45 करोड़ के बंगले में मैं बताना नहीं चाहता क्या-क्या हुआ है वहां और रोज क्या-क्या होता था, ये मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि कुछ मर्यादा रखनी पड़ती है, नहीं-नहीं, मैं नहीं बताना चाहता अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः मैं मारवाह साहब ।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः बस 2 मिनट में, दो मिनट में एक और सुनाकर फिर बैठ रहा हूँ अध्यक्ष जी, क्योंकि ये भी आपके उम्र बढ़ाने के लिए है। बचा लो कुछ अपने कल के लिए भी ना समझी में खुदा से लड़ने लगे, तुम हवाओं ने जो अपने तेवर बदल लिए, फिर सांसों में लिए तड़पाने लगेंगे तुम्हे। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को सांसों के लिए तड़पाया है ये इसके लिए इतना बुरा दिन गिना जाएगा अध्यक्ष जी, ये जो बात कही है ना किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है। जो किसी को तड़पाता है इसने लोगों की जानों के लिए तड़पाया है लोगों को, एक लास्ट में कहकर बैठ रहा हूँ मैं।

माननीय अध्यक्षः चलिए, धन्यवाद।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः 'हवाओं में धुआं है, फिजाओं में जहर है' ये दिल्ली को छोड़ कर गया है अध्यक्ष जी केजरीवाल। आपका धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः सदन की बैठक तीस मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

सदन पुनः अपराह्न 04:40 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष (श्री विजेन्द्र गुप्ता) पीठासीन हुए।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य श्रीमती शिखा रॉय।

सुश्री शिखा रॉयः धन्यवाद अध्यक्ष जी, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपने बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी पिछले कई वर्षो से हम सब दिल्ली के उस हवा की बात जो जहरीली हो चुकी है, उसकी अक्सर करते हैंक्योंकि हम सब भुक्तभोगी है। हम यहीं इसी हवा में सांस लेते हैं तो इसलिए जो दिक्कतें हमें आती थी पिछले इतने वर्षो में उसको हम रोज ही अपने-अपने घरों में उसके ऊपर चर्चा होती रहती है। क्योंकि उसके कारण घर परिवारों में अपने सभी बहुत ही प्यारे जो हमारे सब परिवार के लोग होते हैं। रिश्तेदार नाते जब उनको सुनते हैं कि आज वो होस्पिटल में एडमिट है, आज उसका लंग्स का ईशू आ गया है तो बार-बार इस विषय पर हम चर्चा करते हैं बल्कि रोज उठकरके ही अब तो मोबाइल में एक्यूआई भी देखना पड़ता है कि आज कितना है, आज क्या स्थिति रहेगी। कभी-कभी तो मैं सोचती हूं कि जो नया बच्चा

जन्म ले रहा है इस दिल्ली में जिसके फेंफड़े उस समय इतने नाजुक होते हैं तो उसको आते ही ऐसी हवा में सांस लेनी पड़ती होगी तो शायद बेचारा बच्चा भी कभी ये सोचता हो कि मैं माँ के अंदर गर्भ में ही ज्यादा मैं खुश था और अच्छे वातावरण में था। ये स्थिति बिल्कुल ऐसी लगती है कभी-कभी जब देखती हूं, बच्चों को मिलने जाती हूं कोई नया बच्चा परिवार में आता है तो और मैं ये हैरान हूं कि ये बातें जब हम चाहे विपक्ष की बात नहीं है एक साधारण नागरिक की तरह हम इस चीज को सब महसूस करते हैं। तो क्या सरकार में आ करके कुछ अलग हो जाता है कि जो मंत्री हो जाते हैं, जो मुख्यमंत्री हो जाते हैं तो उनके यहां क्या उनकी नाक के आगे या उनके घरों में कुछ अलग फिल्टर लगे होते हैं कि वो इन चीजों को महसूस नहीं कर पाते। कल हमारे मंत्री आशीष सूद साहब जब बयान कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आतिशी जी के घर में दो फीडर लगे हुए है बिजली की सप्लाई के तो मुझे लगा कि शायद ऐसा होगा कि इनके यहां पर भी कोई कुछ फिल्टर भी अलग सरकार देती होगी, जिससे इन लोगों को ये जो हवा है, सीएम साहब के घर पर वो भी लगे हैं फिल्टर लगे हैं अलग है। एक्स सीएम साहब के घर अभी मंत्री साहब बता रहे हैं कि शायद वो फिल्टर्स भी अलग से लगे हैं। ऐयरप्यूरिफायर्स लगें है जिसकी जो सरकारी खर्चे पर लगे होंगे जरूर। तो शायद इस वजह से नहीं महसूस होगा कि वो दिल्ली की जनता के साथ कर क्या रहे हैं। ये ठीक है कि

व्हीकल दिल्ली मे दिन भर दिन बढ़ता जा रहा है और एयर जो पोल्यूशन है उसमें vehicular जो emissions हैं, पोल्यूशन है वो शायद 29-30 परसेंट योगदान देता है, अगर मैं मुझे फिगर्स क्योंकि अलग-अलग तरह की फिग्र्स 29, अलग-अलग तरह की फिग्र्स भी आती रहती है। लेकिन इतना है जब हमें पता है कि ये प्रोब्लम इस vehicular traffic से होती है तो उसके सोल्यूशन्स के बारे में, उसके समाधानों पर चर्चा हमने कभी इसी सदन के माध्यम से पिछली सरकार की तरफ से नहीं सुनी। कभी हमने ये नहीं सुना कि कैबिनेट इस बात को लेकरके चिंतित है। आज जब हम इस सदन में ये देखते हैं कि जब पानी सीवर की बात आती है तो उस पर सदन विशेष चर्चा करता है। आज सीएजी की रिपोर्ट आई है तो उस पर भी सदन विशेष चर्चा कर रहा है तो इसी लिए कि चर्चा के साथ-साथ जो समाधान इसमें मिले उस पर implementation हो और इस बात का समाधान निकले लेकिन पिछली सरकार के माध्यम से हमने कभी ये नहीं इस बात को देखा सुना था कि उन्होंने इस बात पर चर्चा भी की। केवल जब पोल्यूशन के लेवल्स बढ़ते थे। विपक्ष चिल्लाता था, लोग चिल्लाते थे। हस्पतालों में मरीज बढ़ जाते हैं तो केवल एक ही बातों की चर्चा होती थी कि ये पराली से है ये पंजाब से आता है, ये हरियाणा ये करता है ये ही सुनने को मिलता था। लेकिन कभी किसी समाधान की तरफ हमने कोई कदम उनके बढ़ते हुए नहीं देखे। अगर vehicular traffic pollution कर रहा है तो इसका अर्थ ये ही है कि दिल्ली

में कैसे vehicles transport के system को यूज करने के लिए कम हो। उसका सबसे बड़ा माध्यम पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही रहता है। इसलिए सरकार ये हमेशा उम्मीद रही कि public transport को इतना मजबूत करो, इतना सुदृढ और सक्षम करो कि private transport system को कम इस्तेमाल हो और सब जो दिल्ली में एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं वो उस सिस्टम को इस्तेमाल करें तभी हम सड़कों के ऊपर से प्राईवेट व्हीकल को कम कर सकते हैं। लेकिन यहां तो ये हालत थी कि जितना बसों की fleet नौ हजार के करीब जो analysis और रिपोर्ट देती है कि वो बसेज होनी चाहिए थी उससे कहीं नम्बर इतना कम रहा हमेशा कि कोई भी सोच भी नहीं सकता था कि आम साधारण जन बिना धक्के खाए, बिना घिचेपिचे सरकारी बसों में सफर कर सके तो इस लिए हर कोई मजबूर रहता था अपना प्राईवेट व्हीकल खरीदने के लिए चाहे वो टू व्हीलर ही हो। हम सब जानते है कि इनकी emission कितनी घातक होती है जो इस हवा को जो है जहरीला बनाती है। आज मैं सोचती हूं कि हम सबको मन से धन्यवाद देना चाहिए हमारी उस 93 से 98 की सरकार का जिसने मैट्रो के बारे में सोचा। हमारे खुराना जी मैट्रो को conceive किया। आदरणीय साहिब सिंह वर्मा जी ने उसको आगे बढ़ा करके उसको प्रोजेक्ट को 98 में शुरू किया। अगर वो नहीं होता आज दिल्ली में तो दिल्ली की हालत क्या होती। मैं ये सोचती हूं कि सोच भी नहीं सकते हैं कि कैसे सड़क पर व्हीकल भी चल पाता। अगर 93 में ये सोच एक

सरकार की, एक ideology की एक पार्टी की हो सकती है तो इस दौरान में जो सरकारें रही उन्होंने ये सोच एक सरकार ने कर ली और 98 में चले गए तो उसके बाद से और नई सोच नई जो टैक्नोलोजी नई कुछ विचार इसके ऊपर किये जाने चाहिए थे जो बीच की सरकारों ने लगातार इसको इग्नोर किया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो माध्यम हैं उनके अलावा भी और क्या माध्यम हो सकते हैं क्योंकि मैने अभी पीछे एक उस में पढ़ा था कि शायद हमारा केन्द्र हमारे प्रधान मंत्री जी इस बात पर विचार हो रहा है उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से जब दिल्ली से गुड़गांव तक एयर जो है एक रेल बनेगी जिससे आगे का सफर होगा। कहने का अर्थ ये ही है कि जो नये तरीके हो सकते हैं इस ट्रैफिक को कम करने के वो सोचे तो जाते हैं लेकिन इस सरकार ने कभी ऐसे किसी विषय पर कभी भी चर्चा और ध्यान नहीं दिया। अध्यक्ष जी बहुत कुछ इस विषय पर मुझ से पूर्व माननीय सदस्यों ने कहा है इस लिए कुछ शायद नया ना हो क्योंकि विषय बहुत से आ चुके हैं। अध्यक्ष जी, हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक चीज ये मानते हैं कि connectivity to the last mile का जो एक सिस्टम होता है उसका एक साधन हो। उसमें ग्रामीण सेवा जो एक हमारा सिस्टम था बहुत अच्छा माध्यम इसका रहा। लेकिन जितने 2011 में 6,153 वो थी उतनी ही पोपूलेशन 17 परसेंट बढ़ गई। लेकिन कभी ये नहीं सोचा गया कि इसके विषय पर ..

(समय की घंटी)

सुश्री शिखा रॉयः उसका विचार करना चाहिए। अध्यक्ष जी जब घंटी बज जाती है ना तो मेरा मुझे ये हो जाता है कि मैं बैठूं इसलिए मेरा विषय पर से थोड़ा..

माननीय अध्यक्षः यहां आपका विषय वैसे पूरा हो गया है मैने पूरा समय दिया है।

सुश्री शिखा रॉयः वो हो जाता है। मैं चाहती नहीं कि मैं आपके बैल बजाने के बाद बोलूं लेकिन चूंकि मेरे पास मैटीरियल काफी है इस बारे में। मैं केवल इतनी बात और इसमें ऐड करूंगी कि एक तरफ तो इसके बारे में सोचा नहीं गया लेकिन दूसरी तरफ इस डिपार्टमेंट में इसको कंट्रोल करने के जो measures थे उनको नजरअंदाज कर वहां भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा अड्डा बन गया। आंकडों से पता चलता है कि जो फिटनेस सेंटर्स थे, झुलझुली और बुराड़ी में यानि आंख से देखकर ही कोई टेस्टिंग नहीं। व्हीकल आया, कौन से ऐसे अधिकारी थे, कौन सा ऐसा सिस्टम था जो आंख से ही चैक करता था कि ये इसी फिटनेस हो गई और उसको फिटनेस का सर्टिफिकेट दे दिया जाता था। नब्बे प्रतिशत इस तरह के व्हीकल्स को दिया जाता था। तो हम सोच सकते हैं कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार का माध्यम जो है वो ये पर्यावरण के environment की जो वो थी वो बना हुआ था। इलैक्ट्रिक व्हीकल एक बहुत बड़ा अच्छा माध्यम है इसको कवर करने के लिए जब हम लोग 2017 में एमसीडी में भाजपा की सरकार बनी थी तो 75 व्हीकल्स खरीदे गए थे, मोदी जी के उस मिशन को लेकरके कि

दिल्ली में प्रदूषण कम हो और अफसरों को दिये गए थे कि उन व्हीकल्स का प्रयोग वो करें। कहने का अर्थ कि अगर एमसीडी जैसा विभाग भी इसके बारे सोच सकता है तो इस इलैक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए सरकार ने इसको बढ़ावा देने के लिए क्या सोचा, कुछ नहीं। अध्यक्ष जी क्योंकि बैल बज चुकी है इसलिए बहुत सारे विषय मेरे पास होते हुए भी..

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद।

सुश्री शिखा रॉयः मैं नहीं रखना चाहूंगी, उसका सम्मान करूंगी इस बैल का। बस इतना कहते हुए कि अब हमारी सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। मैं ये भी जानती हूं कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम कुछ ही समय में नहीं कंट्रोल कर सकते लेकिन इसकी और हर बढ़ता हुआ कदम भी काफी पर्याप्त होगा अगर उस पर ध्यान दे करके हमारी मिनिस्ट्री और हमारे मुख्य मंत्री साहिबा इस पर ध्यान देंगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः डा. अनिल गोयल माननीय सदस्य।

डॉ. अनिल गोयलः धन्यवाद अध्यक्ष जी, दिल्ली में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम पर मुझे बोलने के लिए कहा गया। तो ये विषय क्योंकि स्वास्थय से भी जुड़ा है और वाहन प्रदूषण से भी, ये दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली हो गई। ये दस्तावेज जो सीएजी का है वो भ्रष्टाचार का है criminal negligence का है और इसमें सारी बीमारी का इलाज भी लिखा है।

जो बीमारी का इलाज केजरीवाल सरकार नहीं कर पाई। वायु प्रदूषण रोकथाम के लिए दम घोंटू गैस खासतौर से नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी पिछले सालों में बराबर होती जा रही है। फिर भी इस हवा जो हम भी सांस लेते है और विपक्ष के लोग भी लेते हैं उनकी खांसी, उनकी ठीक हो गई जिनकी नहीं होनी चाहिए थी वो शायद बैगलूरू में जा कर हो गई। लेकिन उस दम घोंटू गैस में क्या होता है ये मैं बताना चाहता हूं। nitrogen oxide, Sulphur dioxide, ammonia, lead और जो फ्यूल स्टेशन्स हैं उन पर benzene भी होती है। बच्चों के स्कूल बंद, कन्सट्रक्शन बंद। अभी मेरी बहन ने कहा हमारे घर में भी छोटा बच्चा है उसके फेफड़े मजबूत नहीं होंगे, अगले पांच साल। हो सकता है आगे आने वाले समय में उसकी दस पन्द्रह साल ऐज कम हो जाये। पांच साल एवरेज ऐज कम। इसके अलावा कैंसर होना और पीएम 2.5 मैं बताना चाहता हूं इस सदन के माध्यम से देश की जनता को वो सीधे हार्ट में जाता है पीएम2.5 और हार्ट अटैक करता है, स्ट्रोक करता है। इसके अलावा जब कंस्ट्रक्शन बंद है 3 महीने तो क्या होता है कि वहां पर जो लोग बाहर चले जाते हैं वो आते नहीं। सबसे बड़ी बात ये है अध्यक्ष जी, ये तीन महीने का इशु नहीं है। हमारे माननीय मंत्री एनवायरनमेंट मिनिस्टर सिरसा जी ने इसको समझा, जैसे ही सरकार बनी मैं देख रहा था कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में इन्होंने 10 point चार्टर इसका बना दिया। इन्होंने उस बीमारी को समझा कि इसकी डायग्नोसिज़ भी किया, इसका ईलाज भी किया और मुझे

विश्वास है इस सदन के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि सिरसा जी अगले साल नवम्बर दिसम्बर में एक खराब हवा दिल्ली को नहीं देंगे, एक साफ हवा देंगे ऐसा मेरा विश्वास है। बीमारी हमको मालूम है वाहन है वाहन से निकलने वाला एमिशन है, वायु प्रदूषण की जांच है, स्वच्छ ऑल्टरनेटिव परिवहन के साधन है। अध्यक्ष जी, 1.3 करोड़ वाहन में दुपहिया 81 लाख हैं। 81 लाख सिर्फ दुपहिया हैं और वो क्यूं हुए, क्योंकि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं दे पाये। अभी मैं परसो का अखबार दिखाना चाहता हूं। एनसीआर में 18 नये मेट्रो कोरिडोर, 216 किमी. नया मेट्रो बनने जा रहा है, मोनोरेल, लाइट रेल, electric 5 हजार बस माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा इलेक्ट्रिक बस मारवाह जी इलेक्ट्रिक बस 5 हजार दिल्ली में आने वाली हैं। ये क्या है, ये आगे आने वाले समय की सोच है। एक तरफ वो सरकार है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस 9 हजार हैं पुरानी हैं, आफ रोड है, मैनेजमेंट प्रॉब्लम है, एक वो सरकार है जो ग्रामीण बस 2011 के बाद 6 हजार से ज्यादा बढ़ाती नहीं, लास्ट माइल connectivity में भी पॉल्यूशन घर घर में घर घर में पॉल्यूशन पहुंचा दिया। एक वो सरकार है जो दस वर्ष पुराने बसों को चलाकर प्रदूषण फैला रही है बजट होने के बावजूद, बजट होने के बावजूद मोनो रेल, लाइट रेल, इलेक्ट्रिक ट्राली बस वो नहीं चला रही, उसके लिये कोई कदम नहीं उठा रही। और एक तरफ सरकार है माननीय रेखा गुप्ता जी की वो पहले दिन आते ही कहती है कि दिल्ली की हवा साफ करनी है, दिल्ली की हवा साफ करनी है

और ये भी अखबार की रिपोर्ट है सिरसा साहब को मैं दिखाना चाहता हूं "cleaner air, cleaner month than previous year but now" पिछले साल के मुकाबले में मार्च एक बेहतर हवा रही 201 क्यूआई के नीचे रहा। मैं बधाई देना चाहता हूं दिल्ली की सरकार को और ये क्यूं हुआ क्योंकि जमीनी स्तर पर गुणवता में सुधार हो रहा है, जमीनी स्तर पर कार्य हो रहा है। ये अखबारों की खबर है। फ्यूल स्टेशंस पर माननीय मंत्री जी ने जो कहा कि बेंजिन निकलती है वहां पर स्मार्ट गैजेट्स का इस्तेमाल होगा। मुझे लगता है जो व्हीकल एमिशन जांच होती है वो एट सोर्स होगी, जैसे टीडीएस होता है तो उस तरह से जो भी गाड़ियां हैं उनको फ्यूल नहीं मिलना ये बहुत बढ़िया उपाय है जो पिछली सरकार को करना चाहिये था नहीं किया गया। और आप सोचिये 41 लाख व्हीकल दिल्ली में स्क्रैपिंग के लिये हैं जो 15 साल से उपर पेट्रोल और 10 साल से उपर डीजल रखने की जगह सिर्फ 4 हजार ये सीएजी की रिपोर्ट में बताया और स्क्रैप किया गया एक भी नहीं। न पर्याप्त कर्मचारी न पर्याप्त इक्विपमेंट। तो आप मुझे बताईये ग्रैप की जरूरत क्यूं पड़ती है। इसलिये पड़ती कि जब आप इसको मेनटेन नहीं कर पा रहे। उसकी जगह उन्होंने क्या किया ऑड इवन ये व्यर्थ ये सांइटिफिक एनवायरनमेंट कमेटी की रिपोर्ट है दिल्ली में सबसे बड़ा प्रदूषण का सोर्स है जो दिल्ली से बाहर आने वाले हेवी व्हीकल और दिल्ली से आने वाली अन्तर्राज्जीय बसें उनको कंट्रोल कौन कर रहा है, आईएसबीटी पर उसको कंट्रोल करने के लिये कुछ भी नहीं किया

गया, पार्किंग बेतरतीब, उपलब्धतता ही नहीं, ट्रैफिक कंजेशन के कारण दिल्ली चिड़चिड़ी हो रही है। रोड रेज जितने भी कारण हैं वो ट्रैफिक congestion के कारण है उसके रोकने के लियेएक बेहतर पार्किंग व्यवस्था होनी चाहिये थी वो नहीं हुई। फिर एमिशन की जांच में तो इतना फ्रॉड है आप उसको पढ़ो तो दिल को दर्द होता है कि क्या एमिशन की जांच में भी भ्रष्टाचार हो रहा था। 24 परसेंट को बिना जांच पास कर दिया, फेल को पास किया, 1.08 परसेंट पेट्रोल सीएनजी पंप में से 65 लाख में ये सब फेल हो गये, एक व्हीकल को एक ही समय पर कई केंद्रों पर पास दिखाया गया। वाहन डाटा बेस को पीयूसी डेटा से लिंक करना चाहिये था नहीं हुआ। जब वाहन डाटा को पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट से लिंक करेंगे तब ये ठीक होगा नहीं तो वहां जबर्दस्त भ्रष्टाचार हुआ और इसका किसी भी काम का एक थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिये। कोई काम अगर आप करेंगे मैंने किया तो मेरा ऑडिट कोई तीसरी पार्टी करे, ऐसा कुछ नहीं किया। माडर्न स्मार्ट गैजेट, रिमोट सेंसिंग डिवाइस किया गया कमर्शियल को तो 95 परसेंट को सिर्फ मैनुअली फिट घोषित कर दिया गया। 64 परसेंट व्हीकल दिल्ली में बगैर फिटनेस टेस्ट के दिल्ली में घूम रहे हैं। 60 परसेंट फिटनेस सर्टिफिकेट इशु किये गये बगैर फिटनेस टेस्ट किये गये जो इसमें सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बावजूद पीएस 3, पीएस 4 को रजिस्टर किया गया गाड़ियों को जबकि ये आर्डर नहीं था। इतना नेग्लिजेंस ये क्रिमिनल अपराधिक लापरवाही के अलावा

और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। 47.5 लाख (समय की घंटी बजी) डिरजिस्टर होने हैं वो नहीं हुए। मैं इस वायु प्रदूषण की भी बात करता हूं। जब हम लोग वायु प्रदूषण की बात करते हैं तो क्लीनर एनवायरनमेंट के लिये चार्जिंग स्टेशन नहीं हैं। आप बताईये इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं तो चार्जिंग स्टेशन चाहिये उसको किसने बनाना था वो नहीं बनाया गया। पार्किंग उपलब्ध नहीं। वायु प्रदूषण ए.क्यू.आई. और गैस चैंबर 500 से ज्यादा अक्सर देखते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि खास तौर से पेट्रोल पंप पर जहां हम देखते हैं बेंजिन निकलता है उससे हेडेक न्यूरोलाजिकल प्रॉब्लम वो सारी होती हैं। ये बराबर है 10 सिगरेट पीना, बुद्धि कम, 10 साल उम्र कम। तो मेरा अध्यक्ष जी प्रदूषण का रोना रोने वाले जो कोई वैज्ञानिक प्लानिंग नहीं किया न कोई कोशिश किया सिर्फ कहा केंद्र कुछ करे ऐसा राग अलापते रहे। हमने मैं फिर माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ करना चाहता हूं केबिनेट की मार्च 2025 में आपने कृत्रिम वर्षा का परीक्षण शुरू कर दिया है और ये वैज्ञानिक तरीके से हवा के जहर को साफ करने की कोशिश है जो कामयाब होगी तो दिल्ली की सांसें लौट आयेंगी। अध्यक्ष जी, करोड़ों रूपये विज्ञापन में उड़े, दिल्ली स्वर्ग बनेगी, डेटा तो जुटाते क्या है प्रॉब्लम। वो डेटा तक नहीं जुटाये। अब दिल्ली में 6 नये वायु गुणवता स्टेशन, 32 रियल टाइम जल निगरानी स्टेशन लगाने का बजट पास किया गया है। अब सही डेटा, सही प्लान, सही काम दिल्ली की हवा पानी इसी साल साफ होगी, इसी साल साफ

होगी। इलेक्ट्रिरिक नीति का ढिंढोरा पीटा लेकिन चार्जिंग स्टेशन कहां है, सबसिडी कहां गयी, रोड टैक्स का क्या हुआ, सब हवा हवाई। सब हवा हवाई कह रहे थे यहां बैठे हुए हवा हवाई इधर आ के सुन लें आज क्या किया है इन्होंने। बैन का एलान किया 15 साल से उपर लेकिन सड़कों पर ये धुआं उगलते रहे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की नेतृत्व में कहा गया कि अब पेट्रोल नहीं मिलेगा 15 साल से उपर डीजल को

(समय की घंटी बजी)

एक मिनट और देंगे बस। इंडिया 2047 में सम्मेलन में हिस्सा लेने का माननीय मुख्यमंत्री जी का प्लान है। आपने ये क्या किया शीश महल बनाया, करोड़ों रूपये एड में बहाये, स्मॉग टावर, आज ही के अखबार की खबर है स्मॉगटावर में कनॉट प्लेस में जंग लगी है जिसमें करोड़ों रूपये एड में गये थे। डीटीसी सुधारने का प्लान ये सब कुछ नहीं किया, फेम स्कीम से मदद लेने की अक्ल नहीं आई ग्रीन कवर सबसे इंपोरटेंट जो अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो मास्टर प्लान 10 प्वाईंट प्लान है ग्रीन कवर दिल्ली में बढ़ाने का भी प्लान है। फेम स्कीम से भी इन्होंने मदद नहीं ली आम पार्टी वालों ने ग्रीन कवर भी कम कर दिया। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं ये दिल्ली के मालिक शीश महल में बैठ कर ऐश करते रहे, दिल्ली जल रही थी, मर रही थी कोरोना में खास तौर से। जब मैं देखता हूं जनवरी 2021 का मैंने सामने देखा कोरोना से मरते हुए लोग जिनकी इम्युनिटी पॉल्युशन से कम थी

उनको निमोनाइटिस थी उनको मर जा रहे थे। ऐसे फ्लाप शो ऑड इवन चला रहे थे स्मॉग टावर लगवा रहे थे तस्वीर खिंचवाने के लिये, करना क्या था सिरसा जी से पूछ लेते जिन्होंने 30 दिन में 10 सूत्रीय प्लान दे दिया माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, लेकिन नहीं इनका तो बस एक ही मकसद था जनता को ठगो और शीश महल में मजे लो। आपने वादे किये जनता को ठगा, दिल्ली को गैस चैंबर बनाकर छोड़ दिया लेकिन अब भाजपा है जो कहती है वो करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वैज्ञानिक तरीके से हवा साफ होगी, डेटा के दम पर नीतियां बनेंगी, ईवी को रफ्तार मिलेगी, दुनिया के साथ कदम मिलाकर पैसा सही जगह लगेगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, दिल्ली को स्वच्छ हरा भरा, प्रदूषण मुक्त बनेगी

दिल्ली और आखिर में बस इतना कहूंगा:

‘‘जब दिल्ली बन गयी थी गैस चैंबर
जनता झेल रही थी तंगी
तब केजरीवाल जी शीश महल में बैठ
बजा रहे थे नीरो जैसी बंसी।’’

थैंक्यू।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री अशोक गोयल।

श्री अशोक गोयलः माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे प्रदूषण की इस चर्चा पर बोलने का अवसर दिया मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। एक्साईज, हैल्थ और डीटीसी के बाद अब जो व्हीकल पॉल्यूशन पे चर्चा हो रही सीएजी की रिपोर्ट पर, इसके लिये मैं आपका और माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। क्योंकि जो सीएजी की रिपोर्ट है ये कुप्रबंधन, अनियमिततायें और अनियमितताओं की वजह से जो भ्रष्टाचार होता है उसके बारे में जानकारी देती है। और ये न केवल पुरानी सरकार जिसने कि पिछले 6-7 वर्षों में जो गलत किया उसके साथ साथ उसके बारे में बताती है, साथ ही साथ आने वाले हम लोगों के लिये भी एक डायरेक्शन इसमें देती है जिससे कि आने वाले दिनों में वो कारण न हो। इस रिपोर्ट में प्रदूषण के कई कारण होते हैं परिवहन, आवासीय साल्वेंट, पावर संयंत्र, सड़कों की धूल और अन्य। लेकिन ये रिपोर्ट सिर्फ परिवहन के क्षेत्र से होने वाले प्रदूषण की चर्चा कर रही है जिसका ओरिजन केवल दिल्ली है कारण भी दिल्ली है जिससे कि जो पिछली सरकार थी वो दूसरों के उपर कारण डालती थी लेकिन ये सिर्फ क्योंकि परिवहन प्रदूषण है इसका ओरिजन भी दिल्ली था और करने वाले भी दिल्ली के थे। दिल्ली की सरकार क्योंकि परिवहन की हम बात कर रहे हैं तो 11 हजार बसों की माननीय अध्यक्ष जी जरूरत थी जिसमें सिर्फ 6750 बसें रही। दिल्ली की जनसंख्या इस दौरान 17 परसेंट बढ़ी लेकिन व्हीकल की संख्या 10 परसेंट घटी और 2137 के दिनों का इसके

अंदर जिक्र है जिसमें 1195 दिन यानि कि 56 परसेंट दिन तो हवा बहुत खराब रही और दिल्ली के अंदर जो व्हीकल थे वो 59 लाख से बढ़ कर माननीय अध्यक्ष जी 1 करोड़ 31 लाख हो गये जिसमें से 81 लाख सिर्फ टू विलर थे जो सबसे ज्यादा प्रदूषण कर रहे हैं। और बहुत सारे चौंकाने वाले आंकड़ें हैं जो मुझ से पहले भी यहां पर माननीय सदस्यों ने दिये जोकि भारी भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करते हैं। 10 अगस्त 2015 से 31 अगस्त 2020 के बीच में जांच में फेल होने के बावजूद भी एक लाख आठ हजार व्हीकल को पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट दे दिया ये भ्रष्टाचार की तरफ बहुत बड़ा इशारा करता है। 76,865 वाहनों को एक मिनट से भी कम जांच के अंदर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट दे दिया गया ये भी एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। 2018-19 से 2020-21 तक माननीय अध्यक्ष जी जो वाहन अपने लाईफ को पूरा कर चुके थे 47,51,000 ऐसे वाहन थे जिनका पंजीकरण रद्द किया जाना चाहिये था लेकिन सिर्फ 2 लाख 98 हजार वाहनों का ही पंजीकरण रद्द किया गया, इससे साफ जाहिर है कि इस सरकार ने प्रदूषण की तरफ ध्यान न देकर भ्रष्टाचार की तरफ ध्यान दिया।

वाहनों को जांच करने के लिए 2 सेंटर थे, एक बुराड़ी और एक झुलझुली। बुराड़ी में सिर्फ मैन्यूअल इंस्पेक्शन किया जाता था और झुलझुली में ऑटोमैटिक मशीन से किया जाता था क्योंकि वहां पर कोई भ्रष्टाचार नहीं हो सकता तो सिर्फ 5 परसेंट वाहनों की जांच झुलझुली में हुई और 95 परसेंट वाहनों की जांच बुराड़ी में

हुई इससे ये पता लगता है कि कितना भ्रष्टाचार पिछली सरकार ने प्रदूषण को ताक पर रखकर भ्रष्टाचार को किया। माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने प्रदूषण को कम करने के लिए कई उपाय लेकर आयें, उन्होंने ये कहा कि मोनो रेल, लाइट रेल ट्रांजिट, इलेक्ट्रिक टॉली, लगातार बजट में, बजट देकर ये बजट में चर्चा करते रहें लेकिन कोई ठोस काम इसके लिए इन्होंने नहीं किया। एक अर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी से इन्होंने टाइअप किया जिसमें उन्होंने कहा कि पूरी दिल्ली का जो प्रदूषण है उसके बारे मेंरियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, पता लगेगा, लेकिन वो यूनिवर्सिटी तो पता नहीं कहां चली गई, बीस में बंद भी कर दिया गया और 87 लाख रुपये उसको और दे दिया गया। तो इतने भ्रष्टाचार लगातार करते रहें, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करते रहें, जीवन से खिलवाड़ करते रहें।

ऑड ईवन का ढोंग लेकर आयें। ग्रैप-3 के अंदर ऑड ईवन लगाया जाता है जो 1, 2, 3 चरण है। 2017 से 20 के बीच में माननीय अध्यक्ष जी 95 बार जो पॉल्यूशन की वजह से जो 95 बार ऑड ईवन लगना चाहिए था लेकिन इन्होंने सिर्फ 5 ही बार ऑड ईवन लगाया और उसमें से भी जो दुपहिया वाहन थे, टू-व्हीलर थे, जोकि करीब 1 करोड़ 30 लाख में से 85 लाख वाहन हैं उनको इम्जेम्प्शन दे दी, यानी कि उस ऑड ईवन का भी मीनिंग इन लोगों ने बिल्कुल खत्म कर दिया।

smog टावर के बारे में चर्चा हुई कि भ्रष्टाचार का अड्डा, 22 करोड़ लगाये लेकिन एक साल के अंदर वो बंद हो गया। पराली

के बारे में जिक्र किया। माननीय अध्यक्ष जी, 40 हजार की पराली, एक घोल बनाया और 22 करोड़ रुपये उसके ऊपर खर्च हुए। मैंने एक हमारे आम आदमी पार्टी के सदस्य मेरे मित्र थे, मैंने कहा ये जो पराली है, आप कहते हो कि पंजाब से जलकर दिल्ली में आती है, जब चंडीगढ़ से चलती है तो रास्ते में करनाल भी आता है, पानीपत भी आता है फिर दिल्ली आता है, वहां पर 200 एक्यूआई है, वहां पर 180 है, ढाई सौ है तो दिल्ली में ये 500 कैसे हो जाता है पराली की वजह से। तो उन्होंने कहा भाई साहब ये जो प्रदूषण है हमारा ये चंडीगढ़ में फ्लाईट पर बैठता है माननीय अध्यक्ष जी और सीधे ही दिल्ली उतरता है। और जब पंजाब में इनकी सरकार आ गई, अब प्रदूषण चंडीगढ़ में बैठता है लेकिन वो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ, उसमें बैठता है और उसके बाद ये उसको ब्लेम करते हैं। ऐसे अनेकों काम, इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ दिखावा किया।

मैं कभी-कभी आदरणीय अध्यक्ष जी ये सोचता हूं कि अगर हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता- नरेन्द्र मोदी जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री- मोदी जी न होते तो इस दिल्ली का हाल क्या होता। उन्होंने केएमपी बनाया, एएमपी बनाया, 70 हजार व्हीकल जो दिल्ली में आते थे वो आना बंद हो गए। मेट्रो लगातार बढ़ती रही, ये बजट रोकते रहे, लेकिन केंद्र की सरकर लगातार मेट्रो को बढ़ाती रही। मेरठ एक्सप्रेसवे बनाया। धौला कुंआ पर कितना बड़ा जाम लगता था वहां पर लूप बनाया। यूबीआर-1 और 2 लगातार जो बन

रहे हैं। दिल्ली जयपुर हाइवे, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे को उन्होंने वाइडनिंग की, अगर ये न होता तो आज दिल्ली सांस लेने के भी काबिल न होती। तो नरेन्द्र मोदी जी का भी मैं इस सदन के माध्यम से बहुत- बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं।

और ये माननीय अध्यक्ष जी ये सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला नहीं, ये लागों की जिंदगियों का भी मामला है। खराब सांस की वजह से अस्थमा नाम की बीमारी जिनको होती है उनकी तो जान ही चली जाती है लेकिन ये फेफड़ों की बीमारी और बच्चों की ग्रोथ को ये इफेक्ट कर रही हैं। एक रिसर्च आई है जिसमें दिल्ली के अंदर खराब सांस की वजह से हर साल कम से कम 10 हजार लोगों की माननीय अध्यक्ष जी प्रीमैच्योर मृत्यु होती हो रही। और कई संस्थाओं ने ये आंकड़ा भी दिया है कि दिल्ली के अंदर खराब सांस की वजह से 5 से 12 साल की उम्र हर आदमी की कम हो गई है माननीय अध्यक्ष जी, आपकी, हमारी..

(समय की घंटी)

श्री अशोक गोयल: भारतीय जनता पार्टी के सभी लागों की, आम आदमी पार्टी के भी सभी कार्यकर्ताओं की और दिल्ली के सभी लोगों की 5 से 12 साल की आयु कम हो गई। मैं माननीय अध्यक्ष जी इस सदन के माध्यम से मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो 10 हजार मृत्यु हर वर्ष हो रही और 3 करोड़ जो दिल्ली के लोग हैं, अगर हम कम से कम मान लें कि

5 वर्ष भी उनकी आयु कम हो गई है तो 15 करोड़ वर्ष की जो ये आयु कम हो गई है इन आपदा की वजह से, आम आदमी पार्टी की सरकार की वजह से और 10 हजार जो लोग हर वर्ष मर रहे हैं इनकी हत्या का मुकदमा भी इस आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ चलना चाहिए माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि ये मामला सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं, दिल्ली के लोगों की जान से खेलने का मामला है, दिल्ली के लोगों के जीवन का मामला है, इसीलिए मैं माननीय अध्यक्ष जी मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जांच के बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसके ऊपर होनी चाहिए। मैं आपका बहुत-बहुत आभार करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री करनैल सिंह।

श्री करनैल सिंहः धन्यवाद अध्यक्ष जी आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। जैसा कि मेरे से पहले सदस्यों ने इस पर ध्यान केंद्रित किया, आपदा सरकार के जो भ्रष्टाचार की वजह से कितने लोगों का जीवन चला गया ये बहुत चिंता का विषय है। आपदा सरकार ने एक बहुत साजिश के तहत इस काम को किया क्योंकि आपदा सरकार की सांठ-गांठ दवाई कंपनियों से थी। जितने भी उन्होंने एक ढकोसला करके प्रदूषण के नाम पर यंत्र लगाने की और उनका प्रचार करने की कोशिश की वो सिर्फ एक ढकोसला था और पर्दे के पीछे वो ये काम कर रहे थे। देशी और विदेशी

दवाई कंपनियां जो थी उनसे सांठ-गांठ कर रहे थे कि लोग जितने बीमार होंगे उतनी उनकी दवाइयां बिकेंगी। इस चीज की पूरी जांच होनी चाहिए जैसा कि मेरे माननीय सदस्यों ने बताया है कि ये सिर्फ प्रदूषण का मामला नहीं है उनके ऊपर हत्या का केस तो होना ही चाहिए। उन लोगों ने इस भ्रष्टाचार के चक्कर में ये भी नहीं सोचा कि ये प्रदूषण के जो पैसा जो खा रहे थे वो उससे उन्होंने अपने बच्चों की भी चिंता नहीं की, अपने परिवारों की भी चिंता नहीं की क्योंकि वो भी उसका हिस्सा थे। चाहे आदमी प्यूरीफायर लगा ले, गाड़ी के अंदर एसी लगा ले लेकिन 24 के 24 घंटे कमरे में नहीं रह सकता उसको बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। उसमें उनके बच्चे भी थे, उनके परिवार भी थे लेकिन भ्रष्टाचार में इतना डूब चुके थे कि वो इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देकर के सिर्फ कमाई की तरफ ध्यान दे रहे थे।

माननीय अध्यक्ष जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान भी मैं इस तरफ आकर्षिक करना चाहता हूं, आज दिल्ली के अंदर प्रदूषण की वजह से कितने बच्चे प्रीडायबिटिज पैदा हो रहे हैं, अगर इस चीज की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, उन्होंने तो जो किया सो किया लेकिन आज हमारी जिम्मेवारी है, इस देश के भविष्य को अगर बचाना है उन बच्चों की भी चिंता हमें करनी पड़ेगी, पर्यावरण की तरफ ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि जीवन दो चीजों पर आधारित है, वायु और पानी अगर वायु नहीं होगी तो आदमी सांस नहीं ले सकेगा और पानी नहीं होगा तो जी नहीं सकेगा। मुझे

लगता है कि सभी प्रगति, सभी विषय तभी चल पाएंगे जब हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा।

अभी मैं एक रिपोर्ट जो सीएजी की रिपोर्ट है उसको मैं पढ़ रहा था। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं 10 अगस्त, 2015 से 31 अगस्त, 2020 के दौरान प्रदूषण जांच केंद्र पर 22. 14 लाख डीजल वाहनों की जांच की गई लेकिन जिसके अंदर से 24 प्रतिशत वाहनों के संबंध में ही जांच मूल्य दर्ज नही हो पाई थी। 4 हजार 7 मामलों में भले ही जांच मूल्य अनुमति सीमा से अधिक थे पर इन सब डीजल वाहनों को पास घोषित किया गया और कोई भी उसके बारे में कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई। 10 अगस्त, 2015 से 31 अगस्त, 2020 तक डाटा बेस के अनुसार 65 लाख 36 हजार, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी वाहनों की जांचजारी की गई लेकिन उसके अंदर सिर्फ कागजों के अंदर इतना दिखाया गया लेकिन असलियत में सिर्फ 1 लाख 8 हजार वाहनों की अनुमति सीमा से अधिक कार्बन-डाईऑक्साइड उत्सर्जित करने के बावजूद भी घोषित किये गये और उनके अंदर कितना नुकसान हुआ आप खुद कर सकते हैं जांच कर सकते हैं।

दिल्ली के प्रति वर्ष 4.1 लाख वाहन की कुल क्षमता केवल 12 प्रतिशत ही स्वचालित फिटनेस जांच केंद्र हैं, जबकि 2020-2021 के दौरान फिटनेस जांच का 95 प्रतिशत मैन्यूअल जांच केंद्र कराया गया जहां वाहन का न केवल निरीक्षण किया जा रहा था और तथा वाणिज्यिक वाहन की फिटनेस घोषित किया जा रहा था जोकि

निरीक्षण अधिकारी की इच्छा पर थी कि वो सिर्फ देख लेते थे कि भई हां इसका निरीक्षण हो गया, खानापूर्ति करते थे, असलियत में कोई काम नहीं होता था। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उन्होंने जो किया वो एक मनुष्य के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ था और मैं सभी सदस्यों की इस बात से सहमत हूं, हत्या का आरोप लगाकर के उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

माननीय अध्यक्षः अब माननीय मुख्यमंत्री/वित्त मंत्री-श्रीमती रेखा गुप्ता जी इस चर्चा पर अपना वक्तव्य रखेंगी।

माननीया मुख्यमंत्री (श्रीमती रेखा गुप्ता): माननीय अध्यक्ष जी, पिछले दो दिन से ये सदन सीएजी रिपोर्ट Performance Audit on Prevention and Mitigation of Vehicular Air Pollution in Delhi इस पर चर्चा कर रहे है। आदरणीय कई सदस्यों ने, सिरसा जी से लेकर के हरीश खुराना, राज कुमार भाटिया जी, सतीश उपाध्याय जी, संजय गोयल जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, अजय महावर जी, मारवाह जी, शिखा राय जी, अनिल गोयल जी, अशोक गोयल जी, करनैल सिंह जी, लगभग 12 सदस्यों ने इस पर चर्चा करी और विपक्ष तो आप देख ही रहे हैं जब भी सीएजी की रिपोर्ट आती है तो कोई न कोई बहाना ढूंढ़के बाहर की ओर दौड़ जाते हैं कि उन्हें ये सब कुछ सुनना ना पड़े, करने में शर्म नहीं आई थी पर सुनने में आती है उन्हें। करने में नहीं आई, सुनने में आती है

इसलिए, चलिए पर फिर भी अच्छा है कुछ शर्म बाकी है। मैं आज उन बातों पर चर्चा नहीं करना चाहती जो उन्होंने किया, वो पूरे सदन ने बार-बार सुना कितनी बसिसज की जरूरत थी, किस तरीके से पैसे का दुरुपयोग या ना उपयोग करते हुए उन्होंने दिल्ली को व्हीकल से दूर रखा, कैसे मोनिटरिंग एंफोर्समेंट और पोलिसी मेकिंग में पिछली सरकारों की कमी रही, जो काम करने चाहिए थे वो किए नहीं, जो नहीं करने चाहिए थे वो किए। कुल मिलाकर के दिल्ली का इतना बड़ा नुकसान हुआ जिसका जिक्र बार-बार माननीय सदस्यों ने किया की दिल्ली की उम्र घट गई दिल्ली को बीमारियाँ लग गई और वो नुकसान हुआ जिसकी भरपाई आर्थिक रूप में नहीं की जा सकती। पर जो पिछली सरकारों ने किया, वो नुकसान आगे ना हो और जो ये नई सरकार जनता के हित में काम करे वो बहुत ही पहले दिन से ही सोच-समझ के और दिल्ली के हित में हर कदम उठाए और वायु प्रदूषण की दिशा में ठीक से काम करे इसकी चिंता हम सब कर रहे है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज की डेट में 6,484 बसिसज सड़कों पर दौड़ रही है। जबकि 11 हजार बसिसज का रिक्वायरमेंट दिल्ली को है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी दिशा में आदेश किए है, जिसमें से डीटीसी की 2400 बसें सीएनजी हैं और लगभग 1727 बसें ईवी हैं और डिमस की 1750 बसें सीएनजी है और 400 बसिसज ईवी हैं। इन सारी बसिसज के होने के बावजूद भी 6,484 इस साल के आखिरी में ये बसिसज केवल 3850 रह जाने वाली

हैं क्योंकि 3 हजार बसिसज जो हैं इस दिसम्बर तक रिटायर हो जायेंगी। ये 3,850 बसिसज जो रह जाएगी इसकी संख्या फिर से किस प्रकार से बढ़ाई जाएगी उसकी प्लानिंग हमने की है कि आते ही सरकार के गठन के तुरंत बाद हमने 2800 बसिसज का ऑर्डर पलेस किया और ईवी बसिसज। तो इस साल के आखिरी तक हम जो 3850 बसिसज रह जाएंगी वो, उसमें 1500 बसिसज और ईवी व्हीकल और 2800 बसें ये जोड़कर के कोशिश करके लगभग साढ़े 5 हजार बसिसज ये इस साल के आखिरी तक उसे मेंटेन करेंगे और 2026 तक पूरी 11 हजार बसिसज को ओन रोड हम लेकर के आएंगे, इस काम के लिए दिल्ली सरकार दृढ़ संकल्प में है। किसी भी तरह की कोई कोताही उसमें ना रहे, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा कि पूरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिल्ली को उसकी बसिसज दी जाए। जितना रूट rationalization है कि जो रूट पर कम चल रही थी बसिसज कहीं कम कहीं ज्यादा, जहां जरूरत है वहां नहीं जाना और जहां नहीं जरूरत है वहां पे खड़े रहना, इस पूरे रूट को दुबारा सा मॉनिटर करते हुए बसिसज को चलाया जाएगा ताकि optimum utilization संसाधनों को हो सके और हर प्रकार से पूरी दिल्ली के हर कोने तक हमारी पब्लिक ट्रांस्पोर्ट की सेवाएं पहुंच सके। मैंने आपको पिछली बार जिक्र किया था कि कैसे डिम्स के शेयरको जो 100 करोड़ रुपए का था उसको 10 करोड़ रुपए में बेच दिया गया है, हम आज इस सदन के माध्यम से कहते हैं इसे भी हम लीटिगेसन में चेलेंज करेंगे और शेयर को वापस लेकर

आएंगे। किसी को कोई अधिकार नहीं है कि सरकार के पैसे का दुरुपयोग करे या सरकार के शेयर को बेच खाए, हम उस शेयर को वापस लेकर आएंगे अध्यक्ष जी। इसके अलावा ईवी बसिसज दिल्ली की सड़कों पे दौड़ाने के लिए उनके चार्जिग स्टेशनस और डिपोज का भी होना बहुत महत्वपूर्ण है। आज वर्तमान में 77 डिपोज दिल्ली में है, उन सबको जितनी बसिसज हमारी सड़कों पर रहेंगी उसके हिसाब से अपडेट करने के लिए चार्जिंग स्टेशनस और चार्जिंग पूवाइंट की संख्या हमारा ये टारगेट है कि 2026 तक इसे हम 18 हजार सार्वजनिक चार्जिंग पूवाइंट और 30 हजार प्राइवेट प्लस सेमी प्राइवेट चार्जिंग पूवाइंट बनाएंगे जो कि वर्तमान में केवल उसका 10 प्रतिशत है, 4,793 इस टाइम सरकारी और गैर सरकारी मिलाकर के चार्जिंग पूवाइंट है जिसे मैंने आपको बताया की 48 हजार चार्जिंग पूवाइंट पर हम लेकर जाएंगे ताकि दिल्ली की इलैक्ट्रिक व्हीकल व्यवस्था को दुरूस्त कर सके। अध्यक्ष जी हम इसके अलावा ये तो बात हो गई पब्लिक सैक्टर की परन्तु केवल पब्लिक सैक्टर से काम चलने वाला नहीं है, जनता जो अपने प्राइवेट व्हीकल खरीदती है उसको भी हमें इलैक्ट्रिक व्हीकल की ओर लेकर जाना पड़ेगा इसके लिए सरकार की ओर से इलैक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी बनाई जाएगी जिसमें अधिक से अधिक प्रोत्साहन जो है जनता को दिया जाएगा ताकि वो लोग इलैक्ट्रिक व्हीकल लें उसका उपयोग करें और इस पूरे के पूरे वायू प्रदूषण को कम करने की दिशा में पूरी दिल्ली एकमुश्त, एक साथ होकर के खड़ी हो,

अभी वर्तमान में जितना टोटल व्हीकल दिल्ली में लगातार खरीदा जाता है पिछली सरकार का मैं आपको फिगर बताती हूं 6 लाख 80 हजार टोटल व्हीकल खरीदा गया है और उसमें से 11 प्रतिशत उसका मात्र 78 हजार व्हीकल, जिसमें स्कूटर की बहुतायत है, वो ईवी था। तो हम चाहेंगे कि जनता इस ओर प्रोत्साहित हो की अधिक से अधिक इलैक्ट्रिक व्हीकल वो ले और उनका इस्तेमाल करे, ये हमारे एजेंड़ा में है। पुराने व्हीकल की बात भी मैं बताना चाहूंगी कि पुराने व्हीकल जो कि 10 साल पुराने डीजल के हैं या 15 साल पुराने पेट्रोल के व्हीकल हैं उसमें पूरी तरीके से अनुशासनात्मक कार्रवाई हो कि जहां जो पोलिसी के अंतर्गत उस पर बैन है उसको लागू किया जाना चाहिए। बहुत मजेदार बात बताती हूं अध्यक्ष जी, पिछली सरकार की मॉनिटरिंग की कैपिसिटीज की एक बस यदि ब्रेकडाउन हो गई किसी सड़क के कोने में खराब हो गई, वो थी नांगलोई की बस और साउथ दिल्ली में चल रही, साउथ दिल्ली में खराब हो गई तो खड़ी रहती थी वो बस की नांगलोई से कोई बस ठीक करने के लिए आएगा और तब वो बस ठीक होगी और फिर जाकर, क्योंकि तब तक ट्रैफिक कंजेशन, तब तक पॉल्यूशन हर पूरी हो असुविधा जनता को होती थी जिसकी ओर किसी का ध्यान नहीं था। उसके बाद किसी व्हीकल में चार्जिंग खत्म हो गई तो जहां की वो बस शुरू हुई वो वहीं वापस जाएगी, फिर चार्जिंग लेगी और उसके बाद आगे काम करेगी तो आप समझिए की इस पूरे प्रोसिजर में कितना ज्यादा समय का, साधनों का दुरुपयोग होता

था, इन सारे छोटे-छोटे points को वर्तमान की सरकार कैटरिंग करेगी और जहां पे है इनके लिए समाधान देगी की भई अगर आपको बस ठीक करने के लिए जो कर्मचारी है वो आपको इमीजिएट जो लोकल आपका बस डिपो है अगर वहीं से आता है तो उसमें क्या दिक्कत है। अगर आपको बिल्कुल नजदीक स्टेशन से, नजदीक के डिपो से चार्जिंग मिल जाती है तो आप क्यों नहीं लेंगे उसको। ऐसे छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कारण जो कि प्रदूषण से जुड़ा हुआ है उन सबको सरकार ध्यान में करके काम करने वाली है और ये केवल दिल्ली के अंदर के व्हीकलस का मामला नहीं है, वो जो लाखों व्हीकल दिल्ली के सारे बॉर्डर से दिल्ली के अंदर रोज आते हैं उसके अंदर आने के बाद में उनका क्या पोल्यूशन लेवल है, वो किस पैरामीटर पर चल रहे है, इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं है। कौन व्हीकल आया, कितना पॉल्यूशन दे गया कोई चैक करने वाली अथोरिटी नहीं है, ना इनके पास स्टाफ है, ना इनके पास पोलिसी थी, ना ये इस काम करने की मानसिकता था। अब हम नई सरकार की ओर से दिल्ली से बाहर से आने वाले व्हीकल जो दिल्ली की बाउंड्रीज में आते हैं उनके लिए भी एक नई पोलिसी लाएंगे की उनके लिए कौन सा पोल्यूशन सर्टिफिकेट लागू होगा, उनको क्या-क्या मायने होंगे, उन्हें क्या-क्या करना होगा दिल्ली में आने से पहले, ताकि दिल्ली में आने वाला एक भी व्हीकल ऐसा ना हो जो दिल्ली को पोल्यूशन देके जाए इसकी पूरी योजना हम करेंगे। आपने बहुत सारे हमारे

साथियों से सुना की कैसे रजिस्ट्रेशन देने के लिए, कैसे पोल्यूशन सर्टिफिकेट के लिए धांधले बाजियाँ हुई। ये अड्डा बन गया भ्रष्टाचार का, परन्तु नई सरकार की ओर से एंड ऑफ व्हीकल के लिए जो रजिस्ट्रेशन है या रिन्यूवल के लिए या पोल्यूशन सर्टिफिकेट के लिए जितने भी पैरामीटर है उनको शक्ति से लागू किया जाएगा और थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराई जाएगा ताकि कोई भी किसी भी तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो और हर तरीके से जेन्यूइन सर्टिफिकेशन, सारे के सारे हमारे व्हीकलस को दिया जाए। इसके अलावा 500 नए कैमरे ट्रैफिक जंकशनस प्वाईंट्स पर लगाए जाएंगे। जो की सरकार का जिसमें हम एक रुपया भी खर्च करवाने वाले नहीं है, पीपीपी मॉडल पर इसको लेकर आएंगे, इसके लिए हमने एजेंसिज को इन्वाइट भी कर लिया है और हमारे पास बिड भी आनी शुरू हो गई है कि ऐसे 500 कैमरा जब ट्रैफिक जंकसनस पर लगेंगे तो ना केवल हमें जो ऐसे व्हीकल ध्यान में आ जाएंगे जिनका की tenure पूरा हो चुका है, बल्कि ट्रैफिक के कारण वाले व्हीकल भी पोल्यूशन करिएटिंग व्हीकल भी, और अन्य भी अनेक प्रकार की सुविधाएं हमारे इन कैमराज से हमें पता चलेगी जो इनडायरेक्टली-डायरेक्टली इस पूरे के पूरे वायू पोल्यूशन में मदद करने वाला है, इसको कम करने के लिए। आईएसबीटी मैंने अपनी बजट स्पीच में कहा, आईएसबीटीज जो हमारे हैं, जहां पर मेन अड्डा रहता है, ट्रैफिक का, बसिसज का और बहुत ज्यादा कंजेशन वहां हो जाता है, उनको हम outskirts में, दिल्ली के outskirts में

लेकर के जाएंगे ताकि जो सैंटर आफॅ दा हार्ट है जो दिल्ली का बिल्कुल मध्य एरिया है वहां पर ट्रैफिक का जाम ना लगे और वहां पॉल्यूशन भी ना हो। इसके अलावा मैट्रो के फोर्थ फेस के लिए, फिफ्थ फेस के लिए हमने अपने बजट में 3 हजार करोड़ रुपए रखे हैं जो कि हम पब्लिक ट्रॉसपोर्ट की ओर लोगों को लेकर जाएंगे और धीरे-धीरे अपने प्राइवेट व्हीकलस को जनता कम करें और इस तरीके से पूरी योजना की हम कैसे एयर पोल्यूशन को कम करेंगे। लगे हाथ एयर पॉल्यूशन की दिशा में केवल व्हीकल एकमात्र कारण नहीं है, इसके अलावा जो डस्ट पार्टिकल इसका कारण रहते हैं, उसके बारे में भी जरूर मैं लगे हाथ बताना चाहती हूं कि ये जो डस्ट पार्टिक्ल जो एयर पॉल्यूशन करिएट करते हैं इसमें हमें रोड डवलपमेंट का समग्र विकास कि जहां गड्ढ़े हैं उन गड्ढ़ों को ठीक करना, जहां नई बनाने की आवश्यकता है वहां नया करें, जो ब्राउन एरिया है, जो खुला एरिया है, मिट्टी वाला एरिया है उसको भी हम कवर करें। चाहे पौधों से कवर करें या उसपे टाइल वर्क, सीमेंट वर्क जो भी वहां पे रिक्वायर्ड है इस तरीके से पूरी योजना बनाते हुए हमने अलग अलग हैड में बहुत अच्छे से इसकी योजना बनाकर के काम करने का प्रयास करेंगे। हम डस्ट पार्टिकल्स को कम करने के लिये आपको मैं ध्यान दिलाना चाहती हूं कि पिछली जो सरकार है जो water sprinklers चलाती थी सरकार नहीं चलाती थी, सरकार नहीं चलाती थी सब कुछ एमसीडी के जिम्मे कर रखा था, एमसीडी को सरकार कहती

थी कि भई हम आपको पैसा दे रहे हैं और आप water sprinklers, smog guns ये सब चलाईये पर सरकार ने दिया नहीं और एमसीडी ने किया नहीं। एक भी एंटी smog गन एमसीडी के माध्यम से उस समय चली नहीं। water sprinklers जेई के स्टोर में खड़े रहे, परंतु उन्होंने कोई काम नहीं लिया तो वायु प्रदूषण होना ही था। और वो भी साल के दो महीने की योजना बनती थी। केवल सर्दी के वो दो महीने जैसे कि पॉल्यूशन उसी समय होता है जबकि हम सब देख रहे हैं कि आज यदि गर्मी से पहले का मौसम है या 12 महीने पॉल्यूशन एक समस्या बना रहता है। आपका एक्यूआई हमेशा इस स्थिति पे रहता है कि जिसको हर वक्त निगरानी करने की और उसपे काम करने की आवश्यकता है। हमारी सरकार ने ये योजना बनाई है कि हम एक हजार वाटर water sprinklers machines एक हजार water sprinklers machines को लेंगे, ढाई सौ वार्ड हर वार्ड पे लगभग 4 मशीनें हम देंगे और ये पूरा का पूरा काम दिल्ली सरकार स्वयं करेगी, अपने एजेंसीज के माध्यम से करेगी, हम किसी के भरोसे रहने वाले नहीं हैं। हम स्वयं ये सारी मशीनें चलायेंगे। और इसी तरीके से 70 विधान सभाओं पे 70 सिस्टम जिसमें कि mechanical road sweeping integrated with water sprinklers and smog guns की एक ऐसी बड़ी मशीन जिसमें कि आपकी mechanical sweeping भी होगी, जिसमें आपका वाटर स्प्रिंक्लर भी होगा, और जो एंटी smog गन भी उसी में जुड़ी होगी, ऐसी 70 मशीनों के साथ हमने पूरा प्रोजेक्ट बना के

300 करोड़ रूपये का फंड अपने इस बजट में रखा है ताकि पूरा और ये दो महीने की योजना नहीं है अध्यक्ष जी, ये पूरा साल भर की योजना रहेगी जोकि सड़कों पे हमारे काम करेगी और दिखाई देगी। ये सारे के सारे हम एयर पॉल्यूशन के तहत हमारी सरकार का पूरा एजेंडा जो हम करने वाले हैं बार बार कभी मीडिया, कभी बाकी लोग पूछते हैं कि आप पॉल्यूशन को कम करने के लिये क्या करेंगे तो आज इस हाउस के माध्यम से मैं आपका, पूरी सरकार का एक विजन, एक पूरा ले आउट प्लान आपके सामने ये चर्चा कर रही हूं। इसके अलावा integrated command and control center जो कि एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, वेस्ट मैनेजमेंट हर चीज का ध्यान रखेगा कि दिल्ली के हर कोने में कहां पे किस तरह की समस्या हमें दिखाई दे रही हे और उसका समाधान तो ऐसा integrated command and control center जो आज तक की सरकारों ने कभी ध्यान नहीं दिया उसको इस बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की ये सरकार अपने इस सेशन में चलायेगी। एनवायरमेंट पैरामीटर मॉनिटरिंग बहुत ही स्टरांग तरीके से इसको हम करने वाले हैं जो अभी 40 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस लगे हुए हैं। इसके अलावा देखिये वो जो मैंने खुद नक्शा मंगवा करके उसको जब देखा तो वो मैंने देखा कि बहुत ही कंजेस्टिड एरिया में है और जोकि एक्चुअल आपका रियल टाईम वैल्यू नहीं दिखाता, आप ऐसी जगह पे वो स्टेशंस लगे हुए हैं और बहुत पुराने लगे हुए हैं कोई 2010 के टाईम का, आज की परिस्थितियां बदल चुकी हैं, आज

हो सकता है वहां पे उसके पास में कोई नयी बिल्डिंग खड़ी हो गयी हो, कोई नया पेड़ उग आया है तो वो जो एयर क्वालिटी उसको दिखानी है उसका मापदंड वो सही प्रकार से नहीं आ पा रहा इसलिये हमने 6 नये एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस और लगाने का फैसला लिया है जिससे कि पूरी दिल्ली की मॉनिटरिंग एक वायु गुणवता जो है उसका असली पैमाना आ जाये और उसको हम अच्छे से स्टडी कर सकें। इसके अलावा धूल का एक बहुत बड़ा कारण हमारा सीएनडी वेस्ट भी होता है। आज की डेट में सीएनडी वेस्ट प्रोसेसिंग का हमारे पास केवल 5 हजार टन का प्लांट है जिसमें हम सीएनडी वेस्ट को प्रोसेस कर सकते हैं। पर वो भी नहीं हो पाता है। वो भी यूटिलाइजेशन नहीं है न वो सीएनडी वेस्ट सड़कों से उठता है न वहां जाता है, न उसको प्रोसेस किया जाता है, सब कुछ कागजों में चल रहा है परंतु आज मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि इस सीएनडी वेस्ट प्रोसेसिंग स्टेशंस को इसकी हम जो कैपेसिटी है उसको और एक हजार टन बढ़ा के 6 हजार तक ले के जायेंगे और पूरी तरीके से सड़कों से वेस्ट उठे, वो मलबा उठे, स्टेशन तक पहुंचे, प्रोसेस हो, और उसमें से जो टाईल बने या जो सामान बनके निकले उसका पूरा उपयोग हो इसकी क्लोज मॉनिटरिंग की जायेगी और उसको पूरी तरीके से workable किया जायेगा। ऐसे ही लैंडफिल साईट्स, वर्षों तक पिछली सरकार केवल गाना गाती रही कूड़े के पहाड, कूड़े के पहाड़, कूड़े के पहाड़ के बाहर जाके फोटो खिचवाते थे, फिर डालते थे, फिर

कहते थे मैं खत्म कर दूंगा, एक साल में खत्म कर दूंगा, 6 महीने में खत्म कर दूंगा, छड़ी घुमाउंगा हो जायेगा। केवल बातों से नहीं हो सकता अध्यक्ष जी, इसके लिये काम करना पड़ता है और आप ध्यान कीजिये मैं माननीय सदस्यों को भी बताना चाहती हूं कि इन लैंडफिल साईट्स के उपर काम करने के लिये जो फंडिंग थी हमेशा स्वच्छ भारत मिशन से 80 प्रतिशत फंडिंग स्वच्छ भारत मिशन के तहत केंद्र सरकार के द्वारा की गयी तो भी इन्होंने काम नहीं किया, इनको खर्चे की चिंता नहीं थी केवल काम करना था वो भी इनके बस की नहीं थी इन्होंने काम नहीं किया केवल पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि time bound removal of these three landfills sites will happen इसको हम करेंगे और लगातार इसके उपर हमारा हर तीन महीने में इसका कितना एरिया हमने और इसको कवर कर लिया, कितना हमने इसमें से मैटिरियल उठा दिया है इसको हम पूरी तरीके से ध्यान करेंगे। कंस्ट्रक्शन साईट जो डस्ट में एक बडुत बड़ा पार्टिकल रहता है वो कंस्ट्रक्शन साईट पे भी पूरी तरीके से निगरानी रखते हुए वहां पे नियम कायदे कानूनों को लागू किया जायेगा। एक और चीज मैं इसमें जोड़ना चाहती हूं जैसे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट हमारे चल रहे हैं कूड़े का निष्पादन एनर्जी में कंवर्ट करके किया जा रहा है। उसका भी पूरी तरीके से उसका यूटिलाइजेशन हो उन प्लांटस का जरूरत के अनुसार नया प्लांट खुले उसकी भी हम चिंता करेगें और एक नया ई-वेस्ट के उपर एक नया इको पार्क जिसमें कि पूरे के पूरे शहर का ई-वेस्ट प्रोसेस

करने का काम दिल्ली सरकार करेगी क्योंकि वो ई-वेस्ट जो है दिल्ली में ऐसे कई जगह हैं खासकर यमुनापार की तरफ ई-वेस्ट के ऐसे ऐसे लोगों ने अडडे बनाए हुए हैं जहां वो उसको जलाते हैं और उसका जो धुआं होता है वो सबसे खतरनाक होता है। ये वो साइट है एयर पोल्यूशन की जिसकी ओर कभी कोई काम नहीं हुआ तो हमारे कार्यकाल में इकोपार्क जो है ई-वेस्ट को मैनेज करने के लिए उसको समाप्त करने के लिए साइंटिफिक तरीकों से हम इस पूरे ई-वेस्ट को मैनेज करेगें इसको खत्म करेगें और वो भी बिना एयर पोल्यूशन के ये इस सरकार का ध्येय है अध्यक्ष जी मैं आज आपके माध्यम से पूरी जनता को दिल्ली की जनता को बताना चाहती हूं ना केवल इतना इसके अलावा तीसरा पोजीटिव काम कि दिल्ली में हरित दिल्ली, ग्रीन दिल्ली, पौधे लगे इससे पहले कि सरकारें पौधे लगाती थी परंतु कागजों में। मैं आपको अपनी शालीमार बाग विधानसभा का बताती हूं पिछली सरकार की पिछली विधायक ने आठ करोड़ रूपये का टैंडर उठाया कि पौधे लगाएगें सेंट्रल वर्जेज में एक भी पौधा पूरे क्षेत्र में कहीं लगा नहीं एक भी पौधा नहीं लगा। ऐसा हर जगह है पूरी दिल्ली में हर जगह हुआ है कि कागजों पे पौधे लगे, उगे पर जो फल निकला वो सरकार के ये लोग खा गए। कोई सरकार ने जो किया जनता को उसका एक परसेंट भी लाभ मिला नहीं। हमारी सरकार ने 70 लाख नए पौधे लगाने का काम करेगें ऐसा हमने प्रण किया है और वो भी अकेले देखिए मैं ये मानती हूं कि ये जो plantation drive

है 70 लाख पौधे कोई सरकारी कर्मचारी अकेले नहीं लगा सकते। कोई सरकारें नहीं लगा सकती जब तक की आप उसमें समाज को इनवाल्व ना करें और ये हम पूरी योजनाबद्ध तरीके से school students को institutions को सामाजिक संस्थाओं को, सोसाइटी को सबको इनवाल्व करते हुए हम ये 70 लाख पौधों का जो टारगेट है इसको अचीव करेगें। दिल्ली में पौधे लगाएगें और पर्यावरण रक्षक नाम से एक नई टीम एक नए योद्धा खड़े करगें जो दिल्ली के पर्यावरण की रक्षा करने के लिए आगे आएगें और उनके लिए हम समय समय पे अलग अलग उनको सम्मानित करने के कार्यक्रम भी करेगें ताकि ये जो दिल्ली को स्वच्छ, सुंदर, पोल्यूशन फ्री बनाने का जो टारगेट है वो केवल सरकारों का ध्येय नहीं है केवल सरकारों का लक्ष्य नहीं है। ये दिल्ली पूरी दिल्ली की इसमें इंवाल्वमेंट हो। पूरी दिल्ली इसमें शामिल हो। हर दिल्लीवासी का ये लक्ष्य हो इस दिशा में हम काम करेगें अध्यक्ष जी ये केवल सीएजी की रिपोर्ट ने जो बताया वो हम सबने सुना, हम सबने देखा कितनी शर्मनाक तरीके से सरकारों ने इसपे काम किया और शर्म की बात और ये भी है कि वो अपने कर्मों को देखना नहीं चाहते। रोज एक नया मुददा ले आएगें, जनता का ध्यान भटकाने के लिए। भई आप अपने घर के आप पूरे इस हाल की लाइट बंद करके बैठ जाइए मोमबत्ती जलाके आपको कौन पूछ रहा है। आप कभी कुछ बोल देते हैं आप कभी कुछ बोल देते हैं, कौन कह सकता है आपको कोई देखने वाला है कि जी आपका पावर कट

हुआ है फोटो डाल दी मैडम ने मोमबत्ती लगा के। मेरा भी आज कैंडल लाइट डिनर करने का मन कर रहा है मैं भी लगा लेती हूं। मैं भी वो फोटो डाल दूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे घर में लाइट नहीं है। अब इसके उपर भी सीएजी रिपोर्ट बैठानी पड़ेगी कि मैडम ने ऐसा किया, क्या किया तो ये बड़ा गलत तरीका है दिल्ली की जनता को गुमराह करने का परंतु हमारी सरकार पोजीटिव तरीके से, पोजीटिव दिशा में काम करेगी इसका मैं दिल्ली की जनता को और इस पूरे सदन को विश्वास दिलाती हूं और अपनी बात को आप देखो एक ट्रैंड शुरू हो गया है आखिरी में एक शेर बोलना बहुत जरूरी है।

अब तो मारवाह जी ने भी बोलना शुरू कर दिया है तो बोलना ही पड़ेगा–

''कि ये जो नए मंसूबे हैं कि ये जो नए मंसूबे हैं
ये जो नई तामीरें हैं, जो हमने इतना बड़ा ले–आउट प्लान बताया है।''

''कि ये जो नए मंसूबे हैं ये जो नई तामीरें हैं
आने वाली कल की कुछ धुंधली सी तस्वीरें हैं
आने वाले कल की कुछ धुंधली सी तस्वीरें हैं।
हम ही रंग भरेगें इनमें, हम ही रंग भरेगें इनमें

हम ही इन्हें चमकाएगें, नवयुग आप नहीं आएगा

नवयुग आप नहीं आएगानवयुग को हम लाएगें।

नवयुग को हम लाएगें।''

बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अधयक्षः माननीय सदस्य गण सदन ने वर्ष 2021 में समाप्त हुए वर्ष के लिए दिल्ली में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम और शामन की performance audit पर सीएजी की रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा की है। रिपोर्ट में दिल्ली की जनता से जुड़ी महत्वपूर्ण समस्या यानि प्रदूषण और विशेष रूप से वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर चर्चा की गई है सीएजी ने यह सही कहा है कि वाहनों से होने वाला उत्सर्जन प्रदूषण का प्रमुख स्त्रोत है जो दिल्ली में हुआ और इसे तत्कालिक दिल्ली सरकार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता था। सरल शब्दों में यह एक ऐसी समस्या थी जिसका समाधाान पूरी तरह से तत्कालीन सरकार के दायरे में था

इसके बावजूद त्तकालीन दिल्ली सरकार इसे नियंत्रित करने में विफल रही जैसा कि सीएजी ने सुझाव दिया है शहरी परिवहन प्रणाली में सुधार, बुनियादी ढांचे में निवेश के माध्यम से परिवहन मोड में बदलाव एनफोर्समेंट सिस्टम को मजबूत करना जैसी कई ऐसी रणनीतियां थीं जिनका उपयोग वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए किया जा सकता था। रिपोर्ट में वाहनों से होने

वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा किये गए प्रयासों में विभिन्न कमियों की ओर इशारा किया गया है। इनमें से कुछ इस प्रकार है। सरकार के पास वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली के लिए कोई प्रभावी तंत्र या बुनियादी डाटा तक नहीं था। सरकार ने सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार के लिए कोई कदम नहीं उठाया और बड़ी संख्या में डीटीसी बसें सड़कों पर नहीं उतरीं। बजट प्रावधान रखने के बावजूद मोनो रेल, लाईट रेल ट्रांजिट या इलैक्ट्रिक ट्रोली जैसे बसों जैसे सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के वैकल्पिक तरीको को शुरू करने के लिए कोई पहल नहीं की गई। प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्रों में गम्भीर अनियमिततायें थीं। प्रदूषण जांच केन्द्रों का कोई निरीक्षण नहीं किया गया। 18-19 में 64 प्रतिशत वाहनों का फिटनेस चैक किया जाना था, लेकिन उन्होंने फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं लिया और 90 प्रतिशत से अधिक फिटनेस टेस्ट केवल दृश्य निरीक्षण visual inspection के आधार पर किये गए जिससे टेस्टिंग की प्रक्रिया व्यर्थ हो गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए अप्रैल 2020 में बीएस-3 और बीएस-4 वाहनों का पंजीकरण किया गया। 47.51 लाख जीवन समाप्ति वाले वाहनों में से जिनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाना था उनमें से वास्तव में केवल 2.98 लाख वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया। ऑड ईवन ट्रकों पर प्रतिबंध, इलैक्ट्रॉनिक ब्हीकल की शुरूआत जैसे उपायों को ठीक तरह लागू नहीं किया गया। माननीय सदस्यगण ऐसा लगता है कि विज्ञापनों और मीडिया में किये गए बेबुनियादी दावों के

विपरीत तत्कालीन सरकार ने दिल्ली के लोगों को वाहनों से होने वाले प्रदूषण से बचाने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया जिससे जानलेवा बिमारियों सहित गम्भीर कठिनाइयां सामने आ रही हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लोक लेखा समिति को इस रिपोर्ट की गहन जांच करनी चाहिए और उन व्यक्तियों की पहचान करनी चाहिए जो अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहे। रिपोर्ट की सामग्री के अनुसार तत्कालीन सरकार की ओर से गंभीर खामियां की गई प्रतीत होती हैं। पीएसी तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और सभी विभागों को सदन ये निर्देश देता है कि एक महीने के भीतर अपने एक्शन टेकन नोट प्रस्तुत करने का एक्शन टेकन नोट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है।

अब इसमें हमारा ये अनुरोध है कि इसमें चूंकि ये चर्चा अल्पकालिक चर्चा जिस पर कल सूर्य प्रकाश खत्री जी ने अपना वक्तव्य दिया था और दो सदस्य इसमें और जिन्होंने इस नोटिस को दिया था। जिनमें मोहन सिंह बिष्ट और श्री राजकुमार भाटिया तो अब सदन के समक्ष है कि अगर दो सदस्यों को बुलवाके और मंत्री जी उस पर अपनी टिप्पणी दे दें तो ये हमारा कम्पलीट हो जायेगा।. नहीं, देखिए ऐसा है ये पिछले सत्र में आया था इस सत्र में रिकॉर्ड पे है। अब ये इसको रिकॉर्ड से वाइन्डअप करना चाहिए, क्योंकि उसमें दो-दो मिनट आप अपनी बात कहके और आप दो मिनट करके इस सब्जेक्ट को क्लोज कर देते हैं। ठीक है मंत्री जी।

अल्पकालिक चर्चा (नियम-55)

श्री मोहन सिंह बिष्ट: अध्यक्ष जी सूर्य प्रकाश खत्री जी द्वारा सदन के अंतर्गत एक अप्रैल को दिल्ली में पीने के पानी की कमी और जलभराव तथा सीवरेज के रूकावट तथा नालियों के संबंध में चर्चा प्रारम्भ करने के लिए आपसे अनुरोध किया था। अध्यक्ष महोदय ये सत्य है कि दिल्ली के अंतर्गत पीने के पानी की गंभीर समस्या ये आने वाले दिनों के अंतर्गत एक बिकराल रूप ले सकती है। अध्यक्ष महोदय ये सत्यता तो ये है दिल्ली के पास ना तो अपनी कोई नदी है, ना कोई पानी के स्त्रोत है, ना दिल्ली को पड़ोसी राज्यों पर निर्भर होना पड़ता है। तब दिल्ली को पीने का पानी मिलता है। अध्यक्ष महोदय ये भी सत्य है कि दिल्ली के लिए यदि पानी की किसी ने चिंता की थी तो मेरी सरकार 1993 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उस समय में इसकी चिंता की गई। चिंता ही नहीं दिल्ली को किस प्रकार से पीने का पानी मिले, दिल्ली के लोगों का गला कैसे जो सूख रहा था उनको स्वच्छ गंगाजल मिले ये मेरी पार्टी ने किया था। अध्यक्ष महोदय ये भी सत्य है कि दिल्ली जैसी महानगरी जिसका अपना पानी ना हो, जिनके अपने संसाधन दूसरे प्रदेशों से पानी लेकर के आना हो। हमें दूसरे पे डिपेंड रहने के लिए अपने यहां भले ही इस क्षेत्र के अंतर्गत भागीरथी ट्रीटमेंट प्लांट अध्यक्ष महोदय ये जब मेरी सरकार थी तो भागीरथी ट्रीटमेंट प्लांट में 80 एमजीडी पानी ट्रीट किया जाता था। इसी सदन के अंदर जब कांग्रेस की सरकार

थी और पानी वेस्टेज हो रहा था हमने उस समय में एक बात कही थी। हमने कहा साहब इसका पूरा पानी वेस्टेज हो रहा है इस पानी को एक्सट्रा और ट्रीट किया जाए जिससे दिल्ली के लोगों के प्यास की समस्या का समाधान हो। अध्यक्ष महोदय ये ही नहीं इसी सदन के अंदर जब मेरी सरकार थी, हमारी सरकार ने योजना बनाई थी। उत्तर प्रदेश के साथ समझौता हुआ। समझौता होने के बाद हमारे यहां पे गंग नहर के माध्यम से 140 एमजीडी पानी का लेने, लाने का काम किसी ने किया तो उस समय की तत्कालीन सरकार भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुआ। अध्यक्ष महोदय इसी सदन के सदस्य जो हमारे उस समय में और अब पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय साहिब सिंह वर्मा जी द्वारा इसी क्षेत्र के अंतर्गत आपने देखा होगा कि हरियाणा से पानी लाकर के जो दिल्ली के दूसरे शहर के अंदर ये मुनक नहर से पानी लाने का काम किसी ने किया ये भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुआ। इसकी प्लानिंग बनाई गई। अध्यक्ष महोदय ये प्लानिंग बनाने की देन सिर्फ थी भारतीय जनता पार्टी की। हरियाणा ये पानी, पंजाब से पानी, हिमाचल से पानी ये इस प्रकार से लाया गया। अध्यक्ष महोदय वर्तमान स्थिति क्या है कि दिल्ली को 1300 एमजीडी के आसपास पीने का पानी चाहिए, लेकिन आज सप्लाई जो सिर्फ हो रही है ये 990 एमजीडी। अध्यक्ष महोदय यहां पे बराबर में वो सरकार बैठी थी जिन्होंने पानी के नाम से घोटाला किया और घोटाला नहीं दिल्ली के लोगों को प्यासा रहने के लिए मजबूर किया। अध्यक्ष महोदय मैं पिछले दिनों के

अंदर बार-बार कहता था और मुझे जो समय याद था कि 2017 के अंतर्गत इस दिल्ली की प्यास बुझाने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश गवर्मेंट से एक करार हुआ था वो करार का एक वो था कि हम दिल्ली को हम 150 एमजीडी पानी देंगे और 150 एमजीडी पानी का जो स्कीम थी जिस सरकार ने पिछले वर्षों के अंतर्गत जो इस दिल्ली की भलाई के लिए।

माननीय अध्यक्षः शॉर्ट करिये, थोड़ा शॉर्ट।

श्री मोहन सिंह बिष्टः शॉर्ट क्या मैं वैसे ही बैठ जाऊंगा सर।

माननीय अध्यक्षः नहीं, नहीं वो सदस्यों की भावना है।

श्री मोहन सिंह बिष्टः नहीं चर्चा होनी चाहिए बॉस सुनिये ये हमारी सरकार पे आयेगा।

माननीय अध्यक्षः सदन बढ़ा लीजिए फिर एक दिन।

श्री मोहन सिंह बिष्टः खामियां इनकी थीं, खामियां उनकी थीं। सर हमने भी तो सुना है ना ये जो वास्तविक चीज है ये जनता के प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। अरे भई 150 एमजीडी पानी जिसके लिए करार हुआ। मुनक नहर की तरह एक नहर बनानी थी उस सरकार ने वो मुनक नहर की तरह वो नहर बनायी ही नहीं उनकी सिर्फ एक डिमांड थी कि उत्तर प्रदेश सरकार की जितने भी आपके दिल्ली के अंतर्गत नाले हैं उन नालों में ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया जाए। वो पानी हमारे खेत और खालियानों को दिया जाए तो

वहां के खेत और खलियान सूखे नहीं रहेंगे। दिल्ली के लोगों को 150 एमजीडी पानी मिलकर के दिल्ली की प्यास बुझाई जा सकती है। और अध्यक्ष महोदय मैं ही नहीं कह रहा हूँ ये पिछले दिनों के अंदर एक पेपर के अंदर इसमें एक इस प्रकार का आया था। उसमें साफतौर पे कहा गया योजना बनी, लेकिन आम पार्टी की सरकार द्वारा उस समस्याओं के समाधान को दूर रख दिया गया। अध्यक्ष महोदय आज आप देख रहे होंगे दिल्ली की हालत दिल्ली में यदि हम देखते हैं तो पानी से लोग किस प्रकार से त्राही, त्राही कर रहे हैं ये आप हम सब जानते हैं। एक ऐसी सरकार बैठी, करोड़ों रूपए का बजट सबमर्सिबल के नाम से, बोरिंग के नाम से पैसे की तो बर्बादी की गई जो स्कीम बननी थी उस स्कीम को लागू नहीं किया। अध्यक्ष महोदय ये ही नहीं आज यदि हम पानी की समस्याओं को देखें अध्यक्ष महोदय ये चीजें मैं धन्यवाद करता हूँ सूर्य प्रकाश खत्री का जो इस प्रकार की बात को लेकर के दिल्ली के लोगों को जो जगाने का काम किया। गलती पिछली सरकारों की, भुगतेंगे हम। तो इस प्रकार का अध्यक्ष महोदय ये ही नहीं जो भी बड़ी-बड़ी पाइप लाइन आ रही हैं वो बहुत लीकेज हैं। यदि उस लीकेज को ठीक कर दिया जाए तो दिल्ली का पानी जो बर्बाद हो रहा था उससे वो बच सकता है। अध्यक्ष महोदय मैं सीधा से अपनी बात को जल्दी खत्म कर दूंगा शायद आपको भी लग रहा होगा क्योंकि।

माननीय अध्यक्षः 6.00 बज गये हैं।

श्री मोहन सिंह बिष्टः वो टाइम भी हम भी देखते हैं सर हमने तो बहुत अब तब से लेकर टाइम देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। सर मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं ये दिल्ली एक ऐसी दिल्ली बन गई है। इसमें हमारे मंत्री जी ने जल मंत्री जी ने जिस प्रकार के प्रश्न के उत्तर में कहा जहां बीजेपी के एमएलए हैं उनके पानी को काट दिया उनमें कमी कर दी जाती, उस दिन प्रश्न के उत्तर में जब विपक्ष के लोग चिल्ला रहे थे। अध्यक्ष महोदय, मेरी विधानसभा जहां से मैं अब चुनाव लड़ा हूं जहां 30 एमजीडी पीने के पानी की आवश्यकता है लेकिन मिलता कितना है सिर्फ 5 एमजीडी। इसी तरह से दिल्ली के अन्य क्षेत्रों के अन्तर्गत भी इसी प्रकार की हो। अध्यक्ष महोदय पीने के पानी के बाद सीवर लाइन, आज आप देख रहे होंगे सीवर के जितने ट्रीटमेंट प्लांट हैं ये प्लांटों का पानी सीवर में पूरी तरह से जाम पड़े हैं और पानी सड़कों के ऊपर आ रहा है। सम्पूर्ण दिल्ली में गाद की सफाई ना होने के कारण चौड़े-चौड़े नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं। दिल्ली में नालों की समस्या ये बनी पड़ी है। अध्यक्ष महोदय, ये ही नहीं अनेक इस प्रकार के बहुत सी चीज़ों पर हम इस जो एक प्रस्ताव लेकर के आये थे उन पर हम चर्चा करना चाहते थे लेकिन समय की कमी के कारण निश्चित रूप से मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय आपने मुझे ये उठाने का मौका दिया।

माननीय अध्यक्षः बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मोहन सिंह बिष्टः मैं आपका आभार जताता हूं, लेकिन अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्षः माननीय।

श्री मोहन सिंह बिष्टः इस ऐसी चीज़ों पर हम सरकार के पार्ट हैं अंग हैं और सरकार कोई अकेले नहीं है हम इनकी नाक, आंख, कान ये सदस्य जो वो क्षेत्रों के अन्दर रहता है उनको बताने का प्रयास करता है जिससे सरकार की आने वाले दिनों में उनको कोई परेशानी ना हो, तो इस पर चर्चा में कभी इसको इतना शोर्ट मे ना लें, लाइट मे ना लें। यदि मैम्बर इतनी तैयारी करके आता हो तो आपने निश्चित रूप से आपने मुझे बोलने का समय दिया।

माननीय अध्यक्षः आज वाकई मोहन सिंह बिष्ट जी की तैयारी इतनी जबरदस्त है मैं देख रहा हूं सारे पेपर।

श्री मोहन सिंह बिष्टः बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः बहुत अच्छी तैयारी से आये हैं इससे पहले कि मैं अंतिम वक्ता माननीय सदस्य श्री राजकुमार भाटिया जी को बुलवाऊँ मैं सदन की सहमति से सदन का समय 15 मिनट इसको हम बढ़ाते हैं श्री राजकुमार भाटिया जी।

श्री राजकुमार भाटियाः धन्यवाद अध्यक्ष जी, दिल्ली में जल भराव और सीवर ब्लॉकेज को लेकर नियम-55 के तहत इस चर्चा में भाग लेने का आपने मुझे अवसर दिया। मान्यवर, हमने 24

तारीख को शपथ ली थी 28 तारीख को सदन में इस नियम के तहत हमने चर्चा के लिये शोर्ट नोटिस समय मांगा था और आज 2 तारीख है तिथि बदल गई है लेकिन साथ में स्थिति भी बदली है, एक महीने के अंदर-अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में हमारे साथी मंत्री श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी ने जो एक्शन प्लान बनाया है उससे तिथि बदलने के साथ-साथ स्थिति भी बदली है मैं इनको बधाई देता हूं। उस समय इस समस्या के प्रति मेरी जो दृष्टि थी और आज के दृष्टिकोण में काफी फर्क आया है। माननीय मंत्री महोदय जी की कार्य योजना से दिल्ली के लोगों में आस और विश्वास जागी है कि इस बारी दिल्ली प्यासी नहीं रहेगी और दिल्ली में जलभराव भी नहीं होगा मैं इनको बधाई देता हूं। मान्यवर अभी भी ड्रिंकिंग वॉटर लाइन्स में कई जगह खासकर छोटी लाइनों में जंग लगा हुआ है जिसके कारण गंदे पानी की सप्लाई हो रही है पिछली सरकार कहा करती थी कि हम बिजली, पानी फ्री में देंगे कुछ भी फ्री में नहीं था फ्री के नाम पर एक धोखा था और उस धोखे को जनता ने पहचाना है। मान्यवर मैं सदन को बताना चाहूंगा कि जिस घर में दो चार सौ पांच सौ रूपये का बिल जाया करता था और उसका बिल फ्री कर दिया गया उस घर में दो बोतल पानी रोज खरीदकर पीना पड़ता है 30 रूपये की एक बोतल दो बोतल पानी की कीमत 60 रूपये और 1 महीने में 18 सौ रूपये का पानी झुग्गी और छोटे मकानों में आज भी खरीदकर पीया जा रहा है क्योंकि नल से जल ये सरकार जो पिछली गई है वो

पीकर इसको खत्म करके गई है। आज कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं है कि नल में जल आ रहा हो और अगर कहीं नल में जल आ रहा है तो जितने फ्लोर बन गये हैं जितने छोटे मकानों के ऊपर मंजिलें बन गई हैं वहां बिना मोटर के पानी नहीं जाता और बिना जब मोटर चलती है तो 200 यूनिट फ्री बिजली का धोखा भी एकदम साथ के साथ खत्म हो जाता है। उन्होंने कुछ फ्री में नहीं दिया, दिया तो केवल रोग दिया, दिया तो केवल वायु प्रदुषण दिया और आज सीवर की समस्या कहीं भी कोई भी कॉन्सटिट्वेन्सी ऐसी नहीं है जिसमें सीवर की समस्या ना हो। छोटी-छोटी गलियों में बड़ी सड़कों पर बड़े नालों में ब्लॉकेज पूरी तरह से है मुझे तो लगता है किसी षड्यंत्र के तहत उन्होंने जहां-जहां भी पुलिया बनाई जहां-जहां भी नाले बनाये उसमें एक-एक स्लैब डालकर कहीं ना कहीं उसे रोक दिया जाये ताकि दिल्ली की जनता सदैव जल भराव से परेशान रहे। अनेक स्थानों पर लैवल की समस्या है। छोटे नाले और बड़े नाले के लैवल में एक असमानता है। मंत्री महोदय से मैं अनुरोध करूंगा कि अलग-अलग डिपार्टमेंट भले वो एमसीडी हो, पीडब्ल्यूडी हो, डूसिब हो जहां-जहां भी नाले को देखने वाली एजेंसी है इन नालों के लैवल को चैक कराया जाना चाहिये। छोटे नाले नीचे हैं और बड़े नाले ऊपर हैं पानी जाता नहीं है बैक मारता है घरों में पानी भर जाता है और दिल्ली में टोटल पूरी दिल्ली में चाहे वो पौश कॉलोनी है, चाहे झुग्गी कॉलोनी है, चाहे रिहेब्लिटेशन कॉलोनी है उनके आउट गोइंग लैवल के कारण वहां

जल भराव सामान्य सी समस्या हो चुकी है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय आपने जिस प्रकार से machinery announcement किया है आपने जिस हिसाब से पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं, मैंने तो पहले ही कहा है कि आपके दृष्टिकोण से मेरा भी दृष्टिकोण बदला है लेकिन एक इंग्लिश के कवि Frost की एक कविता की 'The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep' हमें एक लम्बी यात्रा तय करनी है। जब आपका और मुख्यमंत्री जी का दौरा मेरी विधानसभा में था, मान्यवर अध्यक्ष जी मैं बताना चाहूंगा कि एक pit बना हुआ था पीडब्ल्यूडी का जिसमें पानी गुजरता था कूड़ा जमा हुआ था तो मैंने एक बच्चे को कहा कि इसमें बांस मारकर देखिये कितना गहरा है वो बांस डालते-डालते बच्चा उसमें गिर गया मुझे लगता था कि वो डूब जायेगा लेकिन वो डूबा नहीं उसी की तह पर रह गया, वो उसका जो सिल्ट था इतना जमा हुआ था पिछले 10 सालों में कभी वो सिल्ट साफ नहीं हुआ था और वो बच्चा सुरक्षित उस पर जैसे कृष्ण कन्हैया यमुना में घुम रहे थे वैसे घुमता हुआ नज़र आया। ये पिछली सरकार की नाकामी है उसके बाद माननीय मंत्री महोदय जी के निर्देश पर जब पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने नालों की सफाई करनी शुरू करी तो 18-18 फुट गाद एक-एक नाले से गुजरी और जब मैंने अफसरान से पूछा कि पिछली बारी इसकी सफाई कब हुई थी तो उन्होंने दबी ज़बान में बताया कि पिछले 10 सालों में मुझे विधायक ने एक बारी भी नहीं कहा कि इस नाले

की आप सफाई कर दें। कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ होगा कितनी बड़ी financial anomalies हुई होंगी, कैसे-कैसे दिल्ली को ठगा गया होगा और ये एक नाले की नहीं अनेक नालों की समस्या है और आज दिल्ली में जब जेसीबी चलती है माननीय मंत्री महोदय के निर्देश पर जो सुपरसकर जाते हैं या अन्य मशीनें जाती हैं तो जनता हमारी तरफ हैरानी से देखती है कि ये डायनासौर आप कहां से लाये हैं ये मशीने पिछले 10 साल से हमने कभी नहीं देखी थीं। माननीय मंत्री महोदय इस तरफ जरूर ध्यान देते रहिये क्योंकि दिल्ली आपकी तरफ आस और विश्वास से देख रही है दिल्ली ने हमें वोट किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के कारण तो किया ही है लेकिन उसके साथ-साथ दिल्ली चाहती थी कि सीवर की समस्या से और पानी की समस्या से दिल्ली मुक्त हो जाये। दिल्ली में ये जो भ्रष्टाचार की जो बर्फ जमी हुई थी इसको पिघालने का काम हमारी सरकार को दिया है और निश्चित रूप से हम सब मिलकर इस पर काम करेंगे। इस विषय के एक-एक बिंदु पर जितनी चर्चा हुई है ये चर्चा का समय बिल्कुल कम है क्योंकि अन्य सदस्यों को भी मौका मिलना चाहिये, हर एक का दर्द एक सा है, हर एक के यहां अलग-अलग कोण है अलग-अलग कोने हैं जिसमें जल भराव होता है। बड़े नालों में Flood and Irrigation Department विभाग के जो बड़े नाले हैं उनकी समस्या भी बिल्कुल इसी प्रकार से है कहीं से पानी का बहाव आपको नज़र नहीं आता और दिल्ली में जल भराव तभी रूकेगा

जब नालों में पानी का बहाव आना नज़र आ जायेगा। जब सिल्ट के स्थान पर पानी नज़र आयेगा तभी दिल्ली जल भराव से मुक्त होगी। मैं आपसे इसी विश्वास के साथ इस चर्चा को अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आने वाले समय में भी एक साल नहीं दो साल नहीं ये समस्या को खत्म होने में कई साल लगेंगे और हमें निरंतर इस पर काम करना होगा, वन प्वांइट एजेंडा बनाकर दिल्ली को साफ-सुथरा रखना होगा मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

माननीय अध्यक्षः अब माननीय मंत्री श्री प्रवेश साहिब सिंह जी चर्चा का उत्तर देंगे।

माननीय लोक निर्माण मंत्री (श्री प्रवेश साहिब सिंह): आदरणीय अध्यक्ष जी, जब पहली सरकार के अपना बनने के बाद में जब पहला सत्र हुआ तो उसी में जब आपने देखा कि सारे सदस्यों की सबसे ज्यादा चिंता पानी और सीवर को लेकर है तो आपने शोर्ट डिस्कशन के लिये हां किया और मैं माननीय हमारे सदस्य सूर्य प्रकाश खत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इसको लगाया और बहुत सारे सदस्यों ने इसमें भाग लिया। मैं समझता हूं कि हमारे सदस्यों की अगर, मैं समझता हूं अगर पानी और सीवर की समस्या अगर इसका समाधान निकल जाता है तो हमारे विधानसभाओं की आधी से ज्यादा समस्या का समाधान निकल जायेगा। हमने ये देखा कि पिछले की सरकारों में क्योंकि मैं ज्यादा सरकारों के बारे में जो पीछे की सरकार रही उसकी मैं ज्यादा बुराई इसलिये नहीं करूंगा क्योंकि मैं हमेशा विश्वास करता हूं कि हमें

आगे की तरफ में देखना चाहिये आगे हम क्या कर रहे हैं। पीछे की सरकार पैसा भी खर्च कर रही थी वो पैसा खर्च कहां हो रहा था ये नहीं मालूम, इंजीनियर कहते थे कि लाइन चेंज हो रही है, पीछे जब मैं सारे विधायक सदस्यों से मिल रहा था, एक शायद देवली के हमारे सदस्य जब मैं उनके साथ में बैठा हुआ था अधिकारियों के साथ में और वहां पर अधिकारियों ने बताया कि चार साल पहले 7 करोड़ रूपये की एक वहां पर पाइप लाइन डाली गई और जो आज तक भी वहां पर commission नहीं हुई तो 7 करोड़ रूपये की पाइप लाइन डाली जब उसमें पानी छोड़ा गया तो देखा कि बहुत सारी जगह पर लिकेज उसमें निकलकर आया तो आज तक वो चार साल में सात करोड़ रूपया खर्च हुआ वहां पर लाइन डाली गई, संगम विहार में मगर वहां पर पानी आज तक उसका commission नहीं हुआ और जब मैंने अधिकारियों से पूछा कि अब उसको शुरू करने में कितना खर्चा आयेगा तो बोले 5 करोड़ रूपये और खर्चा आयेगा। मैंने अधिकारियों को बोला कि जो भी उस समय का बिल्डर रहा होगा उसकी पेमेंट अगर कोई और भी काम चल रहे हैं तो उसको रूकवाईये तो हम ये सारे काम तो कर रहे हैं मगर मैं साथ में मैं हमारे अधिक्तर सदस्यों के साथ में अभी तक अधिकारियों के साथ में बैठा हूं मैं एक बात के लिये बधाई देना चाहता हूं अध्यक्ष जी कि हमारे सदस्य बहुत सारे पहली बार के विधायक हैं मगर केवल 15 दिन में ही सारे चीफ इंजीनियर बन चुके हैं क्योंकि जब वो मेरे पास में आते हैं

हमारे अधिकारियों को इतना नहीं पता होता जितना सदस्यों को पता होता है। कौन से डाया की लाइन डालनी है, कौन से डाया की पाइप डालनी है कितनी चौड़ी डालनी है कहां पर डिफेक्ट है, कहां पर लीकेज है इसको एक-एक क्षेत्र के एक-एक गली की जिम्मेदारी सारी नॉलेज हो चुकी है तो वो अधिकारी भी सोचते हैं कि इतना कैसे 15 दिन में मालूम पड़ा। 15 दिन में सारे सदस्यों को इसलिए मालूम पड़ा कि ये रोज सुबह दो-दो, तीन-तीन घंटा जनता से जूझते हैं, जनता के साथ में बैठते हैं, गलियों का दौरा कर रहे हैं, गलियों में उतर रहे हैं और जब ये गलियों में जा रहे हैं, मौके पर जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि इनके अंदर में काम करने की नीयत है ये काम करना चाहते हैं केवल अपना होर्डिंग प्रचार नहीं, ये काम को करना चाहते हैं इसलिए मैं ये समझता हूं कि समस्या पूरी दिल्ली की है और मैं ये भी सोचता हूं कि भारत की राजधानी है, सारे बड़े-बड़े लोग यहीं रहते हैं, यहां पर अंबेसी भी है, राष्ट्रपति भवन भी है, प्रधानमंत्री भवन भी है उसके बाद भी इक्कसवीं सदी में हम आज यहां पर पानी बिजली केवल पानी और सीवर की चिन्ता कर रहे हैं कि पानी और सीवर और जब मैंने कहा आधी से ज्यादा समस्याएं खत्म हो जाएंगी तो सारे सदस्य इतने खुश हुए कि ये काम हो गया तो 80 परसेंट समस्या आपकी खत्म हो जाएंगी। तो ये बहुत ही कमाल की बात है अध्यक्ष जी मगर हमारी सरकार के पास में हमारी मुख्यमंत्री साहिबा ने कहा ये वाले बजट में कहा की हमारी सरकार के पास नीयत भी है, हमारी

सरकार के पास में पैसा भी है, हमारी सरकार के पास में मोदी जी जैसा नेतृत्व भी है, हमारी सरकार के पास में डबल इंजन की सरकार भी है। ये इतने सारे अधिकारी हमें इन्हीं से काम लेना है इन्हीं के साथ ही चलना है। तो अभी अगर मैं बात करूं पानी की तो पानी में हमने देखा की बहुत सारी दिल्ली में लाइनें हैं जो 40-50 साल पुरानी डली हुई हैं। बहुत सारी हैं जो 70-80 साल भी पुरानी डली हुई हैं वो सारी लाइनों को चेंज करना है मगर इसी के साथ मैं बहुत ही हैरानी वाली बात मैं आपको बताता हूं जो मुझे अधिकारियों ने जलबोर्ड ने कहा की पीछे की सरकार में पीछे के 2 साल अगर मैं उठाऊं क्योंकि उससे पहले तो वो बोलते कोविड आ गया तो हम कोई काम नहीं कर पाए मैं पिछले के 2 साल ही उठाकर बोलूं तो 2 साल में उन्होंने कहा की पीछे की सरकार ने एक भी पाइप लाइन चाहे पानी की हो चाहे सीवर की हो एक भी पाइप लाइन चेंज करने का प्रोजेक्ट में एक करोड़ रुपये से ज्यादा का काम नहीं किया यानी एक करोड़ रुपये से ज्यादा का कोई भी प्रोजेक्ट का काम नहीं किया। इसका मतलब केवल फायर फाइटिंग कहीं पर लीकेज की शिकायत हो गई उसको ठीक कर दिया वहां पर मगर इनकी कोई एक्शन प्लान नहीं था कोई मास्टर प्लान नहीं था। हमारी सरकार आज जो फायर फाइटिंग होगा वो भी करेगी और एक्शन प्लान भी बनाएगी आगे 50. साल 100 साल हमारी दिल्ली की आबादी जो आज कोई जो है ढ़ाई करोड़ है कल को वो तीन करोड़ होती है साढ़े तीन करोड़ होती

है तो पूरा एक कंप्रेहेंसिव मास्टर प्लान बनाकर पानी और सीवेज का उसके ऊपर में काम करना शुरु करेगी। पानी बहुत गंदा आता है, पानी की लाइनें मिक्स हो जाती हैं क्योंकि पानी की सारी लाइनें पुरानी हो गई हैं उनको चेंज करने की आवश्यकता है। दूसरा मैंने अध्यक्ष जी देखा की वॉटर मैनेजमेंट ठीक नहीं है। पहले जैसे मैंने कहा था कि जो हमारे विपक्ष के लोग थे सदस्य थे वो भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य थे उनके क्षेत्र की जो पानी होता था वो अपने क्षेत्र में ले जाते थे तो मैंने देखा की कोई विधानसभा जिसमें दो लाख की जनसंख्या है वहां पर जो है पानी की डिमांड है 12 एमजीडी मगर वहां पर हम केवल 9 एमजीडी सप्लाई करते हैं। फिर मैंने देखा की कोई विधानसभा जहां पर ढ़ाई लाख की जनसंख्या है जहां पर 15 एमजीडी की डिमांड है वहां पर भी 9 एमजीडी सप्लाई होता है तो पूरी दिल्ली में चाहे वो पॉश कालोनी हो, चाहे गांव हो, चाहे कोई पिछड़ा हुआ इलाका है, चाहे कोई सब जगह में वॉटर सप्लाई जनसंख्या को देखकर उसके समान रूप से बांटा जाएगा ऐसा मैं आपको कहना चाहता हूं।

मैं आज सुबह-सुबह अध्यक्ष जी दिल्ली जलबोर्ड के दफ्तर गया जिसको हम वरुणालय के नाम से जानते हैं जब मैं वहां पर गया तो मैंने देखा की अधिकारी आ रहे थे जा रहे थे कोई वहां पर अटेंडेंस का कोई सिस्टम नहीं था बायोमीट्रिक सिस्टम नहीं था तो मैंने अधिकारियों को बोला की 15 दिन में यहां पर बायोमीट्रिक सिस्टम लगे और दिल्ली जलबोर्ड के जितने भी आपकी विधानसभा

में दफ्तर हैं सभी जगह पर अटेंडेंस होगा कौन इंजीनियर आ रहा है, कौन जा रहा है कैसे आ रहा है ये सब हम उसको सुनिश्चित करेंगे। उसी के साथ में हमारा ये भी दावा है कि हम दिल्ली को टैंकर फ्री करेंगे मगर जब तक टैंकर फ्री नहीं होता है तब तक हमको जो टैंकर से हम जो जल आपूर्ति कर रहे हैं उसको भी हमको करना पड़ेगा। पहले टैंकर में जीपीएस सिस्टम ही नहीं था। कोई टैंकर 8 ट्रिप लगा रहा है 9 ट्रिप लगा रहा है उसको पेमेंट मिल रही है मगर वो लगा रहा है नहीं लगा रहा है ये मालूम नहीं है। वो आता था फिलिंग स्टेशन में अपना सारा टैंक भरता था उसके बाद में कहां जाता था, कौन से रेस्टोरेंट में बेच देता था, कौन से होटल में बेच देता था पानी को न पब्लिक को मिल रहा था और अपनी जेब भरने का और अपने नेताओं की जेब भरने का काम कर रहा था हमने उसमें जीपीएस सिस्टम भी लगाने का काम किया। हमारी मुख्यमंत्री जी ने कहा मुझे कमांड सेंटर चाहिए जहां पर मैं हर चीज को देख सकूं तो आज मैं कमांड सेंटर को देखने गया जो हमने अभी वरुणालय में बना दिया है एक-दो दिन में मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगी जिसमें एक-एक एक्टिविटी को पानी कहां जा रहा है, कितना जा रहा है कहां पहुंचा नहीं पहुंचा, उसको हम उसमें देख पाएंगे तो दिल्ली जलबोर्ड की सारी एक्टिविटी मेरे सारे विभाग जो पीडब्लूडी है आईएंडएफसी है हम सारे विभाग को आईटी डैसबोर्ड के साथ में जोड़ेंगे। आज कितना सिल्ट उठा, कितना गया, कितना डंपयार्ड में गया, कितना टैंकर चला, कितनी

डिक्की मशीन चली, कितनी बुलैरो मशीन चली ये सारे काम हम अपना आईटी डैसबोर्ड में देखेंगे और एक-एक चीज को मॉनीटर करेंगे, उसकी क्वालिटी को मॉनीटर करेंगे। अध्यक्ष जी, दिल्ली में कोई 1250 एमजीडी की डिमांड है मगर हमको केवल 990 एमजीडी पानी आज की डेट में मिलता है उसमें से 864 एमजीडी पानी हमारा जो हम अपना दूसरे राज्यों से लेते हैं और 126 एमजीडी हम जो ग्राउंड वाटर से लेते हैं। तो ये आने वाली गर्मी को देखते हुए अभी दिल्ली में जहां-जहां पर भी पानी का लेवल ऊंचा हो गया है, जहां पर क्वालिटी अच्छी है, मीठा पानी है हमने 239 नये ट्यूबवैल लगाने के लिए बोला है जो कि अगले 3 महीने में 239 नये ट्यूबवैल लग जाएंगे उसमें से 96 ट्यूबवैल मई में चालू हो जाएंगे, 88 ट्यूबवैल जून में चालू हो जाएंगे और 55 जुलाई में चालू हो जाएंगे। उसके अलावा भी जो भी विधायक की हमारे पास में कहीं से डिमांड आती है उसको और ट्यूबवैल चाहिए जहां पानी की क्वालिटी अच्छी होगी, वहां पर और भी आपको ट्यूबवैल देंगे मगर दिल्ली की जनता को पूरा पानी देंगे। इसी के साथ ही अध्यक्ष जी हमारे पास में जो अपना टैंकर हैं गर्मियों में उनकी संख्या भी बढ़ जाती है मगर 160 टैंकर जो दिल्ली जलबोर्ड की प्रापर्टी हैं उसको भी चालू कर रहे हैं उसके लिए भी हमने क्रेन का टैंडर कर दिया है 160 टैंकर और एडीशनल हम उसको दे देंगे तो टोटल अभी तक 901 टैंकर चल रहे हैं उसको बढ़ाकर 1327 करेंगे। मगर ये सारा टैंकर केवल टेम्परेरी व्यवस्था है क्योंकि

अभी-अभी हमारी सरकार बनी है धीरे-धीरे टैंकर को और मैं ये भी कहना चाहता हूं आज की हमारे पास में पानी पर्याप्त है। हमें कई राज्यों से बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है हमको केवल अपनी कमियों को रोकना है, लीकेज को रोकना है जहां पर कहीं चोरी हो रही है लीकेज आ रही है मतलब पहले हम अपना सिस्टम ठीक करें फिर उसके बाद में दूसरे राज्यों के पास जाएं अभी हम अपने सिस्टम को ठीक करने में लगे हैं। इसके साथ ही जो हमारे पुराने हमारे जो कैनाल हैं चाहे वो डीएसबी हैं चाहे वो सीएलसी हैं इस बार के बजट में उनको भी लाइन करने का हमें पैसा मिला है और इसको लाइन करने से 30 प्रतिशत तक का हमारा पानी का वेस्टेज हमारा बच जाएगा उससे हमारा पानी और बढ़ जाएगा। इसी के साथ ही अगर मैं सीवर की बात करूं तो माननीय सदस्यों की डिमांड आ रही थी की सुपर सकर मशीन चाहिए तो 32 हमारी नई सुपर सकर मशीन आ गई हैं 30 का और टैंडर कर रहे हैं। हर विधानसभा में 1 सुपर सकर मशीन हो और अगले 4 महीने में मानसून से पहले-पहले सारे बड़े नाले सारे ट्रंक सीवर सबको डी-सिल्ट करने का काम हम लोग करेंगे। हमारे पास में छोटी मशीनें भी बहुत हैं मगर जब मैं हमारे सदस्यों के साथ में राउंड पर गया तो देखा कि सीवेज की लाइनें भरी पड़ी हैं 10-10 साल से डी-सिल्ट नहीं हुआ था। सारी मशीनों की पेमेंट दिल्ली जलबोर्ड से हो रही है, पैसा जा रहा है मशीन है मगर उनकी डी-सिल्टिंग नहीं हो रही है तो उसके लिए भी हमने कड़ी

चेतावनी के साथ में उनके ऊपर में भी जीपीएस सिस्टम लगाने के लिए बोला है। सारे टैंकर्स में हम उसमें सेंसर भी लगा रहे हैं कि अगर वो किसी पाइंट में जाता है तो पानी का लेवल उसका कितना कम हुआ ये भी पता लगना चाहिए, जीपीएस से तो पता लगेगा पाइंट पर पहुंचा या नहीं पहुंचा मगर उसमें सेंसर भी लगेगा ताकि उसमें पता लगेगा पानी का लेवल कितना कम हो रहा है। तो ये सारे काम कर रहे हैं। इसी के साथ में बहुत सारे सदस्यों ने कहा कि जेई नहीं है, हमारे पास स्टाफ नहीं है तो 180 नये जेई का हमने अभी ऐड भी कर दिया है और एक महीने में 180 हमारे नये जेई भी हमें मिल जाएंगे तो हमारे कुछ तो मेनटेनेंस में लगेंगे, कुछ हमारे प्रोजेक्ट में लगेंगे तो ये कमी भी हमारी पूरी हो जाएगी। फिर हमारे सदस्यों की डिमांड थी कि हमारी लेबर भी कम है खाली हर विधानसभा में 10-10 लेबर दी गई है उसको भी हमने 20 कर दिया है, उसका भी टैंडर हो गया है तो कहीं आपको 20 चाहिए, कहीं आपको 25 भी चाहिए, कहीं आपकी विधानसभा बड़ी है तो उसको ज्यादा भी देंगे मगर ये हमारी सरकार का ध्येय है, लक्ष्य है, संकल्प है कि नीति हमारी सही है, हमारी दिशा सही है, ईमानदारी से काम करेंगे इस गर्मी में सारे लोगों को दिल्ली की जनता को पर्याप्त पानी मिले, मानसून में कहीं पर भी जलभराव न हो, सारे नाले-नालियों की अच्छे से डी-सिल्टिंग हो जाए ये हमारी सरकार का संकल्प है, इसको हम करेंगे। मैं सारे सदस्यों का, आपका जो हमको सहयोग मिलता जा रहा है, आपके सुझाव हमको मिलते जा रहे हैं उसका मैं धन्यवाद करता हूं ऐसे

ही आपके सुझाव मिलते रहें, आप भी अपने क्षेत्र में निगरानी करते रहें। चोरियां हमको रोकनी हैं, हमको जो पुराने सिस्टम में सारी चोरियां पैदा होती जा रही थीं उसको खत्म करना है नये सिस्टम को अच्छा करना है सुदृढ़ करना है बिलकुल जो है करप्शन फ्री करना है कि कोई भी एक रुपये का भी करप्शन नहीं हो सके ऐसा करना है। तो मैं सभी सदस्यों का इस चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

माननीय अध्यक्षः सदन को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित करने से पहले मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित करना चाहूंगा कि सदन के सत्रावसान के लिए मैं माननीय उप-राज्यपाल महोदय के पास प्रस्ताव भेज रहा हूं। आठवीं विधानसभा के द्वितीय सत्र के संचालन में सहयोग देने के लिए मैं सदन की नेता एवं माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता, सभी मंत्रीगण, माननीय नेता, प्रतिपक्ष श्रीमती आतिशी तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। इसके अलावा विधानसभा सचिवालय तथा सरकार के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ-साथ विभिन्न विभागों और सुरक्षा एजेंसियों तथा मीडिया का भी धन्यवाद करता हूं। अब मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे राष्ट्रगान के लिए खड़े हों।

(राष्ट्रगान)

माननीय अध्यक्षः अब सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की गई।)

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्स, 2965 /41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।